हरियाणा विधान सभा

वीरवार, 17 मार्च, 2016 (द्वितीय बैठक)

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में अपराह्न 2.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री कंवर पाल) ने अध्यक्षता की।

इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के निलम्बित सदस्यों पर निर्णय रद्द करने बारे

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, जैसा कि एक सदस्य श्री जय प्रकाश जी द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि हाऊस की इस सीटिंग में अति संवेदनशील एस.वाई.एल. कैनाल के विषय पर जो चर्चा होनी प्रस्तावित है तो इस विषय की गम्भीरता को देखते हुए उन्होंने यह सुझाव दिया है कि इस मामले पर चर्चा के दौरान कांग्रेस पार्टी के सदस्य भी हाऊस में उपस्थित होने चाहिएं। इस सुझाव का सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अनुमोदन किया है। इसलिए अगर सदन की सहमति हो तो कांग्रेस पार्टी के 14 माननीय सदस्य, जिनका दिनांक 14.03.2016 को महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान व्यवधान डालने और महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रतियां फाड़ने के कारण महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान तक सदन से निलम्बन किया गया था, उनमें से 11 सदस्यों का निलम्बन रद्द करके इनको सदन में वापस बुला लिया जाये। इनके नाम इस प्रकार हैं:- श्री आनंद सिंह दांगी, श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, श्रीमती गीता भुक्कल, श्री जय तीर्थ, श्री करण सिंह दलाल, श्रीमती किरण चौधरी, श्री ललित नागर, श्री रघुवीर सिंह कादियान, श्रीमती शंकुतला खटक, श्री श्रीकृष्ण और श्री उदय भान। बाकी तीन सदस्य श्री कुलदीप शर्मा, श्री जगबीर सिंह मलिक और श्री जयवीर सिंह के बारे में बाद में विचार किया जायेगा।

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, मेरा आपसे और माननीय सदन के नेता से अनुरोध है कि जिन तीन सदस्यों का निलम्बन रद्द करने के बारे में आपके द्वारा बाद में विचार करने के बारे में कहा गया है उनको भी इन 11 सदस्यों के साथ ही सदन में बुला लिया जाये क्योंकि वे भी काफी सज़ा भुगत चुके हैं। उनको यहां बुलाया जाये ताकि उनको यहां पर इस बात का अहसास हो सके कि उन्होंने गलतियां की हैं लेकिन उसके बावजूद भी उनको माफ किया गया है। मैं एक बार पुन: अनुरोध करना चाहता हूं कि उनको भी सदन में वापस बुला लिया जाये।

डॉ. पवन सैनी : स्पीकर सर, जो आपने फैसला किया है हम भी उससे पूरी तरह से सहमत हैं।

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, मैं डॉ. पवन सैनी को यह कहना चाहता हूं कि इन्होंने तो यहां पर कोई कष्ट नहीं झेला है जबकि हमने तो पिछले दस साल कांग्रेस सरकार में यहां पर बड़े दुख झेले हैं। हम इसीलिए यह कहते हैं कि बाहर बैठना बहुत मुश्किल काम है। अगर डॉ. साहब को इस बात का अहसास दिलवाना है तो इनको एक दिन बाहर बैठकर देखना चाहिए।

शिक्षा मंत्री (श्री रामबिलास शर्मा) : स्पीकर सर, जैसे आज सुबह विपक्ष के नेता श्री अभय सिंह चौटाला जी ने भी जिक्र किया और उसके बाद इंडीपैंडैंट विधायक श्री जय प्रकाश जी ने भी कहा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इन दोनों की बात को और सारे सदन की भावना को देखते हुए इस आशय का प्रस्ताव सदन में रखा। जहां तक तीन विधायकों के निलम्बन वापस लेने का सवाल है उनके खिलाफ महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रतियां फाड़ने का मामला था। इनके लिए जो आपने फैसला लम्बित रखा है, ऐसा करके आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया है।

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, जब कांग्रेस के 11 विधायक सदन में आ जायेंगे तो फिर उनके साथ भी इस विषय में बात कर ली जायेगी।

श्री रामबिलास शर्मा : स्पीकर सर, आपकी यह बात पूरी तरह से सही है कि जब सदन में कांग्रेस विधायक दल की नेता आ जायेंगी और उन के दूसरे साथी भी सदन में आ जायेंगे तो फिर उनके साथ इस बारे में बात कर ली जायेगी।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : स्पीकर सर, हमें तो इस बात की शंका है कि अगर आप 14 की बजाये सिर्फ 11 को ही बुलायेंगे तो वे 11 विधायक भी नहीं आयेंगे। इसलिए हमारा यह सुझाव है कि आप सभी 14 के 14 निलम्बित सदस्यों को हाऊस के अंदर बुला लें।

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, इस मामले में मेरा एक और सुझाव है कि आपने जिन तीन विधायकों की सस्पैंशन की है उनकी सस्पैंशन को रद्द करके उनके मामले को प्रिविलेज कमेटी में भेज दें और वहां पर उनसे सारी की सारी बातों का जवाब ले लिया जाये।

श्री ज्ञान चंद गुप्ता : स्पीकर सर, मेरा भी इस बारे में एक सुझाव है कि वे तीन सदस्य यहां पर आकर खेद व्यक्त कर दें तभी उनके निलम्बन को रद्द करने के बारे में विचार किया जाये।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, आपने जो फैसला लिया था वह एक बहुत बड़े गम्भीर मामले को ध्यान में रख कर लिया था और सारे सदन ने आपके फैसले पर मुहर लगाई लेकिन अगर कोई गलती करता है तो उस गलती को सुधारने की दिशा में पहला कदम होता है, उस गलती को मानना तथा उस गलती का प्रायश्चित करना दूसरा कदम होता है। सजा और ये सब बातें तो बाद में होती हैं। अभी तक जिन माननीय सदस्यों को आपने बाहर निकाला था उन्होंने न तो अपनी गलती को माना है और न ही प्रायश्चित किया है। यह ठीक है कि उनको जितने समय के लिए बाहर किया था वह भी कम हो रहा है। दूसरी बात यह है कि साथी विधायक श्री जयप्रकाश और नेता प्रतिपक्ष तथा हम सबकी भी भावना साथी सदस्यों के प्रति है लेकिन क्या एक बार भी उन्हें अपनी गलती का बोध या हाउस को अपनी गलती के लिए प्रायश्चित का बोध करवाया है? इसके बावजूद भी आपने और सदन के नेता ने नेता प्रतिपक्ष के सुझाव पर फिराखदिली दिखाते हुये उनके सुझाव को स्वीकार किया है। हम इस फैसले में अब भी आपके साथ हैं लेकिन सदन की मर्यादा और गरिमा को बहुत बड़ी चुनौती दी गई है इसलिए वे कम से कम सदन को इतना तो बोध करवाएं कि उनसे गलती हुई थी और आगे से वे इस बात का ध्यान

रखेंगे। अगर उनको बिना अहसास दिलाये निलम्बन रद्द करके सदन में बुला लिया जायेगा तो उनको इस बात का भी अहसास नहीं होगा कि आपने और सदन के नेता ने उनके प्रति फिराखदिली दिखाई है। जिस प्रकार से उन्होंने पहले महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रतियाँ फाड़ी थी वे फिर उसी प्रकार की दृष्टता दिखायेंगे। आपके ऊपर सदन को चलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उसको देखते हुये हमें विश्वास है कि आप सही फैसला लेंगे। (विघ्न)

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्रीमती कविता जैन) : अध्यक्ष महोदय, आपका निर्णय स्वागत योग्य है और मैं भी उसका समर्थन करती हूँ। मैं जब पहली बार चुनाव जीत कर विधान सभा पहुंची तो विपक्ष की सीटों पर अकेली बैठती थी क्योंकि तत्कालीन अध्यक्ष विपक्ष को नेम करके बाहर निकाल देते थे और मैं पहली बार चुनाव जीत कर आई थी इसलिए मुझे नेम नहीं किया जाता था। मुझे पता है कि सदन में अकेले बैठना कितना मुश्किल काम है। मैं यहाँ सदन में अध्यक्ष से यही मांग करती रहती थी कि विपक्ष के अन्य साथियों को भी बुला लिया जाये क्योंकि विपक्ष के बिना हाउस नीरस होता है। तब मुझसे यही कहा जाता था कि आप जाईये और उनसे माफी लिखवा कर ले आईये, हम आपकी बात मान लेंगे उस समय के आचरण में और आज के आचरण में बिल्कुल भिन्नता है क्योंकि जो साथी आज इधर हैं, वे तब उधर होते थे। उस समय कांग्रेस पार्टी की कारगुजारियों के खिलाफ आवाज उठाते ही सबको बाहर निकाल दिया जाता था। आज जो कांग्रेस के सदस्य बाहर हैं उन्होंने इस सदन की अवमानना की है तथा सबसे बड़ी संस्था का अपमान किया है । अगर वे माफी मांगते हैं तो हमें कोई ऐतराज नहीं है उनको वापिस बुला लिया जाये। साथ ही जो साथी उनको बुलाना चाहते हैं यदि वे उनसे माफीनामा लिखवा कर ले आयें तो हमें उनका निलम्बन रद्द करने में कोई आपत्ति नहीं है।

श्री जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने जो बात कही है वह सही है क्योंकि अगर 14 में से 3 साथी बाहर रहें और 11 सदन के अन्दर रहें तो अच्छा नहीं लगता। मैं भी ज्यादातर इन्हीं हालातों में रहा हूँ। पहले ऐसा होता था कि जो साथी सदन के अन्दर रह जाते थे वे बीच-बचाव करके रास्ता निकाल लेते थे। अध्यक्ष महोदय, आप भी इन हालातों से गुजरे होंगे। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। श्री प्रेम सिंह चंदु माजरा जी से लोकसभा में कुछ अपशब्द निकल गये और हमने उनको सपोर्ट कर दिया। श्री चन्द्रशेखर जी उस समय लोकसभा के सदस्य थे उन्होंने खड़े हो कर सदन में कहा कि इस नौजवान से यदि कोई गलती हुई है तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं उन कांग्रेस के 14 के 14 साथियों की तरफ से क्षमा मांगता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि उनका निलम्बन रद्द करके उनको वापस बुला लिया जाये।

श्री अध्यक्ष : वे तो नौजवान नहीं हैं। वे तो सीनियर सदस्य हैं।

श्री जय प्रकाश: अध्यक्ष महोदय, आज समय दूसरा है और एस.वाई.एल. कैनाल जैसे गम्भीर मुद्दे पर चर्चा होने वाली है। पहले वाला समय होता तो मैं भी किसी के लिए क्षमा नहीं मांगता।

पंजाब विधान सभा के कांग्रेस सदस्यों तथा एस.वाई.एल. नहर पर पंजाब सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विरूद्ध निंदा प्रस्ताव

शिक्षा मंत्री (श्री रामबिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष और श्री जयप्रकाश जी की जो बात है कुल मिलाकर उसकी भावना एक ही है। आप कांग्रेस पार्टी की लीडर से और बाकी के सदस्यों से बात कर लें क्योंकि हम यहां एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। हम अपनी भूमिका निभा रहे हैं और आप अपनी भूमिका निभा रहे हैं। हम सब जो प्रतिनिधि जहां से चुनकर आए हैं वह उनकी भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हैं तो इसमें कोई बड़ा अन्तर नहीं है जैसा कि नेता प्रतिपक्ष ने और श्री जयप्रकाश जी ने कहा, उनकी बात से यह सारा सदन सहमत है। उन तीन नेताओं को सदन में बुलाने का विचार आप उनके नेताओं से कर लें। स्पीकर सर, मैं एक अहम मुद्दे का प्रस्ताव सदन में रखना चाहता हूं। अभी पंजाब के कांग्रेस पार्टी के विधायक हमारी विधान सभा हाल के दरवाजे तक आकर इण्डियन नैशनल लोकदल पार्टी के सदस्यों के खिलाफ जिन्दाबाद-मुर्दाबाद के नारे लगाकर गए हैं ऐसा करके उन्होंने इस सदन की अवमानना की है इसलिए मैं इस सदन में प्रस्ताव रखता हूं कि पंजाब के कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने जो यहां हमारे सदन के मुख्य दरवाजे पर आकर इण्डियन नैशनल लोकदल पार्टी के सदस्यों के खिलाफ नारे बाजी की है जो इस सदन की अवमानना है इसलिए मैं उनके लिए सदन में एक निन्दा प्रस्ताव रखना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : ठीक है जी, अगर हाऊस की सहमति है तो यह निंदा प्रस्ताव पास किया जाता है।

आवाजें: ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष: यह निंदा प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया जाता है।

(निंदा प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया।)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके सामने एस.वाई.एल. कैनाल को लेकर दिल्ली को पानी न देने के बारे में एक रैज्योलूशन रखा था और उस समय आपने कहा था कि मैं इस पर विचार करूंगा । इसके साथ ही आप पंजाब के कांग्रेस पार्टी के सदस्यों के खिलाफ निन्दा प्रस्ताव को पास करके पंजाब के मुख्यमंत्री के पास भिजवाएं कि वे कांग्रेस पार्टी के इन सदस्यों के खिलाफ कार्यवाही करें।

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आप ये निन्दा प्रस्ताव पंजाब के मुख्यमंत्री जी के पास भेजें और उनको कहें कि उन सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करें और उनके खिलाफ एफ.आई.आर. भी दर्ज करें। स्पीकर सर, ये प्रजातंत्र है इसमें हम एक संविधान के तहत सब लोग अपनी-अपनी जिम्मेदारी का वहन कर रहे हैं। वर्ष 2004 में पंजाब विधान सभा द्वारा एक बिल पास किया गया था जिसके माध्यम से नदी जल से जुड़े सभी समझौतों को निरस्त करने का काम किया गया था। उसी परिपाटी में आज एक बार फिर से पंजाब विधान सभा द्वारा

एस.वाई.एल. नहर के मुद्दे पर एक असंवैधानिक तथा अनैतिक प्रस्ताव पास करके हरियाणा के हितों पर कुठाराघात करने का काम किया गया है। एस.वाई.एल. नहर को हरियाणा की लाईफ लाईन कहा जाता है। इस नहर के निर्माण पर हजारों करोड़ रूपया खर्च भी हो चुका है लेकिन बावजूद इसके पंजाब सरकार की सरपरस्ती में इस तरह का बिल पास करना तथा कांग्रेस पार्टी के विधायक श्री चरण जीत चन्नी एवं अन्य कांग्रेस विधायकों द्वारा हरियाणा विधान सभा के सदन के मुख्य दरवाजे के बाहर नारे लगाना बहुत ही दुर्भायपूर्ण है। अध्यक्ष महोदय, एस.वाई.एल नहर के मुद्दे पर हरियाणा सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अभी सुप्रीम कोर्ट में इसकी तारीख भी लगी थी । माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सख्त संज्ञान भी लिया है। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो देश प्रदेश में शान्ति व सुरक्षा की बात की जाती है और वहीं दूसरी ओर किसी सरकार द्वारा अशांति फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। यह उचित नहीं है। हम जनता के प्रतिनिधि है यदि इस तरह की कार्यवाही पंजाब सरकार द्वारा हरियाणा प्रदेश के लोगों के हितों पर कुठाराधात करने के लिए की जाती है तो मैं समझता हूँ कि ऐसी स्थिति में हम लोगों का यहां पर चुनकर आना महत्वहीन हो जायेगा। पंजाब प्रदेश की कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों को हमारी विधान सभा के दरवाजे पर आकर नारेबाजी करने को प्रोत्साहन देकर राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। हमारे विपक्ष के नेता के साथ-साथ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के अन्य सदस्यों ने भी कांग्रेस पार्टी के इस अनैतिक आचरण के खिलाफ विरोध किया है। मैं समझता हूं कि इस तरह के कार्य से कुछ होने वाला नहीं है। हमें मामले की जड़ में जाकर काम करना पड़ेगा। स्पीकर सर, बात भावना की होती है।

जहां तक एस.वाई.एल. नहर मुद्दे पर पंजाब सरकार द्वारा पारित बिल का संबंध है तो निश्चित तौर से it is assault on our sovereignty ही कहा जायेगा। इस तरह के प्रस्ताव हमारे अधिकारों का एनक्रोचमैंट है। यह प्रस्ताव हमारी भावनाओं का भी एनक्रोचमैंट है। पंजाब में जो एस.वाई.एल नहर को मिट्टी से भरने का जो नाटक किया गया है, वास्तव में वह एक बहुत ही संगीन अपराध है।

अध्यक्ष महोदय, मैं इसके विरूद्ध इस सदन के माध्यम से एक प्रस्ताव रखता हूँ और मुझे विश्वास है कि पूरा सदन मेरी भावनाओं से सहमति जतायेगा। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि पंजाब सरकार की एस.वाई.एल. नहर के मुद्दे पर की गई कार्यवाही की यह सदन जोरदार शब्दों में निन्दा करता है, उनके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की जाये तथा निन्दा प्रस्ताव की कॉपी पंजाब सरकार को भेजी जाये। (इस समय मेजें थपथपाई गई)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, संसदीय कार्य मंत्री जी ने पंजाब सरकार द्वारा एस.वाई.एल. नहर पर की गई कार्रवाई के विरूद्ध जो निन्दा प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है। यदि सदन की सहमति हो तो इस निन्दा प्रस्ताव को भी सर्वसम्मति से पास कर दिया जाये।

आवाजें: ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष: यह निन्दा प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पास किया जाता है।

(निंदा प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया।)

मुनक नहर से एक दिन के लिए दिल्ली की जल आपूर्ति में कटौती करने के संबंध मे मामला उठाना तथा दिल्ली के मुख्यमंत्री के विरूद्ध एक निंदा प्रस्ताव पारित करने के लिए अनुरोध करना।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैंने एस.वाई.एल. नहर के उपर एक रैजोल्यूशन दिया था। एस.वाई.एल. नहर के मुद्दे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविन्द केजरीवाल का जो बयान आया था वह बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान था। उन्होंने एस.वाई.एल नहर के बारे में कहा था कि एस.वाई.एल. नहर में जो मिट्टी डाली जा रही है वह ठीक है। हरियाणा से भी दिल्ली को पानी जाता है। हम यह नहीं कहते कि जिस नहर से दिल्ली को पानी जाता है उस नहर को मिट्टी से भर दो या उस नहर पर जिन लोगों की जमीनें आई है उन किसानों को पैसे या जमीनें वापस दे दो। लेकिन कम से कम जब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस किस्म की गैरजिम्मेदाराना भाषा प्रयोग की है तो हमें उनको यह अहसास कराने के लिए कि पानी की क्या कीमत होती है, कुछ समय के लिए दिल्ली का पानी बंद कर देना चाहिए ताकि दिल्ली के मुख्यमंत्री को अपने गैर जिम्मेदाराना बयान देने का अहसास हो सके। पिछले दिनों जब हरियाणा की नहर से दिल्ली जाने वाले पानी को रोक लिया गया था तो सारी दिल्ली में त्राही-त्राही मच गई थी और दिल्ली का मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में जाकर खड़ा हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई कि आप बात-बात पर सुप्रीम कोर्ट में आकर खड़े हो जाते हो। आप क्यों नहीं हरियाणा की सरकार से बात करते हो। मैं दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री के गैर जिम्मेदाराना ब्यान पर सदन में प्रस्ताव लेकर आया हूँ। अध्यक्ष महोदय, आपसे अनुरोध है कि इस प्रस्ताव पर सदन में चर्चा करवाओ और जब सदन में चर्चा होगी तो सारे साथी इस पर बात करेंगे और अपने-अपने विचार रखेंगे और मुझे विश्वास है कि फिर यह सर्वसम्मति से पास भी हो जायेगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस पर चर्चा कराने की अनुमति दें।

श्री अध्यक्ष: अभय जी, आप तो इस सदन के एक अनुभवी सदस्य हैं। आपको हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम से संबंधित नियामावली के नियमों की जानकारी भी भलीभांति रूप से है। इस नियमावाली के अध्याय 19 के अधीन संकल्प के नियम 171 में इस बारे लिखा गया है कि-

"मंत्री से भिन्न कोई सदस्य, जो संकल्प का प्रस्ताव रखना चाहता हो, अपने आशय का कम से कम पूरे पन्द्रह दिन का नोटिस देगा और नोटिस के साथ उस संकल्प का मूल पाठ भी देगा जिसका वह प्रस्ताव रखना चाहता हो"

अभय जी, इस नियम को दिखाने के बाद अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इस नियम में साफ तौर से लिखा गया है कि यदि कोई माननीय सदस्य संकल्प लाना चाहता है तो वह संकल्प से संबंधित नोटिस कम से कम पन्द्रह दिन पहले देगा और इसके अतिरिक्त सदन में लाये जाने वाले प्रस्ताव पर संबंधित मंत्री की सहमति भी आवश्यक होती है। यदि सही मायने में देखा जाये तो हमने पहले ही सदन में एस.वाई.एल. नहर पर निन्दा प्रस्ताव पास कर दिया गया है।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों की मुझे भी जानकारी है। मैंने यह प्रस्ताव आपको प्रस्तुत करते हुये अनुरोध भी किया है कि आप इस प्रस्ताव को नियम 171 के ही तहत ढ़ील देते हुए मंजूर कर सदन में चर्चा करा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: अभय जी, नियम के मुताबिक संकल्प प्रस्ताव पर तुरंत चर्चा नहीं हो सकती है।

श्री जय प्रकाश: अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को उसी भाषा में जवाब देना चाहिए, जिस भाषा का प्रयोग उन्होंने पंजाब और दिल्ली में किया है इसलिए इस संकल्प प्रस्ताव पर चर्चा के माध्यम से ही केजरीवाल को संदेश दिया जा सकता है। केजरीवाल जी को या तो माफी मांगनी पड़ेगी या दिल्ली को पानी से वंछित रहना पड़ेगा। केजरीवाल जी को कोई भी ऐसा अधिकार नहीं मिला हुआ है कि वह अपनी मर्जी के अनुसार पंजाब या दिल्ली में ऐसी धिनौनी भाषा का प्रयोग करें। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से नम्र निवेदन है कि इस संकल्प प्रस्ताव पर चर्चा करवाई जाये।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज): अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बहुत ही घटिया बयान देते हुए कहा है कि पंजाब के पास फालतू पानी नहीं है जो वह हरियाणा को दें। माननीय प्रतिपक्ष के नेता कहते हैं कि हमारे पास भी फालतू पानी नहीं है जो हम दिल्ली को दें। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी को ज्यादा महत्व देने की जरूरत नहीं है। इसके खिलाफ हाउस ने पहले ही निंदा प्रस्ताव पारित किया हुआ है। श्री अरविंद केजरीवाल जी एक ऐसे स्वार्थी व्यक्ति हैं, जिन्होंने हरियाणा की धरती पर जन्म लिया और अब हरियाणा के हितों के खिलाफ बात कर रहें हैं। जो व्यक्ति हरियाणा का ही नहीं हुआ है वह दिल्ली और पंजाब का कैसे होगा? ऐसे व्यक्ति को ज्यादा तवज्जो ना देकर विधानसभा में भी चर्चा नहीं करनी चाहिए। हमारी तवज्जो केवल एस.वाई.एल. नहर पर ही होनी चाहिए।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, संकल्प प्रस्ताव पर चर्चा का विषय एस.वाई.एल. नहर से ही जुड़ा हुआ है।

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, हम केजरीवाल जी के लिए सदन का समय क्यों बर्बाद करें?

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, यदि हम चर्चा ही नहीं करना चाहते हैं तो फिर उसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने का कोई भी औचित्य नहीं था। इसलिए हमने जो निंदा रैजोल्यूशन दिया हुआ है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। रावी ब्यास नदी से हमें 3.85 एम.ए.एफ. पानी की बजाय केवल 1.6 एम.ए.एफ. पानी ही मिलता है। उसी पानी में से हम दिल्ली को उसके हिस्से का 0.2 प्रतिशत पूरा पानी देते हैं। हमें तो पानी पूरा नहीं मिल रहा है और हम दिल्ली को उसके हिस्से का पूरा पानी दे रहें है, फिर भी दिल्ली के मुख्यमंत्री इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, तो उसके खिलाफ चर्चा करने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हमें यह कहकर नहीं छोड़ना चाहिए कि वह हरियाणा का होकर के हरियाणा के हितों के खिलाफ बोल रहा है। उसके खिलाफ चर्चा अवश्य होनी चाहिए। इस प्रकार तो कांग्रेस पार्टी के सदस्यों के खिलाफ भी चर्चा नहीं करनी चाहिए क्योंकि इन्होंने ना जाने अपने शासन काल में क्या-क्या गलत काम किए हैं। जब भी सदन में कोई भी माननीय सदस्य बोलने के लिए उठता है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के सदस्यों की चर्चा करता है तथा उनकी अंगुलियों का इशारा भी खाली पड़ी सीटों की तरफ होता है। अध्यक्ष महोदय, आप इस प्रस्ताव पर चर्चा कराएंगें या नहीं हमें यह बताया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अभय जी, ऐसे संकल्प प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 15 दिन का समय होता है दूसरा गैर सरकारी दिन ही इस पर चर्चा हो सकती है।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आज गैर सरकारी ही दिन है।

श्री अध्यक्ष: अभय जी, आज का गैर सरकारी दिन तो बीत गया है अब तो द्वितीय बैठक शुरू हो गयी है। जब भी इस प्रस्ताव पर चर्चा होगी आपको बता दिया जायेगा।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु): अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रतिपक्ष नेता ने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपके समक्ष रखा है। अध्यक्ष महोदय, आपने माननीय प्रतिपक्ष नेता को विश्वास भी दिलाया है कि इस विषय पर विचार-विमर्श करके चर्चा करवाएंगे। मेरे विचार से नेता प्रतिपक्ष को आपके आश्वासन को स्वीकार करना चाहिए। इनके प्रस्ताव पर आग्रहपूर्वक अभी चर्चा करवाना निश्चित किया जाए, इसकी आवश्यकता नहीं है। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष जी, आप इस मुद्दे की गम्भीरता को नहीं समझ रहे हैं। इस पर आज ही चर्चा होनी चाहिए। अगर आप इस पर चर्चा नहीं कराना चाहते तो हमें बता दीजिए। (विघ्न)

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की तकलीफ जायज है और ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविन्द केजरीवाल ने बहुत ही गैर-जिम्मेदाराना बयान दिया है। वर्ष 1979 में बी.बी.एम.बी. की 85वीं बैठक में हरियाणा को नंगल डैम से 35 लाख एकड़ फीट और दिल्ली को 2 लाख एकड़ फीट पानी मिलना तय हुआ था। हमारे पास पानी लाने का एक ही कैरियर है और वह भाखड़ा मेन लाइन है। भाखड़ा मेन लाइन से हम ऑलरेडी रावी-ब्यास का 44 लाख एकड़ फीट पानी ला रहे हैं। इसी कैरियर से हमें हरियाणा के साथ-साथ दिल्ली के लिए पानी लाने को भी कहा गया था। सतलुज से प्राप्त 16 लाख एकड़ फीट पानी और दिल्ली के लिए 2 लाख एकड़ फीट पानी भी हम भाखड़ा मेन लाइन से ही लाते हैं। शुरू में हम 371 क्युसिक पानी लाते थे लेकिन बाद में सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया कि आपको 125 क्युसिक दिल्ली के लिए पानी और लाना पड़ेगा। अब कुल पानी 496 क्युसिक हो गया जिसे हम भाखड़ा मेन लाइन से लाते हैं। इसके बाद हम इस पानी को नरवाना ब्रांच में लाते हैं और फिर पश्चिमी यमुना नहर में डालते हैं और वहां से इसको दिल्ली ब्रांच मुनक नहर में लाते हैं और फिर हम इस पानी को सी.एल.सी. के माध्यम से दिल्ली पहुंचाते हैं। इसके अलावा यमुना के पानी में दिल्ली का जो 330 क्युसिक पानी का हिस्सा है उसे पश्चिमी यमुना नहर और सी.एल.सी. के माध्यम से हम दिल्ली पहुंचाते हैं। अब श्री अरविन्द केजरीवाल ने जो एस.वाई.एल. नहर को तोड़ने के समर्थन में बयान दिया है उससे हरियाणा के हर आदमी को तकलीफ हुई है चूंकि न तो दिल्ली ने स्वयं कोई नहर बनाई है और न ही नहर बनाने में कोई पैसा खर्च किया है फिर भी हम अपने हिस्से का पानी छोड़कर दिल्ली को दे रहे हैं। अगर हम दिल्ली का पानी न लाएं तो 496 क्युसिक पानी अपने प्रदेश के लिए और भी ला सकते हैं। इसलिए मैंने श्री अरविन्द केजरीवाल के बयान से आहत होकर आज ही उनको चिट्ठी लिख दी है कि हम आपके हरियाणा के विरूद्ध गलत बयान के कारण पानी पहुंचाने में असमर्थ हैं। हरियाणा के लोगों का इस विषय पर ...(विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मेरा विचार है कि आपको इस पर सदन में चर्चा करानी चाहिए। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हाउस को बताना चाहूंगा कि मैंने अभी तक की जो हालत है वह बताई है। हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री को लिख दिया है कि आप नंगल डैम से लेकर दिल्ली तक अपनी नहर बनावाओ और अपना 496 क्युसिक पानी ले जाओ और दूसरी नहर आप ताजेवाला से दिल्ली तक बनवा लो क्योंकि आपके बयान के कारण हम दिल्ली को पानी देने में असमर्थ हैं। हरियाणा प्रदेश को पानी की दिक्कत नहीं हैं। पानी तो हमें पर्याप्त मात्रा में मिला हुआ है। हमें सिर्फ कैरियर की दिक्कत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री हमारे कैरियर के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और हमारे किसानों के हितों का नुक्सान कर रहे हैं। इससे दिल्ली की जनता को भी मैसेज चला गया है कि श्री अरविन्द केजरीवाल सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए दिल्ली का भी नुक्सान कर रहा है। दूसरा, इस समय हमें पानी की काफी दिक्कत झेलनी पड़ रही है। हम अपनी जनता को 5 बार में पानी दे पा रहे हैं। अभी हमारे सामने दो समस्याएं और आई थी। एक दिन दो बच्चे नहर में गिर गए और ग्रामीणों ने हमें वेस्ट यमुना कैनाल नहर रोकने के लिए गुजारिश की और हमें उसे रोकना पड़ा। इससे दिल्ली में पानी नहीं पहुंच पाया और बाद में हमने नहर को शुरू किया तो वहां अमोनिया लेवल बढ़ गया। इसे कम करने के लिए हमें ज्यादा मात्रा में पानी देना पड़ा। इसके बाद दूसरी समस्या जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान जब मुनक नहर को काट दिया गया तो फिर दिल्ली में तीन दिन तक पानी नहीं पहुंच पाया। इससे फिर अमोनिया लेवल बढ़ गया और हमें पानी ज्यादा देना पड़ा क्योंकि अमोनिया का लेवल बढ़ने पर आदमी उस पानी को पी नहीं सकता। इस तरह से जब भी हम दिल्ली का पानी रोकते हैं तो फिर बाद में हमें ज्यादा मात्रा में पानी देना पड़ता है। अब हम अपने प्रदेश में 5 बार में पानी दे पा रहे हैं। नांगल-चौधरी में 10 हजार एकड़ फसल के लिए पानी नहीं पहुंच रहा है। जब भी हम दिल्ली का पानी रोकते हैं तो बाद में उसे अधिक पानी देना हमारी मजबूरी हो जाता है। अब इस मौके पर जब फसल पकने को तैयार खड़ी है हम एक बूंद पानी भी इधर से उधर नहीं कर सकते। इससे हमारा इंटरनल संकट बढ़ जाता है। जहां तक उनको कड़ी से कड़ी बात कहने की बात है तो हमने उनके खिलाफ हाउस में निंदा प्रस्ताव भी पास किया है तथा उनको पत्र भी लिख दिया गया है कि आप अपनी नहर बनवा लो। चौटाला जी, पूरा हाउस आपकी बात से सहमत है। (विघ्न)

15.00 बजे **श्री अध्यक्ष**: चौटाला जी, मंत्री जी ने सारी बात कम्पलीट कर दी है। दिल्ली सरकार के खिलाफ पहले निंदा प्रस्ताव भी पास कर दिया गया है तथा उनको लैटर भी लिख दिया गया है।

श्री ओम प्रकाश धनखड़: अध्यक्ष महोदय, यदि माननीय सदस्य चाहें तो हम इस लैटर को विधान सभा की कार्यवाही का हिस्सा बनाकर सदन के पटल पर भी रख देते हैं।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, इस तरह के लैटर लिखने से बात बनने वाली नहीं है बल्कि हमें इसके लिए कोई कड़ा फैसला लेना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष: चौटाला जी, हाउस तो सिस्टम से ही चलेगा। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, आप इस इशू पर चर्चा करवाएं तो सारी बातें क्लीयर हो जाएंगी। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: चौटाला जी, इस बारे में मंत्री जी ने सारी बातें विस्तार से बता दी हैं। यह इशू 30-35 सालों से चल रहा है। यह सरकार तो पहली बार आई है। अगर कोई कड़ा फैसला लेने की बात थी तो आपकी सरकार तीन बार रह चुकी है आपने क्यों नहीं कोई कड़ा फैसला लिया? यदि आपकी सरकार ने कोई कड़ा फैसला लिया होता तो यह पानी हरियाणा में कब का आ जाता।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, हमारे वक्त में तो यह नहर बनाई गई थी। जब इस हाउस के मुख्यमंत्री बंसीलाल जी थे तो उन्होंने मुख्यमंत्री होते हुए इस बात को स्वीकार किया था कि इस नहर का 60 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा चौधरी देवीलाल जी के वक्त में बना था। जब हमारी सरकार बनी थी तो उस समय हमने सुप्रीम कोर्ट में इस केस की पैरवी की और पैरवी के बाद सुप्रीम कोर्ट से यह फैसला हमारे वक्त में ही आया था जिसमें यह लिखा हुआ था कि या तो पंजाब सरकार एक साल में इस नहर को बनवाए तथा यदि पंजाब सरकार इस नहर को एक साल में पूरा नहीं करवाती है तो केन्द्र सरकार इस नहर को बनवाकर दे ।

श्री अध्यक्ष: चौटाला जी, उसके बाद तो पानी के समझौते रद्द कर दिए गए थे उसके बाद क्या हुआ था यह भी हाउस में बता दो । (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, सरकार के तीन महीने बचे हुए थे और चुनाव आ गए थे।

श्री अध्यक्ष: चौटाला जी, उस समय 9 महीने पहले बी.जे.पी. के विधायकों ने रिजाइन कर दिये थे। मुझे इसलिए याद है क्योंकि रिजाइन करने वालों में मैं भी शामिल था।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, -----

श्री अध्यक्ष: चौटाला जी, हाउस तो संविधान के मुताबिक ही चलेगा। अगर किसी इशू पर दिक्कत आ रही हो तो हमें सुप्रीम कोर्ट में ही जाना पड़ेगा क्योंकि वह इस हाउस से सुप्रीम है। इससे हटकर काम न तो आपकी सरकार कर सकती थी, न कांग्रेस की सरकार कर सकती थी और न ही यह सरकार कर सकती है।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, आप हमें यह बताएं कि आप इस इशू पर चर्चा करवाने के लिए सहमत हैं या नहीं।

श्री अध्यक्ष: चौटाला जी, आप हर इशू पर जबरदस्ती करते हैं। आप जो कहें उस हिसाब से तो सारे फैसले नहीं हो सकते इसलिए आप बैठ जाएं।

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, पिछले दो दिनों से यहां इस इशू पर काम चल रहा है। मैं समझता हूं कि हमारे सामने दो महत्वपूर्ण इशू हैं। पहला तो इस केस की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कोर्ट में इस केस की सुनवाई का समय दो बजे का था और इस पर अभी वहां बहस चल रही है और शाम तक पता चल जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर टिप्पणी देता है या फिर अगली तारीख लगाता है। दूसरी बात राज्यपाल महोदय के पास पंजाब द्वारा भेजा गया बिल साइन होने के लिए पैडिंग पड़ा है। वे साइन करते है या क्या एक्शन लेते है या नहीं लेते हैं अभी देखना है। मेरा कहना यह है कि ये दोनों विषय जुड़े हुए हैं इसलिए इन दोनों बातों की जानकारी आ जानी चाहिए उसके बाद कल इस पर निर्णय कर लेंगे कि इस पर चर्चा करानी है या नहीं। अगर लगता है कि पोजीटिव चल रहा है तो मैं समझता हूं कि इन फालतू के विवादों में पड़ने के बजाय सही दिशा में कार्य करेंगे। अगर हमारे पोजीटिव नहीं होगा तो मैं समझता हूं कि चर्चा ही नहीं बल्कि अगर चर्चा से आगे भी कुछ करना पड़ेगा तो उसके लिए सरकार तैयार है। ऐसा मेरा मानना है।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं तो केवल यह कह रहा हूं कि एस.वाई.एल. कैनाल को लेकर तो कोर्ट में बहस चल रही है। जो मैं कह रहा हूं वह बात इससे जुड़ी हुई नहीं है। मैं यह कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री दिल्ली ने जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है उस पर चर्चा करवाकर निंदा प्रस्ताव पास करके उनको भेजा जाये। आज पूरी दिल्ली को हरियाणा प्रदेश से पानी जाता है। हम अपने हिस्से का पानी मारकर पूरी दिल्ली को पानी देते हैं। दिल्ली का 0.2 प्रतिशत पानी है और पीछे से कम पानी आता है तो हम अपना हिस्सा कम करके दिल्ली को पानी देते हैं। हमारे अपने वाटर वर्क्स में और जोहड़ों में पानी नहीं होता तब भी हम दिल्ली को पानी देते हैं। हमारे लिए कितना भी बड़ा संकट पानी को लेकर आए हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि दिल्ली को पूरा पानी मिले ताकि दिल्ली के लोग परेशान न हों। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है उस पर चर्चा सदन में करानी चाहिए और उसको कैसा जवाब दिया जाए उसके बारे में सभी सदस्यों से पूछा जाए। सरकार मेरी इस बात को दूसरी तरफ ले गई कि मैं एस.वाई.एल. नहर के बारे में पर चर्चा करवाना चाह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब, सिंचाई मंत्री जी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को जो डी.ओ. लैटर लिखा है। उसकी प्रति सभी सदस्यों को अभी दे दी जायेगी।

(इस समय उपरोक्त डी0ओ0 लैटर की प्रति सदन की मेज पर रखी गयी।

ओम प्रकाश धनखड़

अ0स0पत्र क्र0 18-IM/2016.

कृषि, विकास एवं पंचायत सिंचाई, पशुपालन एवं डेरी तथा मत्स्य पालन मत्री, हरियाणा।

दिनांक, चण्डीगढ़ 17, मार्च 2016

विषय :- एस0वाई0एल0 नहर के निर्माण के संबंध में।

आदरणीय श्री अरविन्द केजरीवाल जी,

आपने समाचार पत्रों में ब्यान देकर एस0वाई0एल0 के निर्माण के अवधारण को गलत ठहराया है। आपको विदित होगा कि नंगल डैम से रावी-ब्यास के पानी में हरियाणा को 3.5 एम0ए0एफ0 व दिल्ली को 0.2 एम0ए0एफ0 पानी आबंटित किया गया था।

हरियाणा दिल्ली का 0.2 एम0ए0एफ0 पानी भाखड़ा मेन लाईन नहर से लेकर आता है जो हरियाणा की नरवाना ब्रांच, पश्चिम यमुना नहर प्रणाली के माध्यम से हरियाणा दिल्ली को पहुंचाता है। दिल्ली के लिये उठाये गये इस बोझ के कारण हरियाणा अपना 496 क्यूसिक पानी नहीं ले पाता। इसके अतिरिक्त यमुना का 330 क्यूसिक पानी भी पश्चिम यमुना नहर प्रणाली के माध्यम से हरियाणा दिल्ली को पहुंचाता है।

हमें रावी ब्यास में नंगल डैम हरियाणा व दिल्ली का पानी तो उपलब्ध है लेकिन इस पानी को लाने का साधन उपलब्ध नहीं है और आपने हमारे एकमात्र सम्भावित साधन एस0वाई0एल0 नहर का पंजाब में अपने राजनैतिक स्वार्थ के लिये विरोध कर दिया है। ऐसा करते-करते आप दिल्ली के मुख्यमंत्री होते हुये भी दिल्ली के लोगों के हितों के खिलाफ ही खड़े हो गये हैं।

आपके इस स्टैंड को देखते हुये हरियाणा अपनी नहर प्रणाली से आपका पानी पहुंचाने में असमर्थ रहेगा, क्योंकि आप हरियाणा के किसानों और लोगों के हितों के खिलाफ खड़े हो गये है। दिल्ली के पानी के लिये आप नगंल डैम और ताजेवाला से अपनी अलग नहर बनवाने का कष्ट करें, जिससे दिल्ली का पानी आपके प्रयासों से दिल्ली पहुंच सके।

आदर सहित।

आपका शुभचिंतक

Sd-

(औम प्रकाश धनखड़)

श्री अरविन्द केजरीवाल,
मुख्यमंत्री, दिल्ली,
नई दिल्ली।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भ

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा पुनरारम्भ होगी ।

श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया (ऐलनाबाद) : अध्यक्ष महोदय, महामहिम के अभिभाषण की परिचर्चा आदरणीय बराला साहब के संक्षिप्त भाषण से शुरू होकर नेता प्रतिपक्ष के धारदार तर्कों द्वारा विभिन्न आयामों को छूती हुई आज मुझ तक पहुंची है। मैंने महामहिम का अभिभाषणा बड़े ध्यान से पढ़ा और सुना तथा मुझे जो आशा और उम्मीद थी कि इसमें हरियाणा के विकास के रोड़ मैप की कोई योजना प्रस्तुत की जाएगी। आशा थी कि इसमें विकास की एक नई दिशा दिखाई जाएगी और प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों पर आशावादी घोषणाएं की जाएंगी। मगर बड़े दुर्भाग्य की बात है कि महामहिम का अभिभाषण पूरी तरह निराशाजनक और भ्रामक है। महामहिम के अभिभाषण में पिछले दिनों प्रदेश में जो घटनाक्रम घटा और प्रदेश में कानून व्यवस्था किस तरह से तार-तार होती दिखाई दी उसका कोई जिक्र नहीं किया गया। हरियाणा प्रदेश के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हुआ होगा कि महामहिम के अभिभाषण में कानून व्यवस्था का कोई जिक्र नहीं किया गया। मुझे लगता है कि सरकार ने सोचा होगा कि इस संबंध में आंखें बंद करने से यह समस्या अपने आप हल हो जाएगी। लेकिन लचर कानून व्यवस्था ने जिस तरह से सामाजिक सोहार्द और भाईचारे को बांटने का काम किया उन जख्मों को भरना असम्भव नहीं तो मुश्किल जरूर है। जो पिछले दिनों घटनाक्रम घटा उससे ऐसा लग रहा था कि पूरे हरियाणा की बागडोर उपद्रवियों के हाथ आ गई थी। उस समय पुलिस प्रशासन कहीं भी नजर नहीं आया और न ही पुलिस प्रशासन ने उस आंदोलन को रोकने का काम किया। जब भी कभी कोई छोटा आंदोलन होता है या रास्ता जाम होता है तो पुलिस लाठी चार्ज करती है, पानी की बौछारें और आंसू गैस के गोले छोड़ती है। लेकिन इस आंदोलन के दौरान 4-5 दिन पुलिस प्रशासन निष्क्रिय रहा और मौजूदा सरकार कुंभकरण की नींद सोती रही। क्या कारण थे कि पुलिस ने कहीं कोई लाठी चार्ज नहीं किया। यदि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय होता तो शायद यह दिन देखने को नहीं मिलता। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने तो अपना समूचा समय एक मिथकीय नदी सरस्वती की खोज में, अधिकारियों, अध्यापकों, मंत्रियों और विधायकों को योग कक्षा के बाड़े में ले जाने में और गीता के प्रवचनों को प्रचारित करने में खर्च कर दिया। जब संकट का विस्फोट हुआ तो सरकार एकदम किंकर्त्वयविमूढ़ की स्थिति में आ गई। उनकी स्थिति ऐसी हो गई जैसे गाड़ी की तेज रोशनी के सामने आकर एक हिरन की स्थिति हो जाती है। पुलिस और प्रशासन के जिला स्तरीय अधिकारी उपद्रवियों की व्यापक तैयारियों से पूरी तरह नावाकिफ बने रहे। ये तैयारियां किसी दूरस्थ सीमांत क्षेत्र में नहीं हो रही थी। कल्पना कीजिए कि सेना की टुकड़ियों को हेलीकाप्टरों से उतारना पड़ा। रोहतक अनंतनाग नहीं है, सोनीपत श्रीनगर का बाहरी इलाका नहीं है। मुझे लगता है या तो आगजनी करने वालों के साथ कोई संधि थी। या दूसरी बात यह हो सकती है जिसकी अधिक सम्भावना भी है कि अधिकारियों ने मंत्री परिषद् के सदस्यों के बीच की अंतर्कलह और हताशा को पहचान लिया था। अध्यक्ष जी, जो संतुलन माननीय मुख्यमंत्री और मंत्रिमण्डल के सभी सदस्यों के बीच में होता है ऐसा लगता है कि वह शायद इस आंदोलन के समय कहीं न कहीं बिगड़ गया था। इस बारे में बहुत सी बातें कही जाती है कि यह एक राजनीतिक षड़यंत्र था। मैं भी यह मानता हूं कि इस बात की भी बहुत सम्भावना है कि ऐसा हो सकता है लेकिन प्रशासन का और

[श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया]
राजनीतिक नेतृत्व का भी यह काम होता है कि खुफिया तरीके से इस प्रकार के षड़यंत्रों का पता लगवाकर समय रहते सिरे चढ़ने से पहले ही उनका पर्दाफाश किया जाये अर्थात उनको विफल किया जाये। अगर इस प्रकार के षड़यंत्रों की कामयाबी के बाद अफसोस ज़ाहिर किया जाये तो यह किसी भी जिम्मेदार आदमी के लिए अच्छी बात नहीं होगी। इसी प्रकार से पिछले दिनों हैपनिंग हरियाणा के मामले में भी हमें बहुत सी बातें सुनने को मिली। इसके लिए आदरणीय वित्त मंत्री महोदय ने काफी भाग-दौड़ की। आम आदमी सोच रहा था कि इसमें बड़े-बड़े इनवैस्टर आयेंगे। हरियाणा में उद्योग लगेंगे और हरियाणा के लोगों को उनसे रोज़गार मिलेगा। जिस तरह से हैपनिंग हरियाणा का समापन हुआ उससे हरियाणा प्रदेश की जनता को यह पता चला कि विभिन्न कम्पनियों और हरियाणा सरकार के बीच 367 एम.ओ.यू. साईन हुए और जिनके माध्यम से हरियाणा में 584 लाख करोड़ रूपये के निवेश के वायदे से हरियाणा सरकार प्रोत्साहित थी। इस बारे में मैं यह बताना चाहता हूं कि सरकार के साथ वास्तव में 4 लाख करोड़ का निवेश रीयल एस्टेट में हुआ है। जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई रोड मैप नहीं है। ये रियल एस्टेट की कम्पनियां वही कम्पनियां हैं जो यहां पहले खरीद चुकी हैं। ये कम्पनियां इसके माध्यम से अपनी ज़मीन का सी.एल.यू. चेंज करवाना चाहती हैं।

श्री अध्यक्ष : बलवान सिंह जी, जो आप बातें बता रहे हैं इनका जिक्र तो अभय सिंह जी पहले कर चुके हैं। आप कोई अपने हलके की समस्या के बारे में बात करें ताकि आपका और आपके हलके के लोगों का कोई फायदा हो जाये।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष जी, जैसा कि आपने भी प्वायंट आऊट किया। बलवान सिंह जी मेरे काबिल दोस्त हैं। मुझे लगता है कि किसी ने इनको कॉपी करके दे दिया और पढ़ने के लिए कह दिया। शायद वास्तविकता को लिखने वाले ने भी नहीं जांचा और पढ़ने वाले ने भी नहीं जांचा। जो नेता प्रतिपक्ष ने पहले दिन जो कहा उसकी कॉपी करके इनको पढ़ने के लिए दे दिया। सारे के सारे शब्द यूं की यूं हैं। मुझे लगता है कि इनके कम्प्यूटर वाले से कहीं न कहीं कोई गलती हो गई है। मैं इनको कहना चाहता हूं कि ये इस गलती को चैक करवा लें। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इनको यह सुझाव देना चाहता हूं कि जब यहां पर महामहिम राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण पर चर्चा करते हैं तो वे एक विषय विशेष को लेकर तैयारी करते हैं। अगर किसी माननीय सदस्य को कोई जानकारी चाहिए तो माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रीगण और सारी सरकार का पूरा सिस्टम यहां पर उपलब्ध है। ये हमसे जानकारी ले सकते हैं कि ये एम.ओ.यू. 357 हुए या 359 हुए और इनके तहत 5 लाख 83 हज़ार करोड़ रुपये का निवेश हरियाणा में आयेगा या फिर 5 लाख 84 हज़ार करोड़ रूपये का निवेश हरियाणा में आयेगा। यह निवेश किस-किस सैक्टर में आयेगा और इसके तहत हरियाणा प्रदेश के कौन-कौन से हिस्से में उद्योगों की स्थापना होगी इसके बारे में लगभग-लगभग सभी अखबारों में समाचार छपे हैं ये वहां से जानकारी ले सकते थे, यह सारी की सारी जानकारी हमने नैट पर भी डाली हुई है और नहीं तो हम से ही इस बारे में पूछ लिया जाता हम इनको बता देते। मैं इनके साथ-साथ पूरे हाऊस को भी यह बताना चाहता हूं कि जैसा इन्होंने कहा कि 4 लाख करोड़ रूपये का निवेश रियल एस्टेट सैक्टर में हुआ है ऐसी बात नहीं है। 4 लाख करोड़ रूपये का निवेश रियल एस्टेट सैक्टर में नहीं हुआ है। मैंने उस समय यह इसलिए नहीं कहा कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपना रिप्लाई देंगे तो ये सारी की सारी बातें

उसमें आ जायेंगी। फिर मुझे लगा कि एक ही गलती को बार-बार दोहराया जा रहा है। इसलिए मैं तो माननीय साथी श्री बलवान सिंह जी का सहयोग कर रहा हूं कि ये एक गलती को बार-बार न दोहरायें क्योंकि ऐसा करने से व्यक्ति मज़ाक का पात्र बन जाता है। मैं इनको यह सुझाव देना चाहता हूं कि किसी भी विषय पर बोलने से पहले ये सभी चीज़ों को अच्छी तरह से पढ़कर, जांचकर पूरी जानकारी लेकर आयें ताकि सदन को भी इससे लाभ हो। ये बड़े विद्धान व्यक्ति हैं और इनकी सोच समझ से इस सदन को भी लाभ होगा। इतना नहीं इनकी विद्वता से पूरे हरियाणा प्रदेश को भी लाभ होगा। अगर ये सकारात्मक सोच के साथ सरकार को कोई सुझाव भी देंगे यहां तक कि अगर कोई आलोचना भी करेंगे तो उसको भी हम सहर्ष स्वीकार करेंगे लेकिन जो बार-बार गलती दोहराने वाली बात है यह अच्छी नहीं लगती।

श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया : स्पीकर सर, मेरा इस मामले में आलोचना करने का कोई उद्देश्य नहीं था और न ही मेरी कोई ऐसी मंशा थी क्योंकि मैंने शुरू में ही यह बात स्पष्ट कर दी थी कि इस आयोजन की सफलता के लिए माननीय वित्त मंत्री जी ने बहुत भाग दौड़ की थी। माननीय वित्त मंत्री जी की भाग दौड़ का जो रिजल्ट आया उसके बारे में हरियाणा प्रदेश की जनता जर्नादन को बताना बेहद ज़रूरी है। अध्यक्ष जी, अगर कोई व्यापारी कहीं पर व्यापार करने आता है तो वह सबसे पहले यह देखता है कि वहां पर सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए और शांति होनी चाहिए। जिस तरह से फरीदाबाद की एक कम्पनी हरियाणा विद्युत लिमिटिड ने हरियाणा से असम में अपने कारोबार को शिफ्ट कर लिया है। अगर आप प्रदेश की इण्डस्ट्री को सुरक्षा देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कारगर कदम उठाने चाहिएं जिस प्रकार से वर्ष 2003 में आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन किया था आपको भी इस प्रकार की किसी ऐसी सुरक्षा एजेंसी का गठन करना चाहिए ताकि हरियाणा के सभी ओद्योगिक घराने अपने आपको सुरक्षित महसूस कर सकें। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : बलवान सिंह जी, आप गलत उदाहरण दे रहे हैं। कम से कम आप उदाहरण तो सही दें।

श्री ज्ञान चंद गुप्ता : स्पीकर सर, मैं बलवान सिंह जी के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि ओम प्रकाश चौटाला जी ने तो अपने मुख्यमंत्रित्व काल में करनाल में लिबर्टी फैक्टरी के आगे गड्ढ़े खुदवा दिये थे।

श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया : स्पीकर सर, एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हरियाणा में जो उद्योग हैं वे बंद होने की कगार पर हैं। पिंजौर में जो एच.एम.टी. कम्पनी हे उसके कर्मचारियों को वर्ष 2014 से वेतन नहीं मिला है जिसके कारण वहां के कर्मचारी भुखमरी की कगार पर हैं। वे अपने बच्चों की स्कूल की फीस तक नहीं भर सकते। एच.एम.टी. कम्पनी की वर्तमान कीमत तीन हज़ार करोड़ रूपये है और इसमें 1000 कर्मचारी कार्यरत हैं। यह कम्पनी सरकार की अनदेखी की वजह से बंद होने की कगार पर है।

अध्यक्ष महोदय, अगर सरकार उद्योगों के प्रति इतनी ही समर्पित है तो जननायक चौधरी देवीलाल जी ने फतेहाबाद को औद्यौगिक मानचित्र पर लाने के लिए सबसे बड़ी भूना शुगर मिल की स्थापना की थी। आप उस भूना शुगर मिल की नीलामी की जांच करवायें तथा हमारे इलाके में पैडी और कॉटन ज्यादा होती है उससे संबंधित कोई कारखाना वहाँ पर लगवाया जाये ताकि लोगों को रोजगार मिल सके और किसान को अपनी फसल का उचित मूल्य भी मिल सके । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : बलवान सिंह जी, आप दो मिनट में वाइंड-अप कीजिए।

श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया : अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक मेरे हल्के की बात है तो मैंने पिछली बार भी यह बात उठाई थी कि मेरे हल्के के कई गांवों में सेम की समस्या है लेकिन उसका अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। इसी प्रकार से मैंने 100 बैड के हॉस्पीटल की भी मांग की थी और वहाँ पर कोई पोस्ट-ग्रेजुएट कॉलेज नहीं है उसकी भी मांग की थी लेकिन अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. अभय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय साथी श्री बलवान सिंह को समाधान बताया था कि खेतों में पानी कम दिया करो और फालतू पानी महेन्द्रगढ़ जिले के एरिया में भेज दिया करो । ऐसा करने से इनकी सेम की समस्या दूर हो जाएगी और महेन्द्रगढ़ के एरिया में पानी भी मिल जाएगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया : अध्यक्ष महोदय, यह तो मजाक का विषय है, इनको क्या पता कि सेम की समस्या क्या होती है ? वे लोग पशुधन भी नहीं रख सकते हैं। यादव साहब, मैं सबसे पढ़ा-लिखा आदमी आपको मानता हूं और आप भी इस तरह की बात करते हैं।

डॉ. अभय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं पढ़ा-लिखा हूँ इसीलिए इनको कह रहा हूँ कि इनके पास पानी ज्यादा है और हम सूखे से मर रहे हैं इसलिए कुछ पानी हमें दे दें तो इनकी समस्या भी खत्म हो जायेगी और हमें पानी मिल जायेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया : अध्यक्ष महोदय, यादव साहब अब तो अपने लिए पानी का इंतजाम कर ही सकते हैं क्योंकि ऊपर भी आपकी सरकार है और नीचे भी आपकी सरकार है। अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूँ कि स्कूलों का बहुत बुरा हाल है। सरकार शिक्षा पर इतना खर्च करती है और योग्य अध्यापक भी लगाती है लेकिन फिर भी लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राईवेट स्कूलों को ज्यादा तरजीह देते हैं। आज प्रदेश में 188 स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक भी अध्यापक नहीं है तथा 81 स्कूल ऐसे भी हैं जिनमें कोई भवन नहीं है। इसी प्रकार से 796 ऐसे स्कूल हैं जिनमें विद्यार्थियों की संख्या 20 से भी कम है। भाजपा के पिछले डेढ़ वर्ष के शासनकाल में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित 10वीं तथा 12वीं की परीक्षाओं के जो परिणाम आए हैं वे सरकार के शिक्षा स्तर को सुधारने की पोल खोलते हैं। इस बारे में मेरा माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन है कि आप एल.के.जी. और यू.के.जी. की कक्षाएं शुरू कीजिए क्योंकि सरकारी स्कूलों में बच्चे सीधे ही पहली कक्षा में भर्ती होते हैं इसलिए अंक कम आते हैं।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया कह रहे हैं कि प्रदेश में 81 स्कूल ऐसे हैं जहाँ भवन नहीं है। यह बात सही नहीं है। मेरा इनसे अनुरोध है कि ये अपने आंकड़े मुझे दे दें मैं इनकी जांच करवा लूँगा। आज के दिन कोई भी विद्यालय बिना भवन के नहीं है। यह बात सही है कि कुछ विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या कम थी तथा उसके लिए हमने रैशनेलाईजेशन करवाया है। हमारा नारा भी है कि कोई बच्चा अध्यापक के बिना नहीं रहेगा और कोई अध्यापक बच्चे के बिना नहीं रहेगा।

श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मेरा एक सुझाव है कि सरकारी स्कूलों में दाखिले सारा साल नहीं चलने चाहिएं। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूँगा कि जहाँ पर 10-12 छात्र हैं वहाँ पर भी एक अध्यापक है और जहाँ पर 60 छात्र हैं वहाँ पर भी एक अध्यापक है इसलिए यह छात्र और अध्यापक का अनुपात ठीक होना चाहिए जिससे उनकी शिक्षा प्रभावित न हो । अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

श्री अनूप धानक (उकलाना) (एस.सी.): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। राज्यपाल के अभिभाषण के पैरा नं. 15 में आपने ओलावृष्टि और बेमौसमी वर्षा से हुए नुकसान का जो 1092 करोड़ रूपये का मुआवजा वितरित किया है उसमें मेरे हल्के को पूरी तरह से वंचित रखा गया है। इसके साथ मेरे क्षेत्र का एक किरौड़ी गांव है उसके बारे में मैंने वित मंत्री जी से पहले भी कहा था जिसके लिए उन्होंने 2 करोड़ 82 लाख रूपये का मुआवजा मंजूर किया था लेकिन वह मुआवजा भी अभी तक नहीं मिला है। जहां तक विकास कार्यों की बात है मैंने तो सुना था कि राजाओं के मुंह से निकला हुआ शब्द कानून बन जाता है। मुख्यमंत्री जी जब हिसार में गये थे तो इन्होंने डी.प्लान की मीटिंग ली थी। 11 करोड़ रूपये की राशि जो हिसार के डवैल्पमैंट प्लान की थी उसमें मुख्यमंत्री जी ने वहां के हर एक विधायक को 75-75 लाख रूपये के काम की रिक्मैंडेशन मांगी थी ताकि काम हो सकें। लेकिन हमारे वित मंत्री जी के क्षेत्र के लिए 3 करोड़ 34 लाख रूपये के काम किये हैं, हिसार के विधायक एवं मुख्य संसदीय सचिव डां. कमल गुप्ता के क्षेत्र के लिए 2.8 करोड़ रूपये विकास कार्यों के लिए स्वीकृत किये गये जबकि मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिए मात्र 27 लाख 68 हजार रूपये की राशि स्वीकृत की गई है। हमारे नलवा के विधायक श्री रणबीर गंगवा के क्षेत्र के लिए 37 लाख 60 हजार रूपये की राशि तथा बरवाला के विधायक वेद नारंग को 19 लाख 71 हजार रूपये स्वीकृत की गई। (शोर एवं व्यवधान)

वित मंत्री (कैप्टन अभिमन्यू) : अध्यक्ष महोदय, ये अपनी पार्टी के सदस्य को ही बोलने नहीं दे रहे हैं। अनूप जी मेरे गवांडी हैं। विपक्ष के साथियों को अपनी ही पार्टी के एक गरीब सदस्य को अपनी बात कहने का अवसर देना चाहिए। लेकिन इस तरह का व्यवहार करके ये अपनी ही पार्टी के एक गरीब आदमी को दबा रहे हैं। (शोर) अध्यक्ष महोदय, इनको भाई अनूप जी को बोलने देना चाहिए। (शोर)

श्री अध्यक्ष : गंगवा जी, आपको मौका मिलेगा उस समय आप अपनी बात कह लेना। आप अनूप जी को एक बार अपनी बात पूरी कह लेने दें क्योंकि उनका सात मिनट का समय है। प्लीज आप बैठ जाईये।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, मुझे इसमें इतना ही कहना है मैं स्वयं उस ग्रीवैंसिज कमेटी की मीटिंग में गया था और उस दिन एक डी- प्लान के बारे में मीटिंग हुई थी। यह बात गंगवा जी बिल्कुल सही है। उस मीटिंग में मैंने कहा था कि हर एक विधान सभा क्षेत्र में बराबर-बराबर बजट का हिस्सा होना चाहिए। वह राशि 75 लाख थी या कितनी थी वह मुझे इस समय ध्यान नहीं है लेकिन अगर उसमें उस समय जो कुछ भी कहा गया था उसके बारे में डिप्टी कमिशनर से बात करके डी- प्लान पर जितना रूपया खर्च करने के लिए कहा गया था अगर वह खर्च नहीं हुआ होगा तो वह पूरा खर्च हो जाएगा।

श्री रणबीर सिंह गंगवा : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने 50 लाख रूपये के विकास कार्य विधायक रिक्मैंडेशन पर कराने के लिए पहले कहा था और विधायकों ने कहा कि एक-एक करोड़ रूपये के काम विधायकों की रिक्मैंडेशन से कराए जाएं। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 75-75 लाख रूपये के काम विधायकों की रिक्मैंडेशन से करवा दिये जाएंगे। जहां तक 37 लाख 60 हजार रूपये के काम मेरे हलके में कराने के बारे में श्री अनूप जी कह रहे हैं वे भी मेरी रिक्मैंडेशन से नहीं हुए। हमारे वहां का जो प्लानिंग ऑफिसर है उसने यह कह कर कि विधायक जी आप एक-आध काम और दे दो आपके तो पिछले काम भी हो जाएंगे। उसने यह प्वाइंट आऊट करके कि यहां-यहां का कह लो वहां तो बाकायदा जिला परिषद के मैंबरों को वहां से जिताने के लिए वहां के विधायकों से अनाऊंसमैंट करवा कर वहां से जो मैंबर थे वह ग्रांट भी हमारे नाम लिख दी थी। यह सच्चाई है इसके लिए आप भले ही डिप्टी कमीशनर से बात कर लें। वहां एक मॉनेटिरिंग कमेटी की मीटिंग हुई थी उसके अन्दर भी डिप्टी कमिशनर साहब को कहा था और आपके कहने के बाद जो हमारी रिक्मैंडेशन थी और जो हमारी प्रायर्टी थी उसमें से एक रूपया भी नहीं लगा।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, हम इसके बारे में पता कर लेंगे।

श्री अनूप धानक : अध्यक्ष महोदय, हिसार संसदीय क्षेत्र से हमारे सांसद दुष्यंत चौटाला जी को 27 लाख 40 हजार रूपये स्वीकृत किये गये हैं और मुख्यमंत्री जी आपके जो बी.जे.पी. पार्टी के पदाधिकारी थे जो आपके महामंत्री थे उनकी सिफारिश पर एक करोड़ 47 लाख रूपये स्वीकृत किये गये हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य महामंत्री श्री सुजीत सिंह की सिफारिश पर 71 लाख 10 हजार रूपये स्वीकृत किये गये हैं। मुख्यमंत्री जी, आपकी बात का खुलासा दैनिक भास्कर अखबार ने किया है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने हल्के की समस्याओं को बताना चाहूंगा कि वर्ष 2007-08 में सरकार ने अग्रोहा में बस अड्डा बनाने के लिए दो एकड़ जमीन एकवायर की थी लेकिन वहां अब तक बस अड्डे का निर्माण नहीं हुआ है तो मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि वहां पर बस अड्डे का निर्माण करवाया जाए। इसके अलावा वर्ष 2007-08 में ही अग्रोहा में तहसील बनाने के लिए सात एकड़ जमीन एकवायर की थी लेकिन अभी तक तहसील कार्यालय के भवन का निर्माण नही हुआ है। अत: वहां पर तहसील भवन कार्यालय का निर्माण करवाया जाए। उकलाना हल्के के गांव खेदड़ से भैणी -बादशाहपूर वाले रास्ते पर सड़क के निर्माण के लिए पत्थर बिछाया गया है परन्तु वहां सड़क बनाने का काम बन्द है उसको शुरू करवाया जाए। सरकार के प्रावधान के तहत खेदड़ थर्मल प्लांट के 10 किलोमीटर के अधीन आने वाले गांव को 24 घण्टे बिजली उपलब्ध कराने का प्रावधान है और सरहेड़ा, गैबीपुर, खरकड़ा, खेदड़, बालक, भैणी बादशाहपूर, बधावड़ इन गांवों में 6-7 घण्टे बिजली आती है उनको 24 घण्टे बिजली उपलब्ध करवाई जाए। इसके साथ उकलाना हल्के के गांव में ढ़ाणियां बहुत हैं उनको बिजली उपलब्ध करवाई जाए। अध्यक्ष महोदय, उकलाना हलके के सोथा में जलघर में मौजूदा पानी का एक टैंक है जो पर्याप्त नहीं है ग्रामीणों के पीने के स्वच्छ पानी की आवश्यकताओं को पूरा किया जाए और इसके लिए पानी का दूसरा टैंक बनवाया जाए और इसी के साथ उकलाना गांव के वार्ड नं. 11,12 व 13 में सीवरेज की व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाए। उकलाना के गांव अग्रोहा में बुस्टिंग स्टेशन के लिए जमीन एक्वॉयर हुई थी लेकिन कार्य अभी तक चालू नहीं हुआ है, इस कार्य को भी शुरू करवाया जाना चाहिए। उकलाना गांव के वार्ड न.13 में गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। जिससे बीमारियों के

फैलने का खतरा बना हुआ है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि यहां पर पार्क का निर्माण करवाया जाये। इसके अतिरिक्त गांव सुरेवाला से उकलान सड़क को चौड़ा करने व डिवाईडर बनाने की जरूरत है, उकलाना मंडी में रेलवे लाईन अंडर पास बनवाया जाये, गांव सौथा से खेड़ी जालब तक कच्चे रास्ते को पक्का करवाया जाये, गांव बालक से सदोल तक कच्चे रास्ते को पक्का करवाया जाये, गांव सिवानी बोलान जिसकी जनसंख्या 15000 है, के 8वीं कक्षा के स्कूल को अपग्रेड करके 12वीं स्तर तक का किया जाये। गांव बिठमड़ा, गैबीपुर, सरहेढ़ा हसनगढ़ व किरमारा के स्कूल का दर्जा बढ़ाया जाये। उकलाना हल्के में आई.टी.आई. व पोलीटैकनिकल कालेज का निर्माण करवाया जाये। उकलाना हल्के की नहरों में महीने में कम से कम दो सप्ताह पानी दिया जाए । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उकलाना की जर्जर ईमारत का निर्माण करवाया जाये, सी.एच.सी. उकलान में एम.ओ. तथा एस.एम.ओ. के रिक्त पद भरे जायें। पिछले बजट सत्र में उकलाना मण्डी में पार्क बनवाने का आश्वासन दिया गया था लेकिन कोई पार्क नहीं बनवाया गया है, इसलिए वहां पार्क का निर्माण करवाया जाये। इसके अतिरिक्त प्रभुवाला, सन्डौल, किराडा, ढांड, ज्ञानपुरा, बाडाखेड़ा, सूरेवाला, छान, नयागांव, कन्डुल, भेरी अकबरपुर तथा सरहेड़ा गांव में मिनी बैंक की व्यवस्था की जरूरत है। गांव लितानी में पार्क बनाया जाये, उकलान मण्डी में महिला सामुदायिक केन्द्र बनवाये जाये, अग्रोहा में बी.डी.पी.ओ. के पद को तुरन्त भरा जाये, गांव बालक में स्टेडियम के लिए 6.5 एकड़ जमीन दी गई है इस पर जल्द से जल्द स्टेडियम बनाने की आवश्यकता है। गांव बधावड़ में भी स्टेडियम बनाने की जरूरत है। उकलाना विधान सभा क्षेत्र में आवारा पशुओं से फसलों को बचाने के लिए कोई योजना बनाई जाये, अग्रोहा को पर्यटन स्थल बनाया जाये। अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के मैं अभी ओलावृष्टि व तेज बारिश की वजह से गेहू व सरसों की फसल को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है अत: यहां जल्द से जल्द गिरदावरी करवाकर मुआवजा दिलवाया जाये। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1993-1994 में पांच बेरोजगार युवकों को तत्कालीन सरकार द्वारा रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए परिवहन समिति बनाकर परमिट अलॉट किए गए थे। इन परिमिटों को परिवहन विभाग की अधिसूचना दिनांक 25.2.2016 के द्वारा रद्द करने का काम किया गया है। इन बेरोजगार युवकों की समितियों ने बस खरीदने के लिए जो लोन लिया था उसकी एवज में 20-22 लाख रूपये का कर्जा चढ़ा हुआ है। अगर रूट परमिट कैंसिल कर दिये जायेंगे तो यह बेरोजगार कर्जा कैसे उतारेंगे। परिवहन समितियों को बंद करने से इनसे जुड़े 9000 परिवार प्रभावित होंगे जिन पर कुल मिलाकर 180-190 करोड़ रूपये का कर्जा बकाया है इस तरफ सरकार ध्यान दें। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान अपने हल्के की समस्याओं को रखने का मौका दिया उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद

श्री हरविन्द्र कल्याण (घरौंडा): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। महामहिम राज्यापल ने अपने अभिभाषण के माध्यम से हरियाणा सरकार की सोच और नीतियों को जो सदन में व्यक्त किया मैं उसकी सराहना करते हुए पुरजोर समर्थन करता हूँ।16 महीनों के कार्यकाल में हरियाणा की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में जिस तरीके से काम किया है। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में उसके अभूतपूर्व नतीजें निकलकर सामने आयेंगे। चाहे इंफ्रॉस्ट्रक्चर की बात हो, कुंडली मानेसर पलवल हाईवे के इतिहास को यदि हम उठाकर देखें और जिस तीव्र गति से आज वहां पर काम शुरू हुआ है जी.टी.रोड़ का

[श्री हरविन्द्र कल्याण]

सिक्स लेन जो पिछले कई सालों से लगभग बंद पड़ा हुआ था यह इंफ्रॉस्ट्रक्चर का एक उदाहरण है। इसी प्रकार ई-रजिस्ट्री और ई-सेवाओं के माध्यम से जो प्रदेश के लोगों को जो सहूलियतें प्रदान की जा रही हैं यदि हम दफतरों की बात करें बॉयोमीट्रिक अटैंडेंस की वजह से आज जिस तरीके से अधिकारी व कर्मचारी लोगों के काम के लिए हर समय दफतरों में उपस्थित मिलते हैं। यह एक बदलाव है। Low Cost Housing, Sports Policy, Industrial Policy किसानों को एतिहासिक मुआवजा, महिला थानों की स्थापना, Skilled Development, आदर्श ग्राम योजना, पंचायती राज कानून में संशोधन आदि से एक बहुत बड़ा बदलाव हरियाणा प्रदेश में आया है। माननीय मंत्री श्री कर्ण देव कम्बोज जी यहां पर बैठे हुए हैं। मैं ब्लॉक समिति के चुनाव का अगर जिक्र करूं तो उस कड़ी में करनाल जिले में ब्लॉक समिति में 6 में से 4 सर्वसम्मति से चुनी जानी करनाल शहर जिसमें घरोंड़ा और इन्द्री जिसमें दोनों विधान सभा क्षेत्रों के गांव पड़ते हैं। जरनल कैटेगरी में होने के बावजूद वहां पर चेयरमैन अनुसूचित जाति सर्वसम्मति से चुना जाना यह एक बहुत बड़ा संदेश है पूरे प्रदेश और पूरे भाईचारे के लिए। इसी के साथ-साथ महिला इसी के साथ-साथ महिला का जनरल कैटेगरी में पंचायत के चुनावों में चेयरमैन और वाईस चेयरमैन के पदों पर का चुना जाना महिला सशक्तिकरण की दिशा में बहुत बड़ा उदाहरण है। हम सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से जो भी बातें सदन में रखी हैं उसका आधार केवल विकास ही है। प्रदेश सरकार के विकास पर ही लोगों को विश्वास हुआ है। आज जिस तरीके से हरियाणा प्रदेश प्रगति के मार्ग पर चल रहा है उसी के साथ-साथ इस चीज का भी ध्यान रखा जा रहा है कि हमारा समाज आदर्श बनें। हमें प्राचीन संस्कृति के साथ जुड़कर चलना चाहिए। हमारी सरकार ही गौ संवर्धन गौ संरक्षण एक्ट लेकर आई थी। इसी तरह से 'स्वच्छता अभियान' और 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' इस प्रकार की अनेकों अच्छी योजनाएं हमारी सरकार लेकर आई है। अध्यक्ष महोदय, श्रीमती नैना चौटाला ने बड़ी संजीदगी से महिलाओं के बारे में सदन में बताया था। मैं समझता हूँ कि इसके बहुत अच्छे परिणाम निकलकर सामने आएंगे। मैं एक बात और खासतौर पर जिक्र करना चाहूँगा कि हरियाणा सरकार किसी एक विशेष वर्ग और इलाके के लिए काम ना करती हुई पूरे प्रदेश के लोगों के लिए समान विकास के लिए काम कर रही है। हरियाणा में प्रगति तभी हो सकती है जब हरियाणा में भाईचारे का माहौल हो। हरियाणा प्रदेश में पिछले दिनों जो घटनाएं हुई मैं समझता हूँ कि उसकी जितनी निंदा की जाये कम है। आज जिन लोगों ने अपने राजनैतिक स्वार्थ के लिए हरियाणा में भाईचारे का माहौल खराब करने की कोशिश की है, मैं समझता हूँ कि इतिहास में इसका जिक्र हमेशा काले अक्षरों में लिखा जायेगा। आने वाली पीढ़ियाँ उनको कभी माफ नहीं करेगी। अध्यक्ष महोदय, हर सरकार ने अलग-अलग समय में अलग-अलग सोच के साथ काम किया है ओर मैं समझता हूँ कि किस सरकार ने कितना अच्छा काम किया, उसका आंकलन प्रदेश की जनता करती है। दिसम्बर, 2014 में गुजरात के अंदर प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ था, उसमें मुझे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ जाने का मौका मिला था। गुजरात चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इण्डस्ट्रीज ने एक मीटिंग का आयोजन किया था। उस मीटिंग में यह विषय उठाया गया था कि हरियाणा के तीनों तरफ दिल्ली होने के बावजूद भी लोग इन्वेस्ट दूसरे राज्यों में क्यों करते हैं। उनका जवाब सुनकर बड़ी शर्म महसूस हुई क्योंकि उन्होंने कहा कि हम हरियाणा में निवेश तो करना चाहते हैं मगर एक बहुत बड़ा फर्क है। हम जिन-जिन राज्यों में जाकर निवेश करते हैं हमसे पूछा जाता है कि आपको निवेश करने के लिए

किस प्रकार की सहूलियतें चाहिए लेकिन जब हम हरियाणा में निवेश के लिए आते हैं तो हमसे पूछा जाता आप हमारे लिए क्या कर सकते हो? उसी समय हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उसी समय आश्वासन दिया कि अब समय बदल चुका है। यह बात सही है कि पिछले शासनकाल के दौरान हरियणा को नम्बर-1 कहा जाता था, लेकिन यह सोचने की बात है कि देश के अंदर हरियाणा प्रदेश की किस प्रकार की छवी थी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस विषय को गंभीरता से लेते हुऐ एक साल में इस तरीके से काम किया कि एक सुखद वातावरण हरियाणा में बना है। यह सुखद वातावरण हरियाणा प्रदेश में कायम रहे इसकी जिम्मेवारी हम सभी की बनती है। सरकार पूरे तरीके से विकास के काम करने के लिए वचनबद्ध है। एसवाईएल नहर के मुद्दे पर भी अलग-अलग तरह की जो बातें सामने आई हैं मैं समझता हूँ कि यह कोई अच्छा शुभ संकेत नहीं है । आज हरेक कोई अपनी-अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाने लग जाता है। मैं समझता हूं कि उन्होंने माननीय संस्था का अपमान करने का काम किया और मैं यह भी आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस तरह की कोई भी बात सदन में हो तो हमें सदन की गरिमा को बनाए रखने के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मेरे घरौंडा विधान सभा क्षेत्र में जिस तरीके से विकास का काम चल रहा है, चाहे कल्पना चावला मेडिकल यूनीवर्सिटी बनाना हो, चाहे पब्लिक हैल्थ सब-डिविजन हो, चाहे रेलवे अंडर ब्रिज बनना हो, घरौंडा के विकास कार्यों की एक बहुत लम्बी लिस्ट इस सरकार में बन गई है। घरौंडा विधान सभा क्षेत्र के लोग कहते हैं कि हमें तो 20 साल के बाद अहसास हुआ है कि सरकार भी कोई चीज होती है। हमारे क्षेत्र की सब-डिविजन और लड़कियों के कॉलेज जैसी कई मांगें पूरी हुई हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस सरकार में घरोंडा विधान सभा क्षेत्र प्रगति के मार्ग पर चल पड़ा है और बहुत आगे जाएगा। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।

श्री नरेश कौशिक (बहादुरगढ़): अध्यक्ष महोदय, मुझे पिछले सत्र में बोलने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था। इसलिए मुझे इस सत्र में भी पूरी उम्मीद नहीं थी कि मुझे बोलने का समय दिया जाएगा। आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार को बने हुए लगभग डेढ़ वर्ष हो गया है। जिस प्रकार से पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ हरियाणा प्रदेश की सम्मानित जनता ने पूर्ण बहुमत से माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार को चुना है। उसी विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी "सबका साथ सबका विकास" नारे के साथ पूरे हरियाणा में समान विकास और समान रोजगार के तहत विकास कार्य कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पहले कांग्रेस पार्टी के शासन में दस साल की राजनीति में माननीय पूर्व मुख्यमत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा कुण्डली-मानेसर-पलवल एक्सप्रैस वे पर राजनीति करते रहे और उस पर दस सालों में एक इंच भी कार्य नहीं हुआ लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद उस बड़ी तेजी से कार्य किया जा रहा है इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। हरियाणा में हमारी सरकार ने पिछले एक साल में विकास के बहुत सराहनीय कार्य किये हैं। पिछली बार किसानों की फसलों पर जिस तरह से ओलावृष्टि की मार पड़ी उससे उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रही। पिछली सरकार हरियाणा के ऊपर 80 हजार करोड़ रूपये के कर्ज छोड़कर गई थी। उस स्थिति को देखते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक हजार 92 करोड़

[श्री नरेश कौशिक]

रूपये मुआवजे के रूप में किसान भाइयों को देने का काम किया। इसके लिए भी मैं अपनी किसान हितैषी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो गौ-सेवा और गौ-संरक्षण कानून हरियाणा प्रदेश में बनाने का एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है उसकी पूरे देश में सराहना की गई है। हमारे पूर्वजों द्वारा गौमाता को माता का दर्जा दिया गया था उसके संरक्षण के लिए जो कानून बनाया है उसके लिए भी हम मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी और सरकार विकास की तरफ बढ़ रही थी परंतु कुछ लोगों ने राजनीतिक लाभ उठाने के लिए सामाजिक ताने-बाने को खराब करने की कोशिश की क्योंकि वे लोग नहीं चाहते थे कि एक ईमानदार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ईमानदारी से हरियाणा प्रदेश की सरकार चले। यह सरकार इसी तरह चलती रही तो मैं समझता हूं कि यह सरकार कम से कम लगातार 10 साल तक हरियाणा प्रदेश में शासन करेगी परंतु इन लोगों की नियत यह नहीं थी कि शासन इसी तरह से चले। उस बदनियती के होते हुए उन्होंने हरियाणा में आरक्षण के दौरान इस तरह के हालात पैदा करवाए। जो लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपने आरक्षण की मांग कर रहे थे उनको अस्थिर बनाने के लिए लोगों की वीडियो क्लपिंग बनाकर सरकार के सामने लाई गई। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जिन लोगों ने सरकार के ताने-बाने को खराब करने की कोशिश की है उनके खिलाफ सख्त कारवाई की जाए। अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों पानीपत में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे और उन्होंने "बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ" का संकल्प हरियाणा सरकार को देने का काम किया है। इसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए जो लिंगानुपात 1000 के पीछे 830 या 835 था, उसको 900 करने का काम किया गया है उसके लिए मैं सरकार का और इस प्रदेश की जनता का धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने हरियाणा प्रदेश के हालात ठीक न होते हुए भी पिछले दिनों गुड़गांव में ग्लोबल इन्वैस्टर्स समिट का आयोजन किया जिसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। उस समिट को भी अस्थिर बनाने की मंशा कुछ लोगों की थी। अध्यक्ष महोदय, बाहर के औद्योगिक इन्वैस्टर्स हरियाणा में निवेश करेंगे तो उससे हमारे प्रदेश का विकास होगा। जो लोग हरियाणा में उद्योग लगाना चाहते हैं इस समिट से उनका विश्वास हरियाणा में बढ़ेगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा यह अनुरोध है कि जो लोग समाज में अस्थिरता बनाने की कोशिश करते हैं उनके खिलाफ सख्त कारवाई होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के साथ साथ अपने हल्के की कुछ बातें यहां रखना चाहूंगा। मैं एक ऐसे हल्के से सम्बंध रखता हूं, जहां के लोगों ने बड़ी आशा और उम्मीद के साथ पहली बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को चुना है। अध्यक्ष महोदय, गेट वे आफ हरियाणा होने के कारण बहादुरगढ़ में कमर्शियल व्हीकल्ज बहुत हैं। मंत्री जी यहां बैठे हैं, मैं उनसे और अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से भी निवेदन करता हूं कि एक औद्योगिक केन्द्र होने के नाते हमारे यहां पर एक ट्रांसपोर्ट नगर बनाया जाए क्योंकि यहां आए दिन उद्योगपतियों और ट्रांसपोर्ट वालों की आपस में खींचा तानी होती रहती है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि बहादुरगढ़ हल्के की जनसंख्या ढाई लाख के आस पास है इसलिए यहां की आबादी और कमर्शियल व्हीकल्ज को देखते हुए एक बाई पास का निर्माण अवश्य करवाया जाए। अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के के अंदर बालोर गांव है। वहां इनैलो पार्टी की सरकार में तकरीबन 56 एकड़ उपजाऊ जमीन एक्वायर कर ली गई थी। मेरा निवेदन है कि सरकार उस जमीन को बचाने की कोशिश करे ताकि गांव के लोग अपना गुजर

बसर कर सकें। सरकार द्वारा अनाज मंडी के लिए 56 एकड़ जमीन एक्वायर की गई थी। बराई गांव के जमींदारों ने रैजोल्यूशन पास करके दिया है और लोगों ने मुख्यमंत्री को एफीडैविट भी दिए हैं कि बलोर गांव की जमीन निरस्त करके बराई गांव की जमीन पर अनाज मंडी बनाने का काम किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, हमारे वहां पर रेलवे लाईन पार लड़कियों का वैश्य कालेज है जहां पर कालेज आने जाने के लिए अंडर पास बनाना बहुत जरूरी है। पिछली सरकार के समय में वहां पर अंडर पास बनाने के लिए 32 करोड़ रूपये की राशि जमा हुई थी लेकिन अभी तक वह अंडर पास नहीं बना है। मेरी सरकार से मांग है कि वहां पर जल्द से जल्द अंडर पास बनवाया जाये। अध्यक्ष महोदय, अंत में मेरा सभी सम्मानित सदस्यों से निवेदन है कि जिस प्रकार का माहौल पिछले दिनों हरियाणा प्रदेश में हुआ उसको समझते हुए भाईचारे को कायम करने का हम सभी काम करेंगे तो हरियाणा प्रदेश निश्चित रूप से उन्नति करेगा। धन्यवाद।

श्री बलवंत सिंह (सढ़ौरा) (एस.सी.) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। महामहिम राज्यपाल महोदय ने 14 मार्च को अपना अभिभाषण इस महान सदन में रखा था। महामहिम का अभिभाषण सरकार का आईना होता है कि सरकार आने वाले वर्ष में क्या-क्या विकास के कार्य करनी जा रही है और सरकार की मंशा तथा उद्देश्य क्या हैं ? अध्यक्ष महोदय, यदि महामहिम के अभिभाषण को लाईन टू लाईन पढ़ा जाए या देखा जाए तो पता चलता है कि महामहिम ने हर बिंदु को छूआ है। महामहिम के अभिभाषण में दलित से लेकर किसान, मजदूर, व्यापारी, इण्डस्ट्रियलिस्ट यानि सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। जो दर्शाता है कि सरकार हर आदमी का साथ, हर आदमी का विकास करना चाहती है। ऐसा करने पर ही प्रदेश में चहुँमुखी विकास होगा। अध्यक्ष महोदय, समय का अभाव है और अगर मैं महामहिम के अभिभाषण के एक-एक बिंदु पर बात करूंगा तो बहुत समय लगेगा इसलिए मैं अपनी बात संक्षिप्त में कहूंगा। आज हरियाणा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में जिस तरक्की की राह पर जा रहा है वह अपने आप में मिसाल है। आज हरियाणा प्रदेश हर विषय और क्षेत्र में विकास की राह पर अग्रसर है। अध्यक्ष महोदय, मैं पहले भी विधायक रहा हूं। एस.वाई.एल. का मुद्दा हर सैशन में आता है जो कि हमारी जीवन रेखा है। मैं कहना चाहूंगा कि सदन में तो चर्चा हमेशा होती है लेकिन पहले वाली सरकारों ने उस पर कभी संजीदगी से काम नहीं किया। अब हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस मुद्दे पर लगातार सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही चल रही है और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे हक में जल्द उस पर फैसला आयेगा तथा हरियाणा प्रदेश को अपने हिस्से का पानी मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, जहां तक उद्योगों की बात है इस बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगा कि प्रदेश में उद्योग बढ़ाने के लिए 7-8 मार्च को गुड़गांव में इण्डस्ट्रिलिस्ट के साथ एक समिट रखा था जिसमें 359 के करीब एम.ओ.यू. साईन हुए और 5.84 लाख करोड़ रूपये का निवेश आने वाले समय में प्रदेश में आयेगा जिससे प्रदेश में इण्डस्ट्रीज की ग्रोथ बढ़ने के साथ-साथ बेरोजगार युवकों को रोजगार भी मिलेगा। यह अपने आप में बहुत बड़ा काम है इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। इसी तरह से इस वर्ष डॉ0 भीम राव अम्बेडकर की 125वीं जयंती मनाई जा रही है जो दलितों, पिछड़ों और गरीबों के मसीहा थे। उनके उपलक्ष्य में हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने कई स्कीम्ज

[श्री बलवंत सिंह]

शुरू की हैं जिसके लिए मैं उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की शुरूआत पानीपत से करीबन 8-9 महीने पहले की थी क्योंकि लिंगानुपात में बहुत ज्यादा अंतर आ रहा था। हमारे प्रदेश में एक साल से भी कम समय हुआ है जहां पहले 1000 लड़कों के पीछे 845 लड़कियों का लिंगानुपात था उसमें अब सुधार होकर यह संख्या 900 से ऊपर पहुंच गई है। इससे लगता है कि हमारी सरकार प्रदेश में लिंगानुपात में सुधार करने के लिए कटिबद्ध है और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में इसमें और सुधार आयेगा तथा लिंगानुपात में बराबरी आ जायेगी ।

अध्यक्ष महोदय, आज के समय में हर सरकार यह बात कहती है कि वह किसान हितैषी है। पिछले वर्ष ओलावृष्टि से हरियाणा प्रदेश के किसानों की फसलों को हुए नुकसान की भरपाई हमारी सरकार ने तीन महीने के अंदर 1092 करोड़ रूपये प्रभावित किसानों को वितरित करके यह साबित करके दिखा दिया है कि हमारी सरकार ही सच्चे और सही अर्थों में किसानों की हितैषी सरकार है। हमारी सरकार का यह कार्य पूरे देश में एक एतिहासिक मिसाल है। हमारी सरकार से पूर्व की लगभग सभी सरकारें महज़ किसानों का हितैषी होने का दावा मात्र ही करती थी। उनका काम सिर्फ किसानों के हित में अनेक घोषणायें करने तक ही सीमित था। इसी प्रकार से जब हमारे कपास उत्पादक किसानों की फसल पर सफेद मक्खी का प्रकोप आया तो उसके भी हमारी सरकार ने प्रभावित किसान भाईयों को 967 करोड़ रुपये देने का वायदा किया है। मुझे उम्मीद है कि इस राशि का भी शीघ्रता के साथ वितरण हो जायेगा जिससे प्रभावित किसानों को जल्दी से जल्दी राहत मिलेगी। ऐसे ही मेरे और माननीय स्पीकर साहब के जिले के गन्ना उत्पादक किसानों के बीच यह चर्चा थी कि यमुनानगर में स्थित शूगर मिल बन्द हो जायेगी तो उनका गन्ना कोई नहीं खरीदेगा। विपक्ष के कुछ माननीय साथी हमारी सरकार पर यह इल्ज़ाम लगा रहे थे कि हमारी सरकार यमुनानगर में स्थापित इस मिल को नहीं चला पायेगी। हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक सराहनीय फैसला करके सदा-सदा के लिए ही इस समस्या को हल कर दिया है। हमारी सरकार का यह फैसला आ जाने के बाद ज़मींदार भाईयों का कभी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब गन्ना उत्पादक किसान भाईयों को गन्ने का सही भाव मिलेगा। अगर मिल मुनाफे में होगी तो किसानों को मुनाफा मिल द्वारा दिया जायेगा और अगर किन्हीं परिस्थितियों में मिल को मुनाफा नहीं भी हुआ तो उस स्थिति में सरकार किसानों की ज़रूरी पेमैंट का प्रबन्ध करेगी। इस प्रकार से हमारे गन्ना उत्पादक किसान भाईयों को कभी भी नुक्सान नहीं होगा और उनको उनकी गन्ने की उपज़ का सही और पूरा दाम मिलेगा। इसी प्रकार से चाहे जन धन योजना हो और चाहे पंचायत चुनावों के सम्बन्ध में शिक्षा की मांग को ध्यान में रखते हुए नया कानून बनाकर पंचायत चुनाव सम्पन्न करवाने की बात हो हमारी सरकार ने अनेकों योजनाओं और कामों का क्रियान्वयन देश और प्रदेश के हित को ध्यान में रखते हुए किया है। जब हमारी सरकार ने यहां पर नया पंचायत कानून पास किया तो उस समय बहुत से लोगों ने यहां पर यह चर्चा की थी यह एक गलत कानून है और ऐसा करके सरकार गलत दिशा में जा रही है। जब पंचायत उम्मीदवार के लिए निर्धारित न्यूनतम शिक्षा का कानून यहां से पास हो गया और उसके बाद वह माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए गया तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर लम्बी सुनवाई के बाद अपनी सहमति की मोहर लगा दी। इसके बाद हमारे प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हुए। पंचायत चुनावों का रिजल्ट आने के बाद इस बात का

सभी को अहसास हो गया कि हमारी सरकार ने प्रदेश के दूरगामी हित में यह कितना अच्छा कदम उठाकर कानून बनाने का काम किया क्योंकि इससे बहुत से पढ़े-लिखे लोग चुनाव जीतकर आये। इसमें एक और आश्चर्य की बात यह हुई कि जहां पर सरपंच का पद आरक्षित भी नहीं था वहां पर भी रिज़र्व कैटेगरी के व्यक्तियों ने जीत दर्ज़ की है। इस प्रकार से यह अपने आप में एक मिसाल बनी। इसी प्रकार से हर क्षेत्र में चाहे वह कोई भी क्षेत्र हो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। ऐसे ही आज विकास के नाम पर चाहे कोई भी हल्का हो और चाहे कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो किसी के साथ भी किसी भी मामले में भेदभाव का बरताव नहीं किया जा रहा है। हमारी सरकार "सबका साथ, सबका विकास" के उद्देश्य को साथ लेकर काम कर रही है। अंत में, मैं अपने हल्के की एक ही बात करूंगा। माननीय स्पीकर साहब भी हर रोज़ वहां से जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और उद्योग मंत्री जी से भी मैं यह अनुरोध करूंगा कि मेरा हल्का हिमाचल प्रदेश से सटा हुआ है। हिमाचल प्रदेश का काला अम्ब कस्बा मेरे हल्के के साथ लगता है और वहां पर हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर है। काला अम्ब में बहुत ज्यादा इण्डस्ट्रीज़ लगी हुई हैं। मेरे हल्के से कालाअम्ब हर रोज़ पांच से छ हज़ार पुरूष व महिलायें सुबह से लेकर देर रात तक काम करने के लिए जाते हैं। स्पीकर सर, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि मेरे हल्के में काला अम्ब के साथ लगते ही चार-पांच गांवों की 800-900 एकड़ पंचायती ज़मीन है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वहां पर स्पैशल इण्डस्ट्री ज़ोन बनाया जाये या फिर मेरे हल्के को बैकवर्ड इलाका घोषित करके वहां पर ज्यादा से ज्यादा इण्डस्ट्रीज़ की स्थापना की जाये ताकि जो मेरे हल्के के पुरूष और महिलायें दूसरे प्रदेशों में अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए जाते हैं कम से कम वे दूसरे प्रदेशों में जाने के लिए मज़बूर न हों। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मेरे हल्के के अंदर विशेष इण्डस्ट्री ज़ोन बनाया जाये। मैं यहां पर यह भी बताना चाहूंगा कि उस जगह के साथ मार्किट भी लगता है और इस मार्किट की वहां से दो किलोमीटर की भी दूरी नहीं है। मैं यह बात यहां पर फिर से दोहराना चाहता हूं कि पर्याप्त ज़मीन की भी वहां पर उपलब्धता है। इसलिए वहां पर इसके लिए ज़मीन एक्वायर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अध्यक्ष जी, मेरी आपके माध्यम से सरकार से बार-बार यही प्रार्थना है कि वहां पर स्पैशल इण्डस्ट्री ज़ोन का शीघ्र से शीघ्र निर्माण किया जाये। इसके साथ ही माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि मेरे हल्के में बिलासपुर कस्बे के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पिछले दिनों एक सरकारी कालेज की अनाऊंसमैंट की थी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि बिलासपुर में शीघ्रता से सरकारी कालेज खोलने का प्रबंध किया जाये और सारी की सारी आवश्यक कार्यवाही जल्दी से जल्दी शुरू की जाये ताकि वहां के दो से तीन हज़ार बच्चों को उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए दूर के शहरों में धक्के खाने के लिए मज़बूर न होना पड़े। इसी के साथ मैं माननीय स्पीकर सर का धन्यवाद करता हूं जो उन्होंने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया। धन्यवाद। जय हिन्द।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : स्पीकर सर, अभी श्री बलवंत सिंह जी महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपने विचार प्रकट कर रहे थे। वे एक वरिष्ठ विधायक हैं और सढ़ौरा से दो बार इस महान सदन में विधायक निर्वाचित हुए हैं। उनकी जो बिलासपुर में राजकीय महाविद्यालय खोलने की बात है वह पूरी तरह से सही है। सरस्वती नदी भी चौधरी बलवंत सिंह जी के हल्के से बहती है और इनके हल्के में सरस्वती का 20 किलोमीटर लम्बा

[श्री रामबिलास शर्मा]
हिस्सा आता है। हमने वहां पर 8 फुट गहरी खुदाई करके सरस्वती रहस्य को प्रकट किया है। लोगों को इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था इसके बावजूद भी हमने इस रहस्य को उजागर किया है। जब-जब हम सरस्वती दर्शन के लिए वहां पर गये हैं तो बलवंत सिंह जी वहां पर हमारे साथ रहे हैं। मैं बलवंत सिंह जी को यह बात बताना चाहूंगा कि उनका जो बिलासपुर में महाविद्यालय खोलने का मामला है हमने उसके ऊपर काम शुरू कर दिया है।

श्री बलकौर सिंह : **(कालांवाली) (एस.सी.)** : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपने विचार प्रकट करने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं शिक्षा पर अपनी बात रखना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, आम लोगों के बीच यह भावना नहीं मिल रही है कि सरकार शिक्षा के प्रसार के लिए प्रयासरत है। आज प्रदेश में किसी भी स्कूल की बिल्डिंग सही नहीं है। जहाँ "बेटी-बचाओ-बेटी-पढ़ाओं" का नारा सरकार की तरफ से लाया जाता है वहीं पर मेरे अपने गांव में लड़कियों के स्कूल में अभी तक शौचालय नहीं है और न ही उस स्कूल की चारदीवारी है। वहाँ पर अध्यापकों की भी बहुत भारी कमी है तथा सफाई कर्मचारी भी नहीं है। मेरे हल्के में बहुत सारी कमियाँ देखने को मिल रही हैं। शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए स्कूलों में अध्यापकों की कमी को दूर करना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, जब माननीय मुख्यमंत्री जी सिरसा गये थे तो उन्होंने मेरे हल्के में एक कॉलेज की घोषणा की थी और काफी लम्बे अर्से से यह हमारी मांग भी रही थी क्योंकि मेरे हल्के कालांवाली में 50-55 गांव हैं और वहाँ पर कोई कॉलेज नहीं है। लड़के तथा लड़कियों को पढ़ने के लिए 50-50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। मुख्यमंत्री जी की घोषणा हो चुकी है लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई ऐसे प्रयास नजर नहीं आये जिससे यह लगे कि कॉलेज बनवाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है। बहुत से ऐसे गांव भी हैं जहाँ पर वॉटर वर्क्स तक पानी पहुंचाने वाली नालियाँ भी बंद हो चुकी हैं। मेरे अपने गांव कालांवाली में जब नहर बंद हो जाती है और जमींदार जिन खालों से खेतों में पानी लगाते हैं उन्हीं खालों में से वॉटर वर्क्स में पानी पहुंचाया जाता है। इस प्रकार से पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है। विशेष तौर से मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि गांव के वॉटर वर्क्स में सफाई नहीं हो पाती है। कल भी सदन में यह प्रश्न उठा था कि वॉटर वर्क्स की सफाई कब होती है, कब दवाई डाली जाती है लेकिन अभी तक इसका जवाब नहीं मिला है कि सरकार वॉटर वर्क्स की सफाई कब करवाती है। अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र में हर गांव में पीने के पानी के लिए आर.ओ. सिस्टम लगाने का वादा मंत्री जी द्वारा किया गया था। गांवों की लिस्ट भी मांगी गई थी और मैंने वह लिस्ट भी पहुंचा दी थी लेकिन अभी तक यह नहीं लगता कि सरकार की तरफ से गांवों में आर.ओ. सिस्टम लगाने का क्या प्रोग्राम है? आर.ओ. सिस्टम लगाने भी हैं या नहीं लगाने इसका जवाब भी नहीं दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, गर्मी का मौसम आ गया है और इस मौसम में ढाणियों में बिजली और पानी की सख्त जरूरत होती है। सरकार ने पहले भी बयान दिया था कि ढाणियों में हम बिजली जरूर देंगे। हरियाणा में सिरसा जिले में सबसे अधिक ढाणियाँ हैं लेकिन अभी तक ऐसा नहीं लगता कि ढाणियों में बिजली पानी देने की सरकार की कोई मंशा है, जबकि 16.00 बजे यह आने वाले समय में बड़ी जरूरी है। स्वास्थ्य के बारे में मैं पहले भी सवाल ले कर आया था, इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि जो शिक्षा विभाग का हाल है उससे बुरा हाल स्वास्थ्य विभाग का है। स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों की कमी है। सरकार द्वारा जो स्वच्छ भारत का नारा लगाया जाता है वह कैसे पूरा होगा?

एस0वाई0एल0 नहर के लिए अधिगृहीत की गई भूमि की अधिसूचना रद्द करने पर पंजाब विधान सभा द्वारा पारित किए गए विधेयक पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गए यथा स्थिति के आदेश के संबंध में मुख्य मंत्री द्वारा घोषणा।

मुख्यमंत्री(श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को एक जानकारी देने के लिए खड़ा हुआ हूं। सुप्रीम कोर्ट में आज जो एस.वाई.एल. कैनाल से संबंधित केस था उस केस में एक जानकारी है कि पंजाब सरकार ने एस.वाई.एल. कैनाल के लिए अधिग्रहित की गयी जमीन को डिनोटीफाई करने के संबंध में जो बिल पारित किया था उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है। इसके अलावा उन लोगों ने बनी हुई एस.वाई.एल. नहर को तोड़ने के लिए जिस प्रकार के क्रिया कलाप शुरू कर दिये थे उसको स्टेटस-क्वाँ डिक्लेयर किया है और पंजाब डी.जी.पी., पंजाब चीफ सैक्रेटरी तथा पंजाब सैक्रेटरी, होम को पर्सनली यह हिदायत दी है कि इस सारे केस के वह जिम्मेवार होंगे और उनको इस केस का रिसीवर बना दिया गया है (इस समय मेजें थपथपाई गई।)

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भ

श्री बलकौर सिंह : स्पीकर सर, मेरे हल्के में तीन पी.एच.सी. पड़ती हैं जिनमें कोई भी महिला डॉक्टर नहीं है। अगर कोई डिलीवरी केस आता है तो उसको सीधा सिरसा के हॉस्पीटल में या पी.जी.आई.,रोहतक रैफर कर दिया जाता है जो कि बड़ा मुश्किल होता है। दादू गांव में चौटाला सरकार के समय में एक पी.एच.सी. बनाई गई थी जिसका अब इतना बुरा हाल है कि बिजली तक का भी प्रबन्ध नहीं है । एक बार उस पी.एच.सी. में एक डिलीवरी केस आया वहां बिजली न होने के कारण मोबाईल फोन की लाईट में उस डिलीवरी केस को हैंडल किया गया जो कि सरकार के लिए बड़ी शर्म की बात है क्योंकि इस के लिए संजीदगी दिखानी बहुत जरूरी है। दूसरी बात मैं गऊ संरक्षण के बारे में कहना चाहूंगा कि गऊओं के लिए गऊशालाएं बनाई जाएं ताकि गऊओं का रखरखाव अच्छी तरह से किया जा सके। इसमें मेरा एक सुझाव भी है कि हर गांव में पंचायती जमीन पड़ी हुई है और उसमें यह जरूरी नहीं है कि उसके लिए 8-10 एकड़ जमीन ही चाहिए। 4-5 एकड़ जमीन में भी गऊशालाएं बन सकती हैं और हर गांव और हर नगर उस गऊशाला को चलाने के लिए तैयार है। मण्डी कालांवाली में एक गऊ अस्पताल चल रहा है जिसमें कम से कम 5 किलोमीटर दूर के गांव भी जख्मी गऊओं को उस अस्पताल में लेकर आते हैं और वह अपने खर्चे से ही उनका ईलाज करते हैं उन्होंने ऑप्रेशन थियेटर खुद बनाया हुआ है। स्पीकर सर, वह अस्पताल लोगों की सहायता से चल रहा है। सरकार की तरफ से अभी तक उस अस्पताल के लिए कोई भी सहायता मुहैया नहीं कराई गई है। वह अस्पताल प्राईवेट जगह पर चल रहा है। मेरा सरकार से निवेदन है कि उस अस्पताल के लिए कोई जगह मुहैया कराकर उस अस्पताल को बड़ा बनाया जाए तभी उस सारे एरिया की समस्या हल हो सकती है। पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी वहां गये थे और हमारी कॉलेज की डिमांड को पूरा करने की घोषणा की थी और उसके साथ इन्होंने कालांवाली में एक बस स्टैंड बनाने की बात भी की थी लेकिन अभी तक वह भी नहीं बनाया गया है। हमारे क्षेत्र की बहुत सारी मांगे हैं जो 12 साल से चली आ रही हैं। पीने के पानी से लेकर सड़कों, कॉलेज और अस्पताल तक बनाने की अगर सरकार की मन्सा हो तो हमारे क्षेत्र की सारी मांगों को पूरा करने की कोशिश की जाए । इसी के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मैं सरदार बलकौर सिंह जी से विनती करूंगा कि जिन स्कूलों की बुरी हालत इन्होंने बताई है खासकर जो लड़कियों के स्कूल हैं जहां पर चारदीवारी नहीं है या शौचालय नही हैं उनके नाम मुझे लिख कर दे दें उन पर हम बहुत जल्दी कार्रवाही करेंगे।

श्री हरि चन्द मिढ्ढा : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो अगर मैं अपनी सारी बातें यहां सदन के सामने कहूंगा तो बहुत समय लग जाएगा जिससे बाकी जो सदस्य यहां बैठे हैं वे बोले बगैर रह जाएंगे। मैं चाहता हूं कि आपने मुझे जो एक मिनट का समय बोलने के लिए दिया है उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। मैं अपनी मांगों के बारे में बताते हुए यह कहूंगा कि हमारे क्षेत्र की जो पहली मांग है वह पीने के पानी की है जिसकी शहर में बहुत कमी रहती है। दूसरी समस्या सीवरेज की है जिसकी जर्जर अवस्था हो चुकी है। तीसरी समस्या सड़कों की है उनकी बहुत बुरी हालत है। चौथी समस्या जींद शहर में बाई पास न होने की है। मेरी पांचवी डिमांड यह है कि जीन्द से सभी प्रमुख धार्मिक स्थानों जैसे हरिद्वार आदि के लिए बसें जरूर चलाई जायें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि आज आप बहुत खुश लग रहे हो, मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे हल्के के लिए इतना कुछ दे दो कि कभी मांगने की जरुरत ही न पड़े। आपकी सरकार आने के बाद जीन्द में पैंडिंग पड़े केसिज पर कार्रवाई होनी शुरु हो गई हैं। ऐसा लगता है कि हमने भी कोई तपस्या, साधना या भक्ति की होगी जो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल के रूप में हमें प्रदेश का मुख्यमंत्री प्राप्त हुआ है। (इस समय मेजें थपथपाई गई)

श्री अध्यक्ष: मिढ्डा साहब, तपस्या, साधना और भक्ति तो अब भी कर रहे हो। (हंसी)

श्री रामचन्द कंबोज (रानिया): अध्यक्ष महोदय, जो आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। सबसे पहले मैं कृषि के विषय पर बात करूंगा। हमारा भारत वर्ष एक कृषि प्रधान देश है। राज्यपाल के अभिभाषण में निहित है कि किसानों के लिए उत्तम किस्म के बीज उपलब्ध होंगे तथा अन्य तमाम बातें इस अभिभाषण के माध्यम से कही गई। मैं इन सब बातों से उपर उठकर एक सुझाव देना चाहता हूँ कि कृषि के क्षेत्र में जो उत्पादन है चाहे गेहूं है या चावल है, वह फर्टिलाईजर तथा विभिन्न प्रकार के स्प्रे की वजह से इतना जहरीला हो गया है कि 99 प्रतिशत बीमारियां खाद्यान के जहरीलेपन की वजह से आ रही हैं। अभी दो दिन बाद बजट पेश किया जायेगा तो इस परिपेक्ष्य में मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि बजट में आर्गेनिक्स प्रोडक्शंज पर पूरा सोच-विचार किया जाये। अगर आर्गेनिक्स उत्पादन होगा तो पूरे देश व प्रदेश को खाने के लिए स्वच्छ और साफ उत्पादन सुलभ हो सकेगा और पूरे विश्व में देश की अलग पहचान बनेगी। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण ने शिक्षा पर अपनी वचनबद्धता जाहिर की। किसी भी समाज, प्रदेश या देश की अगर नींव मजबूत होगी तो निश्चित रूप से वह देश और समाज मजबूत होगा। आज जो देश में शिक्षा का हाल है उससे आप सब वाकिफ हैं। इस संबंध में अपने हल्के की समस्या को भी साथ जोड़ूंगा। मेरे हल्के में किसी भी प्रकार का कोई कॉलेज नहीं है। लड़कियों को शिक्षा के लिए 60-70 किलोमीटर बस में बैठकर जाना पड़ता है। उनके लिए कोई अलग से बस का भी प्रावधान नहीं है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी सिरसा गये थे तो इन्होंने रानिया में कॉलेज खोलने की घोषणा भी की थी। मेरा निवेदन है कि आने वाले बजट में इस कॉलेज के लिए भी राशि का प्रावधान करते

हुए कॉलेज निर्माण का कार्य जल्द से जल्द शुरू करवाया जाए ताकि बच्चों को शिक्षा के लिए दूर-दराज के क्षेत्रों में न जाना पड़े और शिक्षा का आधार मजबूत हो सके। जहां तक स्कूलों की दशा व उनके अपग्रेडेशन की बात है तो माननीय शिक्षा मंत्री के कहे अनुसार की उनकी लिस्ट बनाकर उन्हें उपलब्ध करा दें, मैं इस संबंध में लिस्ट बनाकर उन तक पहुंचा दूंगा। इसके अतिरिक्त महामहिम राज्यपाल महोदय ने ग्रामीण विकास व पंचायतों के लिए भी अपने अभिभाषण में जिक्र किया था। इस संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सी म्यूनिसिपल कमेटियों के साथ लगती जो ढ़ाणियां हैं यहा रहने वाले लोग जब अपने काम के लिए म्यूनिसिपल कमेटियों में जाते है तो म्यूनिसिपल प्रशासन द्वारा यह कहकर टाल दिया जाता है कि आपकी यह ढ़ाणियां उनके क्षेत्राधिकार से बाहर हैं। इसकी वजह से इन ढ़ाणियों में न तो पानी, बिजली की और न ही रास्तों की व्यवस्था बेहतर ढंग से हो पाती है। स्कूल जाने वाले बच्चों को इन समस्याओं की वजह से बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस तरह की समस्या केवल मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में ही नहीं है। मैंने इस ढ़ाणियों की पंचायत के लिए भी एक रिजोल्यूशन डाला हुआ है। मेरा निवेदन है कि इन ढ़ाणियों के लिए कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए कि जो म्यूनिसिपल कमेटियों के साथ ढ़ाणियां लगती हैं उनके रहने वाले लोगों के सामने कोई दिक्कत न आने पाये। इन ढ़ाणियों के वोट को वार्ड के तहत शहरी म्यूनिसिपल कमेटियों के लिए डलवा तो लिया जाता है लेकिन व्यवस्था के नाम पर इन ढ़ाणियों को दिया कुछ नहीं जाता है।

अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था कि 'सबका साथ सबका विकास' यह सुनकर बड़ा अजीब लगता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में पहली बार पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई है। हमें लगा यह सरकार कुछ अलग से काम करेगी, मगर जब सरकार की व्यवस्थाओं को देखते हैं तो बड़ा अजीब लगता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी ने आपसे और श्री बलकौर जी से भी कामों की सूची मांगी है। हम जब विपक्ष में होते थे, तो हमसे कभी भी सत्ता पक्ष के मंत्री ने कामों की सूची नहीं मांगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम चन्द कम्बोज: अध्यक्ष महोदय, मैं वही बात आपके माध्यम से सदन में बता रहा हूँ कि जनता ने पिछले 10 साल के शासनकाल को अच्छी तरह से देखा है कि प्रदेश के अंदर कितने विकास के काम हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, यदि हम 'सबका साथ सबका विकास' के बैकग्राउंड पर जाये तो प्रदेश की जनता अच्छी तरह बता देगी कि कितने विकास के कार्य इस सरकार में हुए हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सिरसा जिले के सरकारी अस्पतालों में ना तो वेंटिलेटर की मशीनें हैं और ना ही कैंसर, हैपेटाइटिस-'बी' व 'सी' जैसी खतरनाक बीमारियों की जांच करने के लिए कोई लेबोरेट्री है। उद्योग के क्षेत्र में हमारा सिरसा जिला पिछड़ा हुआ है। मैं इस बात को मानता हूँ कि हमारा सिरसा जिला बैकवर्ड एरिया में आता है। इस जिला को स्मार्ट सिटी तो नहीं बनाया जा सकता लेकिन इसके शहरों को डवैल्प करने के लिए सरकार का अलग से बजट का प्रोविज़न करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इस समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय सदन में उपस्थित नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सिरसा में जनसभा के दौरान कहा था कि विधायक तो केवल 5 करोड़ रूपये विकास के लिए देने की मांग करते हैं जबकि उन्होंने मेरे क्षेत्र को 25 करोड़ रूपये दिए हैं। अध्यक्ष महोदय, हमने जो कामों की प्रपोजल भेजी थी उसमें से कोई भी काम नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष: कम्बोज जी, विकास के काम तो आपके क्षेत्र में भी हुए होंगे ।

श्री राम चन्द कम्बोज: अध्यक्ष महोदय, आप चैक करवा सकते हैं कि मेरे हल्के में क्या-क्या काम हुए हैं। मैं जनता का चुना हुआ नुमाइंदा हूँ। सरकार के कार्यकाल का दूसरा वर्ष चल रहा है, सरकार कहती है कि 10 करोड़ रुपये के विकास के कार्य हो चुके हैं। लेकिन मुझे इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं कि कौन-कौन से विकास के कार्य हुए हैं। अगर मुझे अपने हल्के के विकास कार्यों की जानकारी होगी तो मैं जनता के बीच में जाकर विकास के कार्यों को गिनवा सकता हूं। इस तरह से कांग्रेस शासनकाल के दौरान किए गए कार्यों और भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा किए गए विकास के कार्यों में कोई भी फर्क नजर नहीं आता है। (शोर एवं व्यवधान) क्षेत्र के विकास के कार्यों के सूची दी जा चुकी है ।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू: अध्यक्ष महोदय, पहले भी विकास कार्यों की सूची दी जा चुकी है, उसका क्या हुआ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम चंद कम्बोज: अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में सबसे बड़ी समस्या बिजली को लेकर रहती है। ढाणियों में बिजली नहीं आती है। जिसके कारण बच्चे रात को पढ़ नहीं पाते हैं। प्रदेश में बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं होगी तो प्रदेश का भविष्य कैसे संवरेगा? अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ सामान्य बात बता रहा हूं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कम्बोज जी, मैं यह तो नहीं कह रहा हूं कि आप सरकार के खिलाफ बोल रहे हो लेकिन हमें सभी सदस्यों को बोलने का समय निश्चित करना होता है और निश्चित समय अवधि से अधिक समय तक बोलने की मैं किसी भी सदस्य को इजाजत नहीं दे सकता। (विघ्न)

श्री रणधीर सिंह कापड़ीवास : अध्यक्ष महोदय, सदन में उपस्थित सभी सदस्यों को माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देनी चाहिए क्योंकि आज एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। मैं आपको दो लाइन सुनाना चाहूंगा ... (विघ्न)

श्री राम चन्द कम्बोज : अध्यक्ष जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र रानिया की सबसे बड़ी समस्या रानिया-कुत्तावड़ के पुल से संबंधित थी । मेरा यह प्रश्न भी लगा हुआ था मगर उस पर डिस्कशन नहीं हो पाया। इस संबंध में मैंने लोक निर्माण मंत्री राव नरबीर सिंह से भी बात की है। लगभग 15-16 गांव घग्गर नदी के दूसरी तरफ पड़ते हैं। उन गांवों के लोगों को अपनी सब्जी वगैरह बेचने के लिए या तो ऊपर से घूमकर जाना पड़ता है या कम से कम 20-25 किलोमीटर लम्बा रास्ता तय करके जाना पड़ता है या फिर उनको सिरसा जाना पड़ता है। मेरी यही अपील थी कि इन 15-20 गांवों के लोगों को अपने रोजाना के कार्य करने और बच्चों को स्कूल-कॉलेज जाने के लिए कई किलोमीटर का फासला तय करके जाना पड़ता है। मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए 16 करोड़ 33 लाख रूपये देने की भी घोषणा की हुई है और इसका प्रपोजल भी तैयार कर रखा है। (विघ्न)

लोक निर्माण मंत्री (राव नरबीर सिंह) : अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम इस पुल को अगले साल बना देंगे ।

श्री राम चन्द कम्बोज : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय लोक निर्माण मंत्री राव नरबीर सिंह को मेरे विधान सभा क्षेत्र की मांग संबंधी आश्वासन देने के लिए धन्यवाद करता हूं। (विघ्न)

श्री सुभाष सुधा (थानेसर) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे गवर्नर एड्रैस पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। इसके साथ मैं कहूंगा कि हमारी सरकार ने "सबका साथ सबका विकास" का नारा दिया। हमारी सरकार पूरे प्रदेश में समान विकास करना चाहती है। हमारी सरकार हर बीस किलोमीटर पर एक महिला कॉलेज स्थापित करने जा रही है और इसके साथ-साथ हर डिस्ट्रिक्ट में एक महिला थाना खोल रही है। हमारी सरकार ने पढ़ी-लिखी पंचायत बनाई है। इसके बारे मैं कहूंगा कि सरपंच, जिला परिषद और ब्लॉक समिति के मैम्बर इतने पढ़े-लिखे हैं कि वे मेरे पास जे.ई.ई. से नक्शा पास करवाकर लाते हैं और बताते हैं कि हम क्या-क्या डिवैल्पमैंट अपने गांवों में करना चाहते हैं। पढ़ी-लिखी पंचायत का चुनाव करने के लिए मैं हरियाणा सरकार को धन्यवाद करूंगा। इसी के साथ मैं सदन को बताना चाहूंगा कि कुछ सप्ताह पहले असामाजिक तत्वों ने किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश की सुव्यवस्था को बिगाड़ा। आदरणीय मंत्री नायब सिंह सैनी, माननीय सदस्य डॉ पवन सैनी और माननीय सदस्य श्री नरेश कौशिक ने किसानों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की। इसके साथ-साथ हरियाणा में जहां-जहां असामाजिक तत्वों ने हमारे व्यापारियों पर अत्याचार किये और उनकी सम्पत्ति का नुकसान किया हमने उन स्थानों का भी दौरा किया है। हम रोहतक, झज्जर, गोहाना आदि सब जगह का दौरा करने गए। मैं पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए हरियाणा सरकार का धन्यवाद करता हूँ। मैं एक और मांग करूंगा कि जिन लोगों की दुकानें वगैरह जल गई हैं उनको मुआवजे के साथ-साथ एक-एक नौकरी भी अवश्य दी जानी चाहिए। मुझे क्षेत्र के दौरे के दौरान एक लड़का मिला जिसने मुझे बताया कि मैंने बुजुर्ग माता-पिता की सेवा करने के लिए अपनी नौकरी छोड़कर एक छोटी-सी दुकान खोली थी परंतु उसे असामाजिक तत्वों ने मेरी दुकान को जला दिया। उसने कहा कि अब चाहे मुझे मुआवजा भी मिल जाए लेकिन मैं अपने माता-पिता को छोड़कर किसी दूसरे शहर में चला जाऊंगा या फिर कोई छोटी-मोटी नौकरी कर लूंगा। आज यहां पूरा सदन बैठा है। इसके लिए आप उसकी मदद करें और उसे नौकरी देने की कृपा करें। मैं चाहूंगा कि व्यापारियों को मुआवजे के साथ-साथ एक नौकरी भी दी जानी चाहिए। आदरणीय सदस्य सरदार जसविन्द्र सिंह संधू ने सदन को बताया कि 1947 में 10 लाख पंजाबी हिंदू शहीद हुए और उन्होंने प्रदेश में जिस प्रकार से मेहनत करके दुकानों बनाई और रोजगार पैदा किया, यहां पर छोटी-छोटी रेहड़ियां लगाई और अनेक छोटे-छोटे कार्य किये वह तारीफ के काबिल है। जो दुकानदार असामाजिक तत्वों के भय से डरे हुए हैं और दुकान नहीं करना चाहते उनके बच्चों को नौकरी दी जाए। मैं कहूंगा कि 7-8 मार्च को गुडगांव में जो हरियाणा ग्लोबल इन्वैस्टर्स समिट हुआ उसमें 5.84 लाख करोड़ रूपये की इन्वैस्टमैंट के लिए एग्रीमैंट हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, कुरूक्षेत्र पिछड़ा हुआ इंडस्ट्रियल एरिया है इसलिए यदि यहां पर भी कुछ इन्वैस्टमैंट लाई जाती है तो मैं इसके लिए मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करूंगा। हमारे देश में लड़कियों की संख्या दिन प्रतिदिन गिर रही थी इसलिए हमारी सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं अभियान चलाया है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री महोदय ने इस दिशा में हमें पानीपत से मार्गदर्शन दिया। जो लिंगानुपात 835 था वह आज बढ़कर 900 तक पहुंच गया है इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, इंसान को अपनी सोच बदलनी चाहिए। मैं एक बात आप सबके साथ जरूर सांझा करना चाहूंगा। मेरी इच्छा थी कि हमारी बेटी हो। मेरी पत्नी जब होस्पिटल में थी और लड़की पैदा हुई थी तो मैने होस्पिटल में जितनी भी नर्सें और स्टाफ था सबको मिठाईयां और कपड़े बांटे। जब उन नर्सो ने मुझसे पूछा कि आपको पता है कि आपके यहां बेटा पैदा हुआ है या बेटी तो मैंने कहा कि

[श्री सुभाष सुधा]

हां मुझे पता है कि मेरी बेटी हुई है इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इंसान को इस तरफ अपनी सोच बदलनी चाहिए। हरियाणा सरकार ने किसानों की खराब हुई गेहूं की फसल के मुआवजे के लिए एक लाख 92 करोड़ रूपये की राशि दी है तथा सफेद मक्खी के प्रकोप से हुई खराब फसल का 967 करोड़ रूपये का मुआवजा दिया है जिसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, कुरूक्षेत्र गीता की स्थली है और यहां हर साल गीता जयंती का आयोजन किया जाता है। इस बार 36 वर्ष के बाद पहली बार गीता जयंती के अवसर पर प्रतिदिन करीबन एक लाख लोग पहुंचे हैं। यहां 15 करोड़ रूपये का बिजनैस हुआ है। मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की है कि कुरूक्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर गीता जयंती का आयोजन किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, सरस्वती धरोहर बोर्ड के निर्माण के लिए भारत सरकार ने हमारे कुरूक्षेत्र शहर को 100 करोड़ रूपये दिए हैं जिसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा। हमारे कुरूक्षेत्र को कृष्णा सर्किट में शामिल किया गया है। कुरूक्षेत्र के ज्योतिसर, बाणगंगा और नरकातारी आदि तीर्थों के लिए भी भारत सरकार ने हमें 100 करोड़ रूपये देने का वायदा किया है। इसके लिए प्रपोजल बन कर चली गई है और शीघ्र ही यह पैसा आ जाएगा। इसके लिए मैं भारत सरकार का, मुख्यमंत्री महोदय का और टूरिज्म मिनिस्टर का धन्यवाद करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगा कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत कुरूक्षेत्र को सुंदरता और सफाई की दृष्टि से नम्बर एक शहर चुना गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि हमारे यहां जो सोलिड वेस्ट मैनेजमैंट प्लांट और सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट मंजूर हो चुके हैं, उन दोनों प्लांटों को जल्दी से जल्दी लगाया जाए। कुरूक्षेत्र शहर में कुरूक्षेत्र यूनीवर्सिटी है और यह पूरे हिन्दुस्तान में 10 वें नम्बर पर है और गेम्ज में यह तीसरे स्थान पर है, मैं चाहता हूं कि इसको सैंट्रल यूनीवर्सिटी का दर्जा दिया जाए। पिछली सरकार में सोनीपत में भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय और रोहतक में एम.डी. यूनीवर्सिटी में यूनीवर्सिटी कॉलेज को डिपार्टमैंट का दर्जा दिया गया था, मैं चाहता हूं कि कुरूक्षेत्र यूनीवर्सिटी में भी यूनीवर्सिटी कॉलेज को विभाग का दर्जा दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, शाहबाद में हॉकी का एस्ट्रोटर्फ है, वहां इंटरनैशनल खिलाड़ी आते हैं इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे शहर कुरूक्षेत्र में भी हॉकी का स्टेडियम बनाकर उसमें एस्ट्रोटर्फ बनाया जाए। इसके अतिरिक्त मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की थी कि कुरूक्षेत्र के अंदर बहुत ज्यादा टूरिस्ट आते हैं इसलिए वहां पर सरकार की तरफ से भोजन की व्यवस्था की जानी चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने वहां पर 20 रूपये थाली के हिसाब से सत्कार भोजन शुरू किया है जिसमें खाने के लिए चावल, रोटी, दाल और सब्जी मिलती है। मैं पूरे सदन से आग्रह करता हूं कि जब भी कोई माननीय सदस्य वहां आये तो सत्कार भोजन जरूर करके आयें। अंत में मैं गवर्नर साहब के अभिभाषण का समर्थन करता हूं और कहना चाहूंगा कि-

गीता धर्म नहीं, जीने की शैली है।

जो संघर्ष का रास्ता है, जो सफलता की और ले जाता है।

श्री रणधीर सिंह कापड़ीवास (रेवाड़ी) : अध्यक्ष महोदय, मैंने कल केवल एक कविता सुनाई थी सदन का ज्यादा समय नहीं लिया था और आपने मान लिया कि मेरी डिबेट पूरी हो गई। अध्यक्ष महोदय, आज मैं बहुत खुश हूं, मैं अपने हल्के की कोई मांग नहीं रखना चाहता।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एस.वाई.एल. को लेकर हमारे पक्ष में जो डिसीजन दिया है वह अपने आप में एतिहासिक फैसला है। यह तभी संभव हो पाया है जब हमारे मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने इसकी प्रोपर पैरवी की है। इसके लिए मैं पूरे सदन को बधाई देना चाहता हूं। हमारे नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि यह करना चाहिए वह करना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे हक में आ गया है इसके लिए फिर से सभी को बहुत-बहुत बधाई। यह पूरे सदन का प्रयास है और दर्शकों का आशीर्वाद है। पंजाब हमको कमजोर समझता था। जो शराफत को कमजोरी समझते हैं वे बुरी तरह से मार खाते हैं। दबंगई व अहंकार में जीनेवाले औधे मुंह गिर जाते हैं। हमारे मुख्यमंत्री की शराफत व धैर्य को कोर्ट ने ठीक जाना है और सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा की मांग को ठीक माना है। अब अच्छे दिन आयेंगे। रावी ब्यास का मिलेगा पानी क्योंकि सभी दलों ने मिलकर दिल से यही बात है मानी। धन्यवाद। (विघ्न)

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू: स्पीकर सर, हमारे दल के कई सदस्य भी अभी बोलना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : संधू साहब, आपकी पार्टी का एक भी मैंबर बिना बोले नहीं रहेगा। आप चिंता मत करो।

परिवहन मंत्री (श्री कृष्ण लाल पंवार) : अध्यक्ष महोदय, कापड़ीवास जी ने बहुत अच्छी कविता सदन में सुनाई है और एस.वाई.एल. के बारे में बोले हैं। इन्होंने कोई मांग नहीं रखी लेकिन मैं इनको बताना चाहूंगा कि इन्होंने पहले रेवाड़ी में सैक्टर-12 में बस स्टैंड बनाने के बारे में कहा था वह बात हमने मान ली है और वहां पर बस स्टैंड जल्द ही बनाया जायेगा।

डॉ. पवन सैनी (लाडवा) : माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया सबसे पहले तो मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। हमारे प्रदेश के बहुत ही तेजस्वी और तपस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक क्षेत्रों समेत प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए "सबका साथ और सबका विकास" और "हरियाणा एक, हरियाणवी एक" के सिद्धांत को लेकर चल रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री पूरे हरियाणा प्रदेश के विकास को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और वचनबद्ध हैं। पिछले 7 और 8 मार्च को जो गुड़गांव में इंवैस्टर समिट आयोजित की गई थी उसमें 359 समझौते हुए थे और जिनके अनुसार 5 लाख 84 हज़ार करोड़ रूपये का निवेश हरियाणा प्रदेश में होगा। इसके अलावा इस सत्र में हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन बिल प्रस्तुत किया जायेगा। इसके कारण हमारे नौजवानों को रोज़गार तो मिलेगा ही इससे हरियाणा प्रदेश भी प्रगति की ओर अग्रसर होगा। जो पिछली सरकारों द्वारा हरियाणा प्रदेश के अंदर क्षेत्रवाद का जहर फैलाया गया हमारी सरकार ने उसको हरियाणा प्रदेश से पूरी तरह से समाप्त करने का कार्य आरम्भ किया है। हमारी सरकार के प्रयासों से हरियाणा प्रदेश से निंदाजनक क्षेत्रीय असंतुलन सदा-सदा के लिए समाप्त हो जायेगा। इससे पूरे प्रदेश में एक क्रांतिकारी बदलाव आयेगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने लाईसैंसशुदा कालोनियों के मानदण्ड़ों को तर्कसम्मत बनाने के लिए योजना बनाई है। इसी के साथ-साथ दीन दयाल आवास योजना की भी शुरूआत की है जिससे हरियाणा प्रदेश के गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों

[डॉ. पवन सैनी]

के लिए सस्ते आवासों का निर्माण किया जायेगा। हमारी राज्य और केन्द्र सरकार ने संविधान के शिल्पी भारत रत्न डॉ0 भीम राव अम्बेडकर की 125वीं जयंती मनाने का फैसला किया है। डॉ. भीम राव अम्बेडकर जी हमारे देश के शोषितों और पीड़ितों के मसीहा थे। हमारी सरकार के ऐसे आयोजन से पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक समानता का संदेश जायेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के शासन के दौरान 25 जून, 1975 से लेकर 21 मार्च, 1977 तक एक काला अध्याय लिखा गया था। इसके दौरान जिन लोगों को शारीरिक और मानसिक तौर पर प्रताड़ना दी गई थी उन लोगों को 26 जनवरी को ताम्र पत्र देकर सम्मानित किया गया है। "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" के आंदोलन को एक जन अभियान बनाकर इस बुराई पर अंकुश लगाने का काम किया है। हमें माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से इस अभियान में कामयाबी मिली है इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय की माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नारी शक्ति पुरस्कार "कणकी देवी" के नाम से देने का काम किया । हमारी सरकार धरती पुत्र किसान के साथ हर समय कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। जब पिछले दिनों बेमौसमी बरसात व ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसलें खराब हुई तो यह पूरे हिन्दूस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है कि पीड़ित किसानों को 1092 करोड़ रूपये की मुआवज़ा राशि का वितरण किया गया। इससे पहले हरियाणा प्रदेश की सरकारें किसानों की फसल के खराब हो जाने के कारण उनको 3 रूपये, 5 रूपये, 15 रूपये, 21 रूपये और 45 रूपये की मुआवज़ा राशि देकर किसानों के साथ भद्दा मज़ाक किया जाता था। आढतियों से हमारे किसानों को बाद में उनकी फसल की पेमैंट हुई लेकिन हमारी सरकार ने पीड़ित किसानों को मुआवज़ा पहले वितरित किया। इसी प्रकार से सफेद मक्खी के कारण जिन कपास उत्पादक किसानों की कपास की फसल बर्बाद हो गई थी उनको भी 967 करोड़ रूपये की मुआवज़ा राशि दी गई है। मैं इस बारे में यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से अभी कुछ दिन पहले ही बेमौसमी बरसात और ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं उसकी भी गिरदावरी करवाकर प्रभावित और पीड़ित किसानों को भी उनकी बर्बाद हुई फसल का उचित मात्रा में मुआवज़ा जल्दी से जल्दी दिया जाये। जिस प्रकार से पिछले साल चीनी सस्ती हुई तो शूगर मिल्ज़ ने किसानों को उसकी गन्ने की पेमैंट देने से मना कर दिया उससे हमारे प्रदेश के किसानों को इस बात की चिंता हुई। हमारी सरकार ने प्रदेश की शूगर मिल्ज़ को अतिरिक्त आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई और कहा कि किसान के गन्ने की पाई-पाई की पैमैंट की जाये। माननीय प्रधान मंत्री जी जिन्होंने हिन्दुस्तान की स्वतंत्रता की 75वीं जयंती पर वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुणी करने की घोषणा की इसका भी मैं स्वागत करता हूं। हरियाणा प्रदेश के लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी भी बैंक में जाने का अनुभव प्राप्त नहीं किया था लेकिन जन धन योजना के तहत 15 जनवरी, 2016 तक लगभग 52 लाख 58 हज़ार खाते खुल चुके हैं जिसके कारण 1112 करोड़ रूपये की राशि जमा हुई है। हरियाणा सरकार ने सरस्वती धरोहर बोर्ड का गठन किया है और इस बोर्ड के तहत सरस्वती महोत्सव मनाकर एक यात्रा निकाली गई और पेहवा में उस यात्रा का समापन हुआ था। उस यात्रा के समापन अवसर पर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2018 में सरस्वती महोत्सव को राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का निर्णय लिया उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। यह यात्रा आदिबद्री से चली थी और रास्ते में जी.टी. रोड पर मेरे हल्के का

एक गांव बीड़-पिपली है वहाँ भी सरस्वती नदी की धारा है जहाँ पर उस दिन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। मेरा मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि वहाँ पर भी एक मंदिर बना कर उसको एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाये। अध्यक्ष महोदय, गौ-संरक्षण एवं गौ-संवर्धन विधेयक आने से गाय के प्रति लोगों में श्रद्धा बढ़ी है और केन्द्र से भी इसके लिए 78 करोड़ रूपये की योजना स्वीकार हुई है उसके लिए भी मैं कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस राशि से गौ-अभयारण बनाये जा सकते हैं और गाय की नस्ल में सुधार करने में मदद मिल सकती है। इसी प्रकार से अब मैं भ्रष्टाचार के बारे में भी अपने विचार रखना चाहता हूँ। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सरकार ने ई-स्टैंपिंग, ई-रजिस्ट्रेशन तथा ई-टैंड्रिंग प्रणाली शुरू की है जिससे जनता का सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। जिस तरह से सरकार ने हिसार में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विकसित करने का फैसला लिया है उसी तरह से कुरूक्षेत्र को भी अन्तर्राष्ट्रीय मानचित्र पर लाने के लिए गीता जयन्ति समारोह को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाना चाहिए। यहाँ पर सूर्यग्रहण का मेला भी लगता है जिसमें दूर-दूर से तथा विदेश से भी लोग आते हैं। इसलिए यहाँ पर अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो जब बनेगा तब बनेगा लेकिन मेरा सरकार से निवेदन है कि तब तक यहाँ पर एक हवाई पट्टी बनाई जानी चाहिए । इस काम के लिए मेरे हल्के के जी.टी. रोड पर ही पड़ने वाले गांव खानपुर कोलियां, कनिपला, सौंटी और बोहली गांव हैं जिनकी पंचायतों से मेरी बात हो चुकी है और वे जमीन देने के लिए तैयार हैं। अध्यक्ष महोदय, आज हमारे प्रदेश की सभी पंचायतें पढ़ी-लिखी हैं और यह बात हम गर्व से कह सकते है इसके लिए मैं पंचायत मंत्री और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ । हिन्दुस्तान पूरी दुनिया का सबसे युवा देश है और उसी के कारण आज हमारे प्रदेश की पंचायतों के जनप्रतिनिधि युवा हैं जिनकी औसत आयु लगभग 34 वर्ष है। इन पढ़े-लिखे युवा प्रतिनिधियों के इ ाान और प्रतिभा के कारण ही हमारे मुख्यमंत्री जी के डिजिटल हरियाणा और प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें मदद मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने ग्राम सचिवालय बनाने का निर्णय लिया है और आगामी वित्त वर्ष 2016-17 में हमने 840 ग्राम सचिवालय बनाने का लक्ष्य रखा है । ग्रामिणों को अपने काम करवाने के लिए लघु सचिवालय तथा सब-डिविजन लेवल पर जाना पड़ता है अगर ये ग्राम सचिवालय बन जायेंगे और इनमें कर्मचारी तैनात हो जायेंगे तो ग्रामिणों को अपने कार्यों के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा और ग्राम स्तर पर ही उनकी सभी समस्याओं का समाधान हो जायेगा। इसी प्रकार से गांव के विकास के लिए हर ग्राम पंचायत पंचवर्षीय व वार्षिक आधार पर "हमारी योजना-हमारा विकास" नामक ग्राम पंचायत विकास योजना बनाएगी। इसके अतिरिक्त "स्वर्ण जयंती महाग्राम योजना" के प्रथम चरण में 10,000 या उससे अधिक आबादी वाले गांवों में योजनाबद्ध और नियंत्रित विकास करके शहरों जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। इन पंचायतों को नगर पंचायतों का दर्जा दिया जाएगा। भारत सरकार ने रूर्बन मिशन के तहत शहरी तर्ज पर ढांचागत और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए पांच समूहों को भी मंजूरी दी है । इसी प्रकार से स्वच्छ हरियाणा-स्वच्छ भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता के दृष्टिगत इस वर्ष के दौरान ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन की 1472 परियोजनाएं स्वीकृत की गई और 957 गांवों को खुले में शौच से मुक्त किया गया । इसके साथ ही गांवों में 600 व्यायामशाला व पार्क स्थापित करने की एक नई स्कीम शुरू की गई है इससे स्वच्छ हरियाणा-स्वच्छ भारत बनेगा और स्वस्थ हरियाणा-स्वस्थ भारत बनेगा।

[डॉ. पवन सैनी]

अध्यक्ष महोदय, इस दिशा में भी हम कामयाब होंगे और स्वच्छता अभियान के तहत भारत सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र में शौचालय बनाने के लिए 4 हजार रूपये वितीय सहायता के रूप में दिये जा रहे हैं लेकिन हमारी हरियाणा सरकार ने 10 हजार रूपये अतिरिक्त राशि देने का काम किया है जिसमें स्थानीय निकायों के तहत शहरों में हर घर में शौचालय बनेंगे । अध्यक्ष महोदय, इस मिशन के तहत हरियाणा सरकार ने ठोस कचरा प्रबंधन की ओर भी विशेष ध्यान दिया है। जिसमें 80 शहरी स्थानीय निकायों के लिए ठोस कचरा प्रबंधन की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी लेकिन इसमें थोड़ी सी तेजी लाने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के जितने भी 90 विधान सभा क्षेत्र हैं उनके जो कॉन्टीचुवेंसी हैड क्वार्टर हैं क्योंकि जो शहरी कॉन्टीचुवेंसी हैं उसमें तो विकास होगा ही होगा लेकिन हमारी हरियाणा में कुछ ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र भी हैं उनके जो केन्द्र हैं उनके जो कॉन्टीचुवेंसी हैड क्वार्टर हैं। जैसे लाडवा का है, इन्द्री का है, सढ़ौरा का है, मुलाना का है , अटेली का है ऐसे बहुत से विधान सभा क्षेत्र हैं उनमें जो विधान सभा के केन्द्र हैं वह विकसित नहीं हैं। मेरा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि ऐसे विधान सभा के जो केन्द्र है, कॉन्टीचुवेंसी हैड क्वार्टर हैं उनके लिए मास्टर प्लान बनाई जाए ताकि उन केन्द्रों में भी विकास हो सके।

श्री अध्यक्ष : डां. साहब, प्लीज वाईंड अप करें क्योंकि दूसरे माननीय सदस्यों ने भी अपनी बात कहनी है ।

डॉ. पवन सैनी : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने व कृषि मंत्री जी ने हरियाणा के अन्दर जो बागवानी विश्वविद्यालय खोला है और उसके दो-तीन रीजनल सैंटर भी खोले हैं। मेरी इच्छा है कि जिन इलाकों के अन्दर इस प्रकार की फसलें बीजी जाती हैं अगर वहां पर बड़े-बड़े कोल्ड स्टोर बनाएंगे तो वहां फसलों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। इसी के साथ हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो प्रत्येक जिले में एक मैडिकल कॉलेज खोलने की बात कही है। जिन स्वास्थ्य सुविधाओं की ओर पिछली सरकारों ने ध्यान नहीं दिया अगर मंत्री जी मैडिकल कॉलेजों को खोलेंगे तो उससे भी हमारे प्रदेश के लोगों को लाभ मिलेगा और जो मंत्री जी ने चार जिलों में हीमाडायलिसिस और पैथोलोजी लैबोरेट्री खोलने का काम किया है इससे जो महंगे ईलाज के कारण हमारे कुछ लोग दम तोड़ देते हैं अगर सरकारी अस्पतालों में ऐसी सुविधा होंगी तो उससे हमारे गरीब वर्ग के लोगों को भी लाभ मिलेगा। अध्यक्ष महोदय शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारे शिक्षा मंत्री जी ने एक अमूल-चूल परिर्वतन किया है। पिछली सरकारों के समय में जहां आठवीं तक बिना पढ़े बच्चों को पास किया करते थे उसके लिए रैमीडियल क्लासिज और मंथली टैस्ट लेने का जो काम किया है इससे बच्चों में उनका शिक्षा का स्तर भी बढ़ेगा और उनमें गुणवत्ता भी आएगी। इसके अलावा गणतंत्र दिवस के अवसर पर बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम और हमारी बेटियों के हाथों से झण्डा फहरवाया गया इससे भी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान में भी कामयाबी मिलेगी। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जिन-जिन विधान सभा क्षेत्रों में लड़कियों के लिए कॉलेज नहीं है जिससे मेरा विधान सभा क्षेत्र भी वंचित है। मैं शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हर विधान सभा क्षेत्र में हमारी बेटियों के लिए भी एक कॉलेज खोला जाए। अध्यक्ष महोदय, जहां शिक्षा स्तर की बात है जिसके लिए हमारे विधायक सुभाष सुधा जी ने भी कुरूक्षेत्र महाविद्यालय की बात रखी जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारी कुरूक्षेत्र युनिवर्सिटी को एक सैंट्रल युनिवर्सिटी बनाया जाए क्योंकि कुरूक्षेत्र युनिवर्सिटी एक बहुत बड़ी मदर

युनिवर्सिटी है बहुत विश्वविद्यालय उस से बने हैं और वहां पर जो स्टेडियम है उसकी हालत बिल्कुल खश्ता है। वहां पर न ही हॉकी का कोई स्टेडियम है और न ही एस्ट्रोटर्फ है। लेकिन पिछली सरकार में जैसा मैंने कहा कि क्षेत्रवाद की * * * थी। उन्होंने सब कुछ रोहतक के लिए काम किया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने जो अनपार्लियामैंटरी शब्द कहे हैं वे रिकॉर्ड न किये जाएं।

डॉ. पवन सैनी : अध्यक्ष महोदय, मेरे जिले में शाहबाद भी एक कस्बा है वहां भी एक हॉकी एस्ट्रोटर्फ लगा है। उसका समय लगभग 5 वर्ष होता है लेकिन उसको भी लगे हुए 10 वर्ष हो गये हैं। इसलिए युनिवर्सिटी में भी खिलाड़ियों को जो सुविधा होनी चाहिए उनको भी पूरा करवाने का काम करें। अध्यक्ष महोदय, जब से हमारी सरकार बनी है तब से बहुत से लोगों के पेट में दर्द है और इस आरक्षण की आड़ में उन लोगों ने हरियाणा में तांडव किया जिससे हमारे बहुत से परिवार बेघर हुए हैं इसलिए मैं इस विषय पर ज्यादा न कहते हुए क्योंकि उस तांडव को देखने पहले मैं अकेला भी गया हूं और मेरे साथ आदरणीय मंत्री नायब जी, कर्णदेव कम्बोज जी और सुभाष सुधा जी भी गये थे जो देखा नहीं गया उनमें चार-चार दिन तक आग जलती रही। मै इस विषय पर ज्यादा न बोलते हुए आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे वह गोहाना का एस.डी.एम. हो चाहे वह हिसार का एस.डी.एम. हो, ऐसे लोगों को चिन्हित करके चाहे प्रशासनिक अधिकारी हों, चाहे पुलिस अधिकारी हों उनको सबक सिखाया जाए।

अध्यक्ष महोदय, जब भी एस.वाई.एल. नहर के मुद्दे पर चर्चा होती है तो इस सदन में बार-बार इस मुद्दे पर मेरे पिता जी ने यह किया है या मेरे पिता जी ने वह किया है, शब्दों का प्रयोग किया जाता है लेकिन मुझे फख है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वाहवाही की बजाय काम में विश्वास रखते हैं। सदन में बार-बार चर्चा शब्द का प्रयोग किया जाता है। चर्चा से कुछ होने वाला नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आज एस.वाई.एल. नहर के मुद्दे पर कुछ अहम कदम उठाने की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी काम में विश्वास करते हैं और जिसके रिजल्ट हम सबके सामने हैं। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा के दौरान अपनी बात रखने का मौका दिया उसके लिए आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। जय हरियाणा-जय हिन्द।

श्री पिरथी सिंह (नरवाना) (एस.सी.) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश है और पूर्णत: कृषि पर निर्भर है। हर वर्ग चाहे वह कर्मचारी है, व्यापारी है या मजदूर वर्ग है, सभी खेती पर ही निर्भर हैं। परन्तु अफसोस आज कृषि घाटे का सौदा बनकर रह गई है। महंगाई की वजह से अपनी फसल उगाने में भी किसान को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी पिछले दिनों बेमौसमी बारिश की वजह से किसान की रबी की फसल बर्बाद हो गई जिसका देश की आर्थिक व्यवस्था पर सीधा असर पड़ा है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले व मध्यवर्गीय लोगों की पैट्रोल व डीजल की बढ़ती हुई कीमतों ने कमर तोड़कर रख दी है। जब भी डीजल की कीमत बढ़ती हैं तो उसका सीधा असर खाद्य वस्तुओं पर पड़ता है तथा महंगाई का प्रतिशत भी साथ-साथ बढ़ता है। डीजल की कीमतें बढ़ने से किराये में वृद्धि होती है

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

[श्री पिरथी सिंह]

जिसका जीवनोपयोगी वस्तुओं पर सीधा असर होने से 5 प्रतिशत महंगाई का आंकड़ा बढ़ता है। आम आदमी को नई सरकार से अच्छे दिनों की उम्मीद थी परन्तु महंगाई ने उनके रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। सब्जी, दालें व अन्य जरूरी वस्तुओं की कीमतों में 5 से लेकर 20 रूपये प्रति किलो की वृद्धि हुई है। पशु चारा जो 2100 रूपये प्रति क्विंटल हुआ करता था वह बढ़कर 2500 रूपये प्रति क्विंटल हो गया है जिसकी वजह से दूध की कीमतों पर सीधा असर पड़ा है। चीनी 2560 रूपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 2800 रूपये प्रति क्विंटल हो गई है। (शोर एवं व्यवधान)

खनन एवं भूगर्भ राज्य मंत्री (श्री नायब सैनी): अध्यक्ष महोदय, पिरथी सिंह जी वास्तविकता से दूर होकर बात कर रहे हैं। चीनी की कीमतें तो पहले से भी कम हो गई हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नायब जी, आपकी बात ठीक है लेकिन पिरथी जी को अपनी बात पूरी कर लेने दें उसके बाद इस विषय पर बात की जा सकती है।

श्री पिरथी सिंह : अध्यक्ष महोदय, सरसों के तेल की कीमतों में भी वृद्धि हुई है। खुदरा व्यापारी मंडी में कीमते दोगुनी हो गई हैं। दालों की कीमत 150 से 200 रूपये प्रति किलो तक पहुंच गई है। केन्द्र सरकार की जमाखोरी व कालाबाजारी करने वालों के साथ मिलीभगत है। यह व्यापारी बेमौसमी बारिश का बहाना बनाकर नाजायज फायदा उठा रहे हैं। दिल्ली में पिछले एक महीने से दालों की रिटेल कीमतों में 50 से 75 प्रतिशत तक की बढ़ौतरी हुई है। इसकी वजह से आम आदमी तथा मजदूरी करने वालों का बजट बिगड़ गया है। गरीबी से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए बच्चों का पेट भरना तथा स्कूल की फीस देना एक सपना बनकर रह गया है। केन्द्र ने भी महंगाई को हल्के में लिया है और कोई एक्शन प्लान महंगाई को बढ़ने से रोकने के लिए तैयार नहीं किया गया है। सरकार मात्र मीटिंग्ज करती है और प्रैस में ब्यान दे देती है परन्तु धरातल पर न ही राज्य सरकार और न ही केन्द्र सरकार इस बारे चिन्तित है। पिछले दस साल जो कांग्रेस की सरकार रही है उस समय मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र नरवाना की पूर्णत: अनदेखी की गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के डेढ साल के शासन काल में भी नरवाना विधान सभा क्षेत्र में कोई कार्य नहीं हो पाया है और ऐसा लगता है कि अब भी इसमें कोई विकास संभव हो सकेगा। आज भी मेरे हल्के के साथ भेदभाव किया जा रहा है। अभी पीछे सफेद मक्खी के कारण जो कपास की फसल बर्बाद हुई थी। सरकार ने इस विषय पर रिचैकिंग करवाई है जिसमें कहीं न कहीं भेदभाव बरता गया है और मुझे नहीं लगता कि सभी पीड़ित किसानों को इसका कोई मुआवजा मिल पायेगा। सरकार स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाने का दावा करती है। मेरे नरवाना विधान सभा क्षेत्र के गांव बेलरखां, कान्हाखेड़ा, कर्मगढ़, ईस्माईलपुर, खानपुर कलां, फुहलां, खुर्दकलां, कलौदा खुर्द, दरौदी तथा उझाना जैसे गांवों में तथा शहर की बाहरी कॉलानियों में पीने के पानी की भारी समस्या है। गांवों में पीने के पानी की जो थोड़ी बहुत सप्लाई आती है वह पीने के लायक नहीं है। इन गांवों में पीने के पानी में टी.डी.एस. की मात्रा काफी मात्रा में पाई जाती है। (विघ्न)

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे माननीय साथी श्री पिरथी सिंह जी को बताना चाहता हूँ कि पिछले साल लगभग 7-8 मार्च को तेज आंधी और ओलवृष्टि की वजह से गेहूं की फसल को भंयकर नुकसान पहुँचा था। सरकार ने तुरंत इस पर संज्ञान लेते हुए 1092 करोड़ रूपये मुआवजे के तौर पर दिए थे। वर्ष 1966 से हरियाणा प्रदेश के अलग बनने के बाद आज तक किसी भी सरकार ने एक फसल के लिए इतना मुआवजा नहीं दिया है। हरियाणा प्रदेश के 21 जिलों में से 5 जिलों हिसार, जीन्द आदि में कपास की खेती सघन रूप से होती है। सफेद मक्खी के प्रकोप से फसल को बड़ी भारी नुकसान पहुँचा था, जिस पर सरकार ने तुरंत स्पेशल गिरदावरी करवाकर नवम्बर, 2015 में 967 करोड़ रूपये का मुआवजा दिया था। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात और सदन में कहना चाहता हूँ कि यह सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए वचनबद्ध है। पिछली किसी भी सरकार ने इतना मुआवजा आज तक नहीं दिया। (शोर एवं व्यवधान)

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू: अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकारों में फसलों को इतना नुकसान हुआ ही नहीं जो इतना मुआवजा देने की जरूरत पड़े। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम बिलास शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय साथी श्री पिरथी सिंह की चिंता है कि नरवाना विधानसभा क्षेत्र में मुआवजा नहीं मिला है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि यदि किसी भी विधायक को लगता है कि कपास या अन्य फसल के लिए मुआवजा नहीं मिला है तो उन गांवों के नाम लिखकर भिजवा दें, हम उन्हें चैक करवा लेंगे। अध्यक्ष महोदय, किसानों को राहत देने के लिए यह सरकार अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी। जो इस सरकार की काम करने की मंशा है वह किसी भी सरकार की नहीं हो सकती है।

श्री पिरथी सिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ठीक कह रहे हैं। लेकिन सरकार ने मुआवजा देने के लिए जो दोबारा री-चैकिंग करवाई थी, उससे पहले गेहूँ की फसल 25 प्रतिशत बिछ चुकी थी। यह कैसे अंदाजा लगाया जायेगा कि मुआवजा मिलेगा या नहीं। अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान क्षेत्र के बेलरखां गांव के 150 आदमियों की रोहतक से आई टीम के द्वारा जांच की गई थी जिनमें से 30 लोग हैपेटाइटिस के मरीज पाए गए थे। जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा बताया गया है कि जिस पानी में टी.डी.एस. की मात्रा 600 से अधिक हो वह पानी पीने के योग्य नहीं होता है। अध्यक्ष महोदय, आपको यह सुनकर हैरानी होगी कि उस गांव के पीने के पानी में टी.डी.एस. की मात्रा 2800 से लेकर 3000 तक पाई गई है। जो पानी के नाम पर जहर है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस गांव में स्वच्छ साफ पानी लोगों को पीने के लिए दिया जाये। अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के नरवाना में बाबा गैबी साहिब नामक तीर्थ स्थल है जोकि पूरे नरवाना हल्के में बहुत ही पूजनीय स्थल है। इस पवित्र स्थल पर नरवाना हल्के के सभी गांव व शहर ही नहीं बल्कि दूर-दूर इलाकों से इस पवित्र स्थल पर पूजा करने के लिए लोग आते हैं। इस पवित्र स्थल की अपनी खुद की जमीन भी काफी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। नरवाना क्षेत्र के लोगों की इस मन्दिर के प्रति काफी गहरी आस्था है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से अनुरोध करता हूँ कि इस तीर्थ स्थल को कुरूक्षेत्र विकास बोर्ड के अधीन किया जाये ताकि यह हरियाणा के दार्शनिक स्थल के रूप में दर्जा प्राप्त कर सके। यह इस सदन के लिए बड़ी महानता का कार्य होगा।

[श्री पिरथी सिंह]

अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने हल्के की इस समस्या के बारे में माननीय मंत्री जी को अवगत करा दिया था परंतु मैं आपके माध्यम से दोबारा इनके संज्ञान में यह समस्या लाना चाहता हूं । मेरे नरवाना हल्के में विज्ञान के क्षेत्र में उच्चतर शिक्षा M.sc. in कैमेस्ट्री, फिजिक्स, जुजोलोजी, बोटनी और मैथ जैसे विषयों की कोई व्यवस्था न होने के कारण यहां के हजारों छात्र-छात्राओं की प्रतिभा पर ग्रहण लग गया है। अत: आज सामाजिक, सांस्कृतिक एवं बौद्धिक विकास हेतु वैज्ञानिक शिक्षा वर्तमान समय की सर्वोत्तम मांग है। हमारे के.एम. सरकारी कॉलेज में वर्तमान में 300 से ज्यादा बी.एस.सी. फाइनल नॉन मेडिकल और मेडिकल के विद्यार्थी अध्यनरत हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : पिरथी सिंह जी, आप प्लीज, वाइंड अप कर लीजिए।

श्री पिरथी सिंह: अध्यक्ष महोदय, 2015 के पास आउट छात्रों की संख्या 275 है पिछले तीन सत्रों के विद्यार्थियों की संख्या लगभग 1000 के पार है जिनमें से अधिकतर दूरदराज के गांव से आने वाली लड़कियां हैं और इसमें 50 प्रतिशत से अधिक छात्राएं बी.एस.सी. पास हैं। नरवाना क्षेत्र के आस-पास कहीं भी सरकारी विश्वविद्यालय नहीं है जिसमें एम.एस.सी. कैमेस्ट्री, फिजिक्स, बायोलोजी इत्यादि विषय पढ़ाए जाते हों। **(इस समय उपाध्यक्ष महोदया चेयर पर आसीन हुई।)** उपाध्यक्ष महोदया, हमारी वैज्ञानिक प्रतिभा व्यवस्था के अभाव में दम तोड़ रही है। आज की गला-काट प्रतियोगिताओं के जमाने में पात्र छात्र योग्य होते हुए भी दाखिला पाने से वंचित रह जाते हैं। संपन्न परिवारों के कुछेक बच्चे सी.डी.एल.यू., सिरसा, एच.ऐ.वी. और जी.जे.यू., हिसार, बी.एल.यू., भिवानी, कुरूक्षेत्र युनिवर्सिटी कुरूक्षेत्र, एवं महर्षि दयानन्द युनिवर्सिटी रोहतक में प्रवेश पा जाते हैं लेकिन अधिकतर ग्रामीण विद्यार्थी उच्चतर शिक्षा से वंचित रह जाते हैं और बी.एस.सी. फाइनल के उपरान्त पढ़ाई छोड़ जाते हैं। अत: शिक्षा मंत्री जी से मेरा हार्दिक अनुरोध है कि नरवाना के के.एम. सरकारी कॉलेज में पोस्ट ग्रेज्युएट कैमेस्ट्री का शुभारम्भ इसी वर्ष 2016 से ही शुरू करवाने का कष्ट करें। इसके अतिरिक्त हमारे नरवाना हल्के में के.एम. सरकारी कॉलेज में वर्ष 2014-15 सेशन के दौरान करीब 1500 लड़कियां थी और पिछले वर्ष भी यह संख्या लगभग इतनी ही रही है। कॉलेज में बच्चों की कुल संख्या 3300 के करीब है जबकि नरवाना क्षेत्र से इतनी ही संख्या में लड़कियां यहां दाखिला न मिलने के कारण आसपास के दूसरे प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ने के लिए भी जाती हैं। प्राइवेट कॉलेजों में बी.ए. फाइनल कम्पलीशन का पैकेज लगभग 80,000 रूपये का होता है जबकि सरकारी कॉलेज में यह कम्पलीशन बहुत ही कम पैसों में की जा सकती है। जहां तक मेरी जानकारी है इसमें सरकार ने एक पॉलिसी भी रखी है कि जिस किसी भी कॉलेज में लड़कियों की संख्या एक हजार से ज्यादा हो वहां नया महिला कॉलेज बनाए जाने का सरकार की ओर से प्रावधान है और इसमें स्टेट गवर्नमैंट को ज्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ता क्योंकि इसके लिए केन्द्र सरकार की ओर से भी विशेष पैकेज दिया जाने का प्रावधान है। अगर सरकार का इस पूरे प्रोजेक्ट पर रवैया नरम है तो उन्हें जमीन से सम्बन्धित कोई भी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि नरवाना सरकारी कॉलेज के पास काफी जमीन है इसलिए मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि नरवाना में सरकारी महिला कॉलेज जल्द से जल्द बनाया जाए। उपाध्यक्ष महोदया, नरवाना सामान्य अस्पताल 100 बिस्तरों वाला अस्पताल है जबकि यहां पर किसी भी तरह की सुविधा नहीं है। इस सामान्य अस्पताल में संबंधित जरूरी सुविधाएं और विशेषज्ञ डॉक्टरों की भारी कमी है जिसकी वजह से मरीजों को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जिसके चलते लोगों को आवश्यकता पड़ने पर रोहतक, हिसार, चण्डीगढ़ और दिल्ली

तक ईलाज के लिए जाना पड़ता है। इसी तरह यहां पर एक्स-रे और अल्ट्रासाउंड मशीनों की सुविधा भी न के ही बराबर है। डॉक्टरों द्वारा किसी बीमारी के लिए लिखे गए एक्स-रे या अल्ट्रासाउंड को करवाने के लिए लोगों को कैथल या फिर जीन्द जाना पड़ता है। साथ ही मुझे जहां तक जानकारी है नरवाना सिविल अस्पताल में स्वीपर के पदों की कुल संख्या 12 मनोनीत है जबकि वहां पर केवल 6 स्वीपर ही काम कर रहे हैं। अत: मेरा आपसे अनुरोध है कि यहां पर जनरल सर्जन, फिजीशियन, पेडियाट्रिशियन, गायनोकोलोजिस्ट व कर्मचारियों की नियुक्ति के साथ-साथ डिजिटल एक्स-रे मशीन की उपलब्धता भी जल्द से जल्द करें। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र के गांव अमरगढ़ में एक प्राथमिक स्वास्थ्य 17:00 बजे केंद्र है। गांव की पंचायत ने इसकी स्वयं की बिल्डिंग के लिए 4 एकड़ जमीन दी हुई है मगर आज भी इस स्वास्थ्य केन्द्र को गांव की सामान्य चौपाल में ही चलाया जा रहा है। इसी तरह गांव सिंसर में पी.एच.सी. की अपनी बिल्डिंग न होने की वजह से इसे भी चौपाल में ही चलाया जा रहा है जबकि सरकार की ओर से पी.एच.सी. के लिए लगभग 5 एकड़ जमीन की मांग की गई थी, पंचायत ने उतनी ही जमीन की रजिस्ट्री विभाग के नाम करवा दी है। उपाध्यक्ष महोदया, नरवाना विधान सभा क्षेत्र में एकमात्र सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उझाना में है। इस सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर आस पास के गांवों के लोग भारी संख्या में प्रतिदिन अपने इलाज के लिए आते हैं जिसकी बिल्डिंग बिल्कुल जर्जर हालत में है। इस बिल्डिंग में कमरों के अभाव के चलते चिकित्सा अधिकारी व कर्मचारियों के बैठने के लिए भी जगह नहीं है। यहां तक कि एक कमरे में 8-8 कर्मचारी बिल्कुल तंग जगह में बैठने के लिए मजबूर हैं। जिसके चलते मरीजों के लिए अपनी बीमारी के साथ साथ तंग जगह भी परेशानी का सबब बना हुआ है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि नरवाना सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए नई बिल्डिंग बनाई जाए। नरवाना नवदीप स्टेडियम से निकले बच्चे आज हर खेल में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर देश व प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। नरवाना के तीन बच्चे आज भी हाकी के खेल में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर व बहुत से बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर देश व प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। आजकल हॉकी प्रतियोगिताओं का आयोजन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। नरवाना स्टेडियम में हॉकी का घासयुक्त कच्चा मैदान मौजूद है, बस जरूरत तो सिर्फ एस्ट्रोटर्फ की है। मेरा मानना है कि यहां पर हॉकी के लिए एस्ट्रोटर्फ बिछा दिया जाए तो काफी संख्या में बच्चे इस खेल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना योगदान दे सकते हैं। मेरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अनुरोध है कि हमारे इस स्टेडियम में बच्चों के खेल की प्रतिभा को देखते हुए यहां एस्ट्रोटर्फ जल्दी से जल्दी बिछाया जाए ताकि बच्चे अपने खेल में सुधार कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलकर देश व प्रदेश का नाम रोशन कर सकें।

उपाध्यक्ष महोदया: पिरथी सिंह जी, आप वाइंड अप करें।

श्री पिरथी सिंह: उपाध्यक्ष महोदया, नरवाना हल्के के लगभग सभी गांवों में बिजली की तारें जर्जर हालात में हैं। जिन गांवों में तारों की हालत ज्यादा ही खस्ता हाल में हैं उन गांवों के नाम निम्न प्रकार से हैं- कर्मगढ़, खरड़वाल, सुलहेड़ा, जुलेहड़ा, राजगढ ढोभी, बडनपुर, ढाबीटेक सिंह सैंथली, जाजनवाला, अम्बसर, घरौदी, हरनामपुरा आदि। उपाध्यक्ष महोदया, जर्जर हुई ये तारें अपने आप टूटकर नीचे गिर जाती हैं जिससे अभी कुछ दिन पहले ही गांव कर्मगढ़ में अपने खेत में काम कर रहा एक किसान जर्जर हुई इन तारों के टूटकर नीचे गिरने की वजह से मौत का ग्रास बन गया। ऐसे हादसों पर सरकार की ओर से पीड़ित परिवार को कोई

[श्री पिरथी सिंह]
आर्थिक मदद नहीं दी जाती है। इससे पहले भी न जाने ऐसे ही कितने हादसे घटित हो चुके हैं। मेरा सरकार से आग्रह है कि नरवाना हल्के की जर्जर हो चुकी बिजली की सभी तारों को बदलवाने का काम करें। उपाध्यक्ष महोदया, नरवाना ओल्ड से डूमरखां तक 132 के.वी. की हाई पावर वोल्टेज लाईन गुजरती है जोकि नरवाना शहर की कई रिहायशी कालोनियों जैसे हनुमान नगर, हरिनगर, हाउसिंग बोर्ड कालोनी आदि के बिल्कुल ऊपर से गुजरती है । जिसकी वजह से आए दिन जान माल का नुकसान होता रहता है। वहां के लोग आज भी मौत के साये में जी रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि इस हाई पावर वोल्टेज लाइन को इन रिहायशी कालोनियों से हटाकर इसे दूसरी ओर से किया जाए।

परिवहन मंत्री (श्री कृष्ण लाल पंवार): उपाध्यक्ष महोदया, बिजली विभाग मुख्यमंत्री महोदय के पास है और उन की घोषणा है कि जहां पहले चाहे लीगल कालोनीज हों, इल्लीगल कालोनीज हों या हाउसिंग बोर्ड हो वहां एच.टी. और एल.टी. लाइनें चेंज करवाने का खर्चा कंज्यूमर्ज को करना पड़ता था लेकिन अब सरकार ने फैसला किया है कि सरकारी खर्चे से उन लाइनों को शिफ्ट किया जाएगा।

श्री परमिन्दर सिंह ढुल: उपाध्यक्ष महोदया, माननीय पर्लियामैंट्री एफेयर्ज मिनिस्टर ने मुआवजे के रूपये देने के बारे में जो वक्तव्य दिया है मैं इस बारे में कहना चाहूंगा कि ठीक है मुआवजा बांटा गया और यह अच्छी बात है। लेकिन मुआवजे में जो घपला हुआ है, उसका डाक्यूमैंट्री प्रूफ होने के बाद क्या सरकार आश्वस्त कर सकती है कि उसकी जांच करेंगे। उपाध्यक्ष महोदया, रेवैन्यू मिनिस्टर जी यहां बैठे हुए हैं मैं उनको कहना चाहूंगा कि हरियाणा के अंदर जो सिस्टम है उसके मुताबिक नहरी पटवारी साल में 4 बार गिरदावरी करता है और रैवेन्यू पटवारी साल में एक बार गिरदावरी करता है। जो नहरी पटवारी की 4 बार गिरदावरी हुई उसका मिलान करके जो दोबारा मुआवजा दिया है उसमें कुछ सुधार हुआ है। लेकिन पहले 400 से 450 करोड़ रूपये का घपला हुआ है। इससे संबंधित मेरे हल्के के खरेटी गांव के सुरजमल नैन ने आर.टी.आई. मांगी जिसके अनुसार 80 प्रतिशत मुआवजे का गलत बंटवारा हुआ है।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : उपाध्यक्ष महोदया, कभी-कभी ऐसा लगता है कि इस सदन को केवल मात्र आरोप लगाने का माध्यम बनाकर रखा हुआ है। यह सदन इस बात का गवाह भी है कि 50वां साल हरियाणा का आया है। जो लोग किसानों के नाम पर राजनीति करते रहे, उन लोगों ने भी इधर बैठकर शासन चलाया है। प्राकृतिक मार पहले भी कई दफा हुई। कभी सुखा पड़ा, कभी ओलावृष्टि हुई और कभी बाढ़ आई। ये सब रिकार्ड की बातें हैं, रिकार्ड न मैं बदल सकता हूं और न मेरे साथी बदल सकते हैं। एक-एक साल का रिकार्ड हमने इसी सदन में प्रस्तुत भी किया है कि किसान मरता और बर्बाद होता रहा तथा लिपापोती होती रही, अखबार बाजी होती रही। ब्यानबाजी होती रही, गिरदावरी होती रही और किसने कितना दिया, कितना नहीं दिया यह सब चलता रहा। लेकिन पहली बार हरियाणा के इतिहास में एक ऐसी सरकार आई है जिसने अपने पिछले एक साल के दौरान अढ़ाई से तीन हजार करोड़ रूपये बजट से अलावा किसानों पर प्राकृतिक मार पर मलहम लगाने के लिए मुआवजे के रूप में दिए हैं। इसके अलावा 240 करोड़ रूपये पिछली सरकार जो छोड़ गई थी वह मुआवजा भी हमने दिया है। इसी तरह शुगर केन फार्मर्ज को लीक से हटकर शुगर मिल्ज को मदद करने का निर्णय सरकार ने लिया

ताकि किसानों को उनके गन्ने की पेमैंट मिल सके। जहां तक कपास के मुआवजे की बात है इस बारे में विपक्ष के साथियों ने ही कुछ कमियां बताई। इसको लेकर जो भी बात आई उसके बारे में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हर पहलू की जांच की जाए ताकि किसानों को किसी तरह का नुक्सान न हो। इसलिए पूरी जांच और पड़ताल प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश देकर करवाई गई। डी.सीज. की रिपोर्ट आने के बाद फाईनैंशियल कमिश्नर्ज को दोबारा भेजकर जांच करवाई है। पहले जहां गिरदावरी एक अधिकारी करता था इस बार चार-चार अधिकारियों की टीम गठित करके गिरदावरी करवाई है। इस कारण से कुछ देरी भी हुई है। लेकिन हमारी सरकार ने एतिहासिक मुआवजा 967 करोड़ रूपये का सफेद मक्खी से हुए नुक्सान के लिए किसानों को दिया है। यदि विपक्ष के साथी सही मायने में किसान के हमदर्द हैं तो इस कार्य के लिए इन्हें सरकार का धन्यवाद करना चाहिए। हर बात में राजनीति करना या अच्छी कार्य में भी कमी निकालना अच्छी बात नहीं है। उपाध्यक्ष महोदया, ढुल साहब भाईचारे में मेरे बड़े भाई लगते हैं और इन्होंने कह दिया कि 540 करोड़ रूपये का घपला हुआ। क्या यह बात सदन में बताने के लिए इन्होंने रखी थी यदि ऐसी कोई बात थी तो ये मरे से कई दफा मिले हैं उसी समय मुझे बताते कि इसको जांच करवाई जाये। इस तरह का सहयोग मेरे साथी कर सकते थे। उपाध्यक्ष महोदया, अभी भी मैं सदन को आपके माध्यम से आश्वस्त करता हूं कि कहीं भी कोई कमी मिलेगी तो उसकी सरकार निष्पक्षता से जांच करवायेगी और ठीक करने का प्रयास करेंगे। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदया, मेरे साथी बैठे हुए हैं। हमारी सरकार ने कपास का मुआवजा दिया है। सिरसा भी उसमें शामिल है और मेरे कई माननीय साथी वहां से चुनकर भी आये हैं। कपास के खराबे पर जितना मुआवजा एक जिले सिरसा में हमने दिया है उतना टोटल मुआवजा 50 साल में नहीं दिया गया। यदि विपक्ष के साथियों ने अपनी 8-10 साल की सरकार के कार्यकाल में इतना मुआवजा दिया हो तो ये हमें बतायें। हमने एक जिले में कपास का इतना मुआवजा दे दिया जितना पिछली सरकारों ने अब तक पूरे प्रदेश में नहीं दिया। (विघ्न) मैं चुनौती देकर कहता हूं कि विपक्ष के माननीय साथी अपने समय का पूरा हिसाब निकाल लें। जितना हमने एक फसल के खराबे का मुआवज़ा हरियाणा प्रदेश के किसानों को दे दिया है इन्होंने अपने समय की सारी की सारी 25-30 फसलों के खराबे का मुआवज़ा किसानों को नहीं दिया होगा। ये अपना पूरा हिसाब लगा लें और उसके बाद मुझसे बात करें। मैं इनकी चुनौती को स्वीकार करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदया : संधू जी, आप क्या कहना चाहते हैं?

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि अपने-अपने समय में सभी सरकारों ने फसल के खराबे के मुआवज़े दिये हैं। मैं यह बात विशेष रूप से उनके ध्यान में लाना चाहूंगा कि मुआवज़ा देने की प्रथा की सबसे पहले शुरूआत चौधरी देवी लाल जी ने की थी। मुआवज़ा देना अच्छी बात है लेकिन जिस प्रकार से किसानों की पिछली जीरी की फसल के दौरान 200 रूपये का मॉस्चर कट लगाकर 10 हज़ार करोड़ रूपये का घपला इस सरकार के समय में हुआ है। यह बहुत गलत बात है। इस बात का इतिहास गवाह है कि आज तक हरियाणा में जीरी की फसल पर 200 रूपये का मॉस्चर कट कभी भी नहीं लगा है। हरियाणा के इतिहास में ऐसा पहली बार इस सरकार के समय में हुआ है। यह भी एक रिकार्ड है। यह बात भी सरकार को याद रखनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री तेज पाल तंवर (सोहना): आदरणीय डिप्टी स्पीकर महोदया जी, वैसे तो हम कल से

महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर कल से बोलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन इसके बावजूद भी हमें आज जाकर मौका मिला है। सबसे पहले तो मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। हमारी सरकार ने अपने छोटे से कार्यकाल में जो-जो कार्य किये हैं उनका ब्यौरा महामहिम राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण में बड़ी अच्छी तरह से किया गया है। हमारी सरकार किस प्रकार से ऐसे-ऐसे महान कार्य हरियाणा प्रदेश के विकास और हित के लिए कर रही है यह देखकर हमारे विपक्ष के भाईयों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे पानी का क्षेत्र हो, चाहे बिजली का हो और चाहे किसानों को उनकी खराब हुई फसल का मुआवज़ा देने की बात हो। हमारी सरकार ने सभी क्षेत्रों के लिए पर्याप्त काम किया है जिसका वर्णन इसमें किया गया है। मैं समझता हूं कि यह निर्विवाद रूप से सत्य है और इस पर किसी भी प्रकार की बहस की कोई आवश्यकता नहीं है। हरियाणा प्रदेश में 49 सालों में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। इस साल हम आप सभी के सहयोग से प्रदेश की 50वीं वर्षगांठ मनायेंगे। हमारे प्रदेश में कुछ काम ऐसे भी होते रहे हैं जो कि किसी भी हालत में नहीं होने चाहिएं थे। श्री अभय सिंह जी चौटाला इस समय नेता प्रतिपक्ष है। आदरणीय चौधरी देवी लाल जी इस समय हमारे बीच में नहीं हैं। उन्होंने हरियाणा प्रदेश की भलाई के लिए जो काम किये उसके बाद किसी ने भी वैसे काम नहीं किये हैं। हमने उनका पूरा साथ दिया था। हमने प्रदेश के हितों के लिए लड़े जाने वाले न्याययुद्ध में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हमारे लगभग सारे के सारे कार्यकर्त्ता 20-20 दिन जेलों में रहे। उस समय मैं स्वयं भी एक महीना जेल में रहकर आया था। विपक्ष के जो नेता अपनी पार्टी की बात करते हैं हरियाणा के विकास की लड़ाई में हमारा पूरा सहयोग इस पार्टी के साथ रहा। हमने आपको सरकार बनाने के लिए सहयोग दिया लेकिन आपकी पार्टी ने कभी भी हमारी पार्टी को महत्व नहीं दिया। आपकी पार्टी की सरकार के समय में भी इस प्रदेश की दशा चिंतनीय रही और बंसी लाल जी के समय में भी हालात वैसे के वैसे ही थे। उसके बाद चौधरी भजन लाल जी की सरकार इस प्रदेश में बनी लेकिन इस प्रदेश के हालातों में कोई सुधार नहीं हो पाया। फिर श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा 10 साल इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे लेकिन उन्होंने भी हमारे प्रदेश को क्षेत्रवाद और भाई भतीजावाद की दलदल में फंसाकर बर्बाद करने का काम किया। भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने जो हरियाणा प्रदेश की सभी क्षेत्रों में दुर्गति की वह आप सभी के सामने है। आज आप किसी भी क्षेत्र में चले जाईये, चाहे वह हॉस्पीटल का मामला है, चाहे स्कूलों का मामला है और चाहे किसान की बात है, पिछले 10 साल में कहीं कोई कार्य नहीं हुआ है। सबकी अपनी-अपनी ढपली अपना-अपना राग था। हम लोगों ने इनको सत्ता पर बैठाये रखा और इनका पूरा साथ दिया लेकिन इन्होंने हमारे इलाके में कोई काम नहीं किया। आज जब हमारी सरकार अच्छे काम कर रही है तो यह बात उनको हजम नहीं हो रही है और वे इसको मानने को तैयार नहीं हैं। आज हमारी सरकार जो काम कर रही है उस पर नुक्ताचीनी तो होती है लेकिन यह नहीं कहा जाता कि हमारी सरकार ने अच्छा काम किया है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो अच्छे कार्य हों उनकी सराहना की जानी चाहिए तथा जो गलत कार्य हों उनकी निन्दा की जानी चाहिए। इसी प्रकार से पिछली सरकार ने मेवात में जो हॉस्पीटल बनाया उसके बारे में भाई जाकिर जी ने भी बताया है और मैं बताना चाहूँगा कि जहाँ पर बीम लगता है वहाँ पर लकड़ी की बल्लियाँ लगा रखी हैं तथा सरिया की जगह पर सरकंडे लगा दिये गये। कहने का मतलब यह है कि उसमें बहुत घटिया सामग्री लगा कर पिछले 10 साल में इस तरह से लूट मचाई गई है। इसी प्रकार से हमारे इलाके के

लिए पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं की गई। बिजली का भी बुरा हाल रहा है, जब से बिजली शुरू हुई थी तब की लगी हुई तारें आज तक नहीं बदली गई। आज सभी लोग कह रहे हैं कि बिजली की तारें लटक रही हैं क्योंकि उन्होंने पिछले 10 साल इस क्षेत्र में कोई कार्य नहीं किया है। आज हमारी सरकार सभी कार्य करने के लिए कृतसंकल्प है। स्वच्छ पीने के पानी की भी व्यवस्था की जायेगी, तारें भी बदली जायेंगी, हॉस्पीटल्स में डॉक्टर मिलेंगे और स्कूलों में अध्यापक भी लगेंगे। इसी प्रकार से किसानों को हर प्रकार की सुविधा दी जायेगी। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने जो फसल बीमा योजना शुरू की है उससे किसानों को बाढ़, सूखा और ओलावृष्टि से होने वाले नुकसान की भरपाई बीमा से हो जायेगी और सरकार की तरफ मुआवजे के लिए नहीं देखना पड़ेगा। इसी तरह से पशुधन में गाय, भैंस इत्यादि का भी बीमा हो जायेगा। सरकार ने इसका प्रीमियम भी बहुत कम रखा है। अगर हमारे खेत में हमारी 25 हजार रूपये की फसल होगी तो उसके लिए किसान को केवल 500 रूपये प्रीमियम बीमा कम्पनी के पास जमा करवाना होगा और अगर हमारी फसल खराब हो जाती है तो उस स्थिति में बीमा कम्पनी 25 हजार रूपये हमें देगी । उसके बाद हमें सरकार से मुआवजे के लिए नारे नहीं लगाने पड़ेंगे। नारे अब तक बहुत लगा लिये अब हमें काम करने की जरूरत है। इसी प्रकार से अगर एस.वाई.एल. की बात की जाये तो उसके बारे में भी सभी राजनीतिक दलों ने इकट्ठे हो कर शोर मचाया और मैं भी उसी चक्कर में एक महीने तक जेल में रह कर आया था। उस समय ताऊ देवीलाल ने उस न्याय युद्ध का आह्वान किया था। ऐसा नहीं है कि हम प्रदेश के किसी मामले में पीछे रहे हैं। लेकिन जब हमने देखा कि इस प्रदेश में कोई काम नहीं हुआ तब प्रदेश की कमान आदरणीय श्री मनोहर लाल जी के हाथ में सौंपी है। एक संत आदमी आज प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं और उनको किसी के धन की लालसा नहीं है। मैं सभी राजनीतिक दलों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि हम सभी मिल कर इस प्रदेश को बहुत उंचाईयों तक ले जा सकते हैं तथा हरियाणा प्रदेश विश्व के मानचित्र पर आ सकता है। आज हरियाणा पूरे भारतवर्ष में पहले स्थान पर आ सकता है। आज पानी, बिजली और सड़कों को तो आप देख ही रहे हैं। इस साल के आखिर तक सभी सड़कें बन कर तैयार हो जायेंगी । इसी प्रकार से मैं मेरे इंडियन नैशनल लोकदल के भाईयों से कहना चाहता हूँ कि आप सहयोग से चलिए और आप सच को सच और गलत को गलत कहिए। जहाँ तक आरक्षण की बात है वह सभी चाहते हैं, सबको मांगना भी चाहिए और हमने भी मांगा था लेकिन ऐसा आरक्षण किसी ने नहीं मांगा होगा कि पूरे हरियाणा प्रदेश को जला दिया गया। किसी की दुकान फूंक दी किसी का स्कूल, बसें, कम्यूनिटी सैन्टर्स फूंक दिये गये। लोगों के सामान को लूट लिया गया और उसके बाद कह दिया गया कि कानून व्यवस्था सरकार ने खराब की है और सरकार उसको सम्भाल नहीं सकी। मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार कानून व्यवस्था को सम्भाल सकती थी लेकिन सैंकड़ों की तादाद में लोग मारे जाते लेकिन सरकार ने बहुत सूझबूझ का परिचय दिया कि इन लोगों को लूट लेने दो। आज उन लोगों के खिलाफ मुकदमें दर्ज हो रहे हैं और उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। उनको बिल्कुल नहीं बख्शा जायेगा। हमारे जिन साथियों ने प्रदेश में इस प्रकार का षडयंत्र रचा है, वे बच नहीं पायेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए था क्योंकि जब अपने घर में आग लगती है तब पता चलता है कि मेरा कितना नुकसान हुआ है। वह आरक्षण किसी जाति बिरादरी का नहीं होता एक समाज ने अगर मांग लिया और अगर उसका हक है तो उसको जरूर मिलना चाहिए। हम भी उसके पक्ष में हैं, हम खिलाफ नहीं हैं। पीछे गुजरों ने भी इस प्रदेश में आन्दोलन किया था। राजस्थान में भी किया था,

[श्री तेज पाल तंवर]

एक-दो महीने तक वह आन्दोलन चला था लेकिन वहां किसी की एक मूंगफली भी किसी ने नहीं उठाई थी। कश्मीर से लेकर कन्या कुमारी तक सारे काम हुए थे लोगों पर केस भी रजिस्टर्ड हुए थे जो आज भी तिहाड़ जेल में पड़े हैं जो तीन-तीन चार-चार और छ:-छ: साल की सजा भुगत रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदया, वे बिना मतलब की सजा भुगत रहे हैं उनको सरकार ने कही थी कि चलो हम माफ कर देते हैं लेकिन किसी को माफ नहीं किया और आज वे सजा भुगत रहे हैं। इसलिए मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि हम सभी अपने प्रदेश को चहूंमुखी विकास दें और जो हमारे कार्य हो रहे हैं उसमें सहयोग दें आप हमारे मुख्यमंत्री जी को बताएं कि यह कार्य गलत है तो मैं समझता हूं कि वह 100 प्रतिशत काम होगा। इसलिए हम मिल जुलकर चलें। अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि हम मिलजुल कर एस.वाई.एल. के मुद्दे को ठीक कर सकते हैं । अगर हमारी नीयत सही रहेगी तो हम प्रदेश में सारे कार्य कर सकते हैं। अत: मैं ज्यादा न कहते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में बैठे हैं मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि हर जिले में जिन-जिन लोगों के जिस-जिस क्षेत्र में कार्य हैं उनको प्राथमिकता के तौर पर ले लिया जाए और लिये भी हैं और यह बात भी हुई है कि सबका साथ और सबका विकास हम सबको साथ लेकर चलेंगे। हम ईधर-उधर की बात न करके क्योंकि आप माननीय सदस्यगण हैं आप प्रदेश की पंचायत में बैठे हैं और बहुत लोगों की आशाएं हमसे जुड़ी हुई हैं इसलिए हम सब मिल जुल कर इस प्रदेश को आगे लेकर जाएं। अगर हम आपस में खेंच खिंचाव न करके सही रास्ते पर चलेंगे तो मैं समझता हूं कि प्रदेश ठीक चलेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे क्षेत्र में भी कुछ समस्याएं हैं। मैं उनको भी आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। जयप्रकाश भाई साहब आप भी ईधर-उधर उछलकूद करते रहते हो कहीं एक जगह टिक कर रह लो कभी ग्रिन ब्रिगेड में चले जाओ कभी तिरंगे में चले जाओ कभी आजाद में आ जाओ तो मेरा आपसे यह कहना है कि कहीं एक जगह टिकोगे तो काम ठीक रहेगा। मेरे हल्के में तावडू का एरिया मेवात से लगता है। हमारे यहां एक एम.डी.ए. (मेवात डवैल्पमैंट अथोरिटी) है उसने हमारे क्षेत्र में बिल्कुल कुछ नहीं किया। हमारे क्षेत्र में कई जगह बिल्डिंग बनी पड़ी हैं लेकिन वह अभी तक चालू नहीं हुई। इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी मेरी अपील है कि वहां पर जो स्कूल और बिल्डिगज बनी हुई हैं कम से कम वह तो चालू कर दी जाएं। हमारे तावडू शहर में महिला कॉलेज की बड़ी भारी दिक्कत है क्योंकि हमारे क्षेत्र में मेव और हिन्दु का आपस में थोड़ा-थोड़ा सा झगड़ा रहता है। अगर हमारा वहां आपस में प्यार रहे जिसको हम तो चाहते हैं कि हमेशा प्यार बना रहे हम कभी नहीं चाहते कि हमारे आपस में किसी किस्म के भेदभाव रहें। उपाध्यक्ष महोदया, मेरे क्षेत्र सोहना में और कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है लेकिन उद्योगों की कमी है। आने वाले समय में सम्मिट के तहत प्रदेश में अब बहुत से उद्योग लगने वाले हैं और उनमें से ज्यादातर मेरे जिले में लगेंगे। आदरणीय डिप्टी स्पीकर महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री ओम प्रकाश बड़वा (लोहारू): उपाध्यक्ष महोदया, बार-बार एक बात कही जा रही है कि सबका साथ सबका विकास लेकिन मुख्यमंत्री महोदय जी को मेरे गांव के रोड़ को बनाने के बारे में कहते हुए मुझे एक साल हो गया है और वहां इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं जिसमें बहुत सारे लोग मर चुके हैं लेकिन सरकार का अभी तक वहां पर कोई ध्यान नहीं है। आप सैनी साहब से पूछिये ये वहां पर कमेटी के साथ टूर पर गये थे। उस समय उस रोड़ के बारे में इनसे भी बात हुई थी। (शोर)

उपाध्यक्ष महोदया : ओम प्रकाश जी, आपको अभी समय दिया जाएगा आप उसमें अपनी

सारी बातें कह लेना।

वित मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : उपाध्यक्ष महोदया, हमारे साथी श्री ओम प्रकाश जी जो लोहारू हल्के से विधायक हैं उनको शायद जानकारी नहीं मिल पाई इसलिए मैं उनको केवल जानकारी देना चाह रहा था कि पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी इनके विधान सभा क्षेत्र में गये थे और बहल में एक बहुत बड़ी विशाल जनसभा हुई थी उस जनसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी लोहारू हल्के के लिए 150 करोड़ रूपये की परियोजना मंजूर करके आये हैं। (शोर एवं व्यवधान) अगर कोई एक-आधी सड़क बननी बाकी रह गई हो तो आप उसके बारे में बाद में बता देना, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत बड़े दिल के आदमी है, वह काम भी करवा देंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने लोहारू की मौज कर दी है, इतनी तो आज से पहले कभी भी नहीं हो पाई थी।(शोर एवं व्यवधान) माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं की यहां का विधायक कौन सी पार्टी से संबंध रखता है। (शोर एवं व्यवधान) इन्होंने खुले दिल से लोहारू के लिए काम किया। यही भावना ''सबका साथ-सबका विकास'' की नीति की प्रमाणिकता को सही मायने में सिद्ध करती है। (शोर व व्यवधान)

श्री रणबीर गंगवा (नलवा): उपाध्यक्ष महोदया, सबका विकास कहा हो रहा है। सड़कों का बुरा हाल है, लोगों को रोजगार तक उपलब्ध नहीं है, इस तरह की अवस्था में ''सबका साथ-सबका विकास'' की नीति की प्रमाणिकता पर संदेह ही उत्पन्न होता है। (विघ्न)

उपाध्यक्ष महोदया: गंगवा जी, श्री वेद नारंग जी अपनी बात रखना चाहते हैं, उन्हें अपनी बात रखने दें। आप प्लीज बैठिए।

श्री वेद नारंग (बरवाला): उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जो आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान बोलने का मौका दिया। आज हरियाणा के जो हालात हैं वह किसी से छिपे हुए नहीं है। हरियाणा में यह जो बुरा दौर निकला है इसकी जितनी भी निन्दा की जाये वह कम है। आज जो किसानों की समस्या है वह सबके सामने है। आज किसानों के हालात तथा आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि न तो किसानों की फसलों को कोई उचित भाव मिलता है, न ही उनके पास सिंचाई के पर्याप्त साधन मौजूद हैं। सरकार ने टेल तक पानी पहुंचाने का वायदा किया था लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं दिखाई दे रहे हैं। हमारे यहां बरवाला में तो पानी का इतना बुरा हाल है कि नहरों में पर्याप्त पानी तक उपलब्ध नहीं है तथा टेल तक पानी नहीं पहुंच पाता है। जहां तक बिजली का संबंध है, हरियाणा सरकार ने बिजली के रेट इतने बढ़ा दिये हैं कि आज हरियाणा प्रदेश में बिजली के रेट सभी अन्य प्रदेशों की तुलना में सबसे अधिक हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि बिजली के रेटों की समीक्षा की जाये। इस संबंध में इडियन नैशनल लोकदल पार्टी के सदस्यों का एक दल चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिला था लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। बिजली के रेट बढ़ने से उपभोक्ताओं पर बहुत ज्यादा मार पड़ी है। व्यापारियों के हालात भी बहुत खराब है। औद्योगिक इकाईयों को बिजली के लिए 160 रूपये प्रति किलोवॉट फिक्स रेट देना पड़ता है। आज उद्योग बंद होने के कगार पर हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इसका उचित समाधान किया जाए। इसके अतिरिक्त जो अभी पिछले दिनों परिवहन नीति में बदलाव किया गया है उसकी वजह से लगभग 9000 परिवार जो लगभग पिछले 20 सालों से इस

[श्री वेद नारंग]

परिवहन समितियों की बसों से प्राप्त आजीविका पर निर्भर करते थे, इस बदली हुई नीति के फलस्वरूप उनके हितों पर भी कुठाराघात हुआ है। आज इस परिवहन नीति की समीक्षा करने की आवश्यकता है। बरवाला विधान सभा क्षेत्र का बिल गेट एरिया और बरवाला शहर में सफाई व सीवरेज व्यवस्था के हालात काफी दयनीय है। पानी की निकासी का प्रबन्ध न होने की वजह से गन्दा पानी लोगों के घरों में घुस जाता है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि इस समस्या का जल्द से जल्द निवारण किया जाये। बरवाला से हिसार तक शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमारी बेटियों को जाना पड़ता है लेकिन इन बेटियों के लिए परिवहन की कोई अलग से व्यवस्था नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि लड़कियों के लिए एक परिवहन बस सेवा बरवाला से हिसार तक शुरू की जाये। बरवाला शहर के अनाज मंडी में स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में साईंस व कामर्स के लिए पर्याप्त स्टॉफ नहीं है जिसके कारण बच्चों को मजबूरन प्राईवेट एकेडमी में जाना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त यहां पर बच्चों के लिए न ही किसी पुस्तकालय का प्रबन्ध है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि इस समस्या की तरफ ध्यान देकर तुरन्त समाधान किया जाये। इसके अतिरिक्त बरवाला विधान सभा क्षेत्र की टूटी-फूटी सड़कों का भी जल्द से जल्द निर्माण-कार्य शुरू करवाया जाये। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन हैं कि मेरे बरवाला विधान क्षेत्र की समस्याओं को जल्द से जल्द सुलझाया जाये। धन्यवाद

श्री मूल चन्द शर्मा (बल्लभगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज हरियाणा प्रदेश में 'सबका साथ-सबका विकास' अवधारणा पर काम किया जा रहा है। आज प्रदेश का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां समान रूप से विकास न किया जा रहा हो। चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो अथवा नौकरी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में विकास की नदियां बह रही हैं। मैं इस महान सदन का सदस्य तो पहली बार बना हूँ लेकिन मैंने अपने जिन्दगी के 28 वर्ष राजनीतिक क्षेत्र में बिताये हैं। मैंने देखा है विपक्ष का कोई एम.एल.ए. अपने काम करवाने के लिए कभी सत्ता पक्ष के नेता अर्थात मुख्यमंत्री के दरवाजे पर नहीं जाता था। आदर और सम्मान के पात्र श्री मनोहर लाल जी प्रदेश के पहले ऐसे संत और सच्चे मुख्यमंत्री है जो सद्भावना से काम करते हैं और किसी के साथ कोई मतभेद नहीं रखते हैं। यदि विपक्ष का विधायक भी इनके पास जाकर कह देता है कि यह मेरी सड़क बनानी है या कोई ट्रांसफर करवानी है तो उस कार्य पर तुरन्त एक्शन ले लिया जाता है। मैंने वह समय देखा है कि विपक्ष के किसी एम.एल.ए. की मुख्यमंत्री के सामने निकलने तक की हिम्मत नहीं होती थी। इस प्रकार के तानाशाही मुख्यमंत्री इस प्रदेश में रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने विधानसभा के हर क्षेत्र में चाहे वह विपक्ष के साथियों का क्षेत्र रहा हो, उनमें जाकर अपने मुखारबिन्द से बिजली, सड़क, पानी आदि विकास के कार्यों के लिए दो सौ से लेकर अढ़ाई सौ करोड़ रूपये तक की घोषणाएं की है। हरियाणा प्रदेश के कुरूक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था, इस प्रकार से यह प्रदेश कवियों और ऋषियों का रहा है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही हरियाणा प्रदेश के किसानों के नाम से हमदर्दी लेती रही है कि हम किसानों के हितों के लिए पानी लेकर आयेंगे, किसानों को फसलों का उचित मुआवजा देंगे। उपाध्यक्ष महोदया, हमारी सरकार ने पिछले साल ओलावृष्टि से खराब हुई गेहूँ की फसल के लिए लगभग 1100 करोड़ रुपये और सफेद मक्खी के प्रकोप से हुई कपास की फसल के लिए सिर्फ 5 जिलों में 967 करोड़

रूपये मुआवजे के तौर पर किसानों को दिए हैं। किसी भी सरकार ने इतना मुआवजा आज तक नहीं दिया जितना कि इस सरकार ने किसानों को दिया है। हमने 20-20 रूपये के चैक मुआवजे के तौर पर देते हुए देखें हैं और इस प्रकार से किसानों का शोषण किया जाता था । किसानों की बड़ी-बड़ी बातें करनी वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किसानों की बेशकीमती जमीन दो या अढ़ाई करोड़ रूपये की मात्र 16 लाख रुपये में खरीदी थी। इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने प्रॉपर्टी डीलर का काम करके प्रदेश के अंदर लूट मचा रखी थी। जब से माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने प्रदेश की बागडोर संभाली है तब से मेरे जिला फरीदाबाद और जिला पलवल के किसानों को 200 करोड़ रुपये मुआवजे के दिये हैं इससे पहले इतना मुआवजा किसी भी सरकार ने किसानों को नहीं दिया। श्री केहर सिंह जी भी इस बात के साक्षी हैं। इस सरकार ने किसान, मजदूर और व्यापारी सभी लोगों के लिए विकास के काम किए हैं। कांग्रेस पार्टी की सोच थी कि पढ़ी लिखी पंचायत नहीं आनी चाहिए क्योंकि पढ़ी लिखी पंचायत आने से कांग्रेस पार्टी ने जो प्रदेश के अंदर लूट मचा रखी थी वो बंद हो जायेगी। इस बार हरियाणा के पंचायत के चुनावों में जनरल कैटेगरी में पढ़े-लिखे लोगों की भागीदारी 33 प्रतिशत की जगह 42 प्रतिशत हुई और अनुसूचित जातियों में 20 प्रतिशत की जगह 25 प्रतिशत की हिस्सेदारी हुई है। हमारे प्रदेश में चारो तरफ सड़कों का जाल बिछा हुआ है। सरकार के डेढ़ साल के कार्यकाल के अंदर ही मेरे फरीदाबाद जिले में आठ लेन के 6 नैशनल फ्लाई ऑवर मात्र 3 महीने के बाद शुरू हो जायेंगे। लोग 6-6 साल से तरसते थे कि कब ये फ्लाई ऑवर तैयार होंगे? कब हम मथुरा और आगरा जा पायेंगे? उपाध्यक्ष महोदया, इस तरह के विकास की कल्पना हमने अपने जीवन में कभी भी नहीं देखी थी। फरीदाबाद सोने की चिड़िया कहा जाता था जो एशिया के मानचित्र पर छाया रहता था। उपाध्यक्ष महोदया, पिछली सरकार के दौरान फरीदाबाद की औद्योगिक नगरी के क्षेत्र में एक-एक उद्योग जैसे मैटल बॉक्स, आयशर जैसे उद्योगों को चुन-चुन कर बंद किया जाता था। प्रदेश का मुख्यमंत्री प्रदेश में विकास करने का काम करता है ना कि प्रदेश को उजाड़ने का। फरीदाबाद में सूई से लेकर जहाज तक के पार्ट बनने के उद्योग लगे हुए थे। फरीदाबाद को कई नेताओं ने उद्योग के मामलों में पीछे करने का प्रयास किया था। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन में एक बात और अवश्य कहूँगा कि फरीदाबाद दिल्ली से लगता हुआ क्षेत्र है, इसलिए इसे उद्योग के क्षेत्र में पीछे नहीं रहने देंगे। माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में फरीदाबाद स्वयं पृथला और आई.एम.टी. आदि उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है। उपाध्यक्ष महोदया, फरीदाबाद का एक हिस्सा उत्तर प्रदेश और दूसरा हिस्सा दिल्ली से लगता है। मेरे एक माननीय साथी अभी कह रहे थे कि रोहतक और झज्जर में बहुत विकास हुआ है और हरियाणा में यह क्षेत्र पहले नंबर पर पहुंच गया है। उपाध्यक्ष जी, बहादुरगढ़ में विकास का कोई काम नहीं हुआ है। पिछली सरकार के समय पूरे प्रदेश में सिर्फ एक ही बात सुनने को मिलती थी कि रोहतक वासियों की नौकरी लगेगी और रोहतक में ही सड़क बनेंगी, रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। हमारा क्षेत्र तीनों तरफ से घिरा हुआ है। एक तरफ से हमारा क्षेत्र उत्तर प्रदेश, दूसरी तरफ से ग्रेटर फरीदाबाद और तीसरी तरफ से दिल्ली से घिरा हुआ है। हमारे क्षेत्र के दो बड़े रास्ते बंद हैं जो एन.सी.आर. से लगते हैं। अगर नोएडा से मिलाने वाला रास्ता शुरू हो जाए और दो फ्लाइओवर्स बना दिये तो हमारे फरीदाबाद के विकास को पर लग जाएंगे। हमारा एक रोड़ दिल्ली-कालिंदी से हमारे फरीदाबाद तक और आगरा रोड़ के साथ-साथ हमारी एक सड़क बन जाए और हाइवे नंबर दो पर जाम नहीं रहेगा तो हमारा क्षेत्र विकास की ओर अग्रसर हो

[श्री मूल चन्द शर्मा]
जाएगा। हमारे क्षेत्र की बहुत बड़ी समस्या कैंसर की बीमारी है। बल्लभगढ़ से आगरा कैनाल और गुड़गांव कैनाल बहती हैं जिनका पानी इतना प्रदूषित है कि अगर उसे कोई चिड़िया भी पी ले तो वह कुछ सैकेंड्स में ही मर जाएगी और अगर कोई आदमी उसमें गिर जाए तो वह भी कुछ ही सैकेंड्स में मर जाएगा। हमें दिल्ली के गटर का पानी दिया जाता है। हरियाणा प्रदेश में जब पानी का बंटवारा हुआ था तो हमें यमुना नदी का पानी मिलना तय हुआ था परंतु हमें गटर का पानी दिया जा रहा है। मेवात का ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पर कैंसर का मरीज न हो। वहां के खेतों में सब्जियों पर कैंसर के कीटाणु हैं और पशुओं के दूध में कैंसर के कीटाणु हैं। इतनी खराब हालत हमारे जिले की हो चुकी है। हम इतने खराब पानी को पीने के लिए मजबूर हैं। जो पानी हमें मिल रहा है वह पीना तो दूर खेतों में प्रयोग करने लायक भी नहीं है। हमारे क्षेत्र का सारा पानी खारा हो चुका है। हमारी मांग है कि यमुना पर बड़े-बड़े डैम बनाए जाएं जिससे दिल्ली, नोएडा और फरीदाबाद को भरपूर पानी मिल सके। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का मेरे विधान सभा क्षेत्र बल्लभगढ़ में विकास कार्य करवाने के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। मुख्यमंत्री जी ने मेरे क्षेत्र में सड़कों के निर्माण के लिए 133 करोड़ रूपये प्रदान किये हैं। हमें कभी उम्मीद नहीं थी कि हमारे क्षेत्र में ऐसी-ऐसी सड़के बन जाएंगी। मेरे क्षेत्र में 10-10 किलोमीटर और15-15 किलोमीटर लम्बी आर.सी.सी. की डेढ़ फुट मोटी सड़कें बन रही हैं। मुझे विश्वास है कि हम जब भी विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री जी से पैसा मांगेंगे तो वे हमारी मांग अवश्य पूरी करेंगे। अगर हमें नोएडा से जोड़ने के लिए दो फलाईओवर्स मिल जाए तो हमारा फरीदाबाद इतना विकास करेगा कि गुड़गांव को भी पीछे छोड़ देगा। उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जय हिन्द।

श्री ओम प्रकाश बड़वा (लोहारू) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। (विघ्न)

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : उपाध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि वे अपना भाषण इस शेर को सुनाकर शुरू करें -

"मैं कहना चाहूंगा कि आदमी को आदमी से डर लगता है।"

श्री ओम प्रकाश बड़वा : उपाध्यक्षा महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि यह शेर तो मैं पहले भी सुना चुका हूँ । आज मैं सदन को एक नया शेर सुनाना चाहता हूं कि

"हजारों खुशियां कम हैं एक गम को भुलाने के लिए,
एक गम ज्यादा है जिंदगी भर रूलाने के लिए।"

मैं आपको एक शेर और सुनाता हूं -

"न हिन्दू बुरा है, न मुसलमान बुरा है,
न गीता बुरी है, न कुरान बुरा है,
न ग्रंथ बुरा है, न बाईबल बुरा है,
न हरिजन बुरा है, न गिरीजन बुरा है,
बुराई है जिस इंसान में वह इंसान बुरा है।"

उपाध्यक्ष महोदया, मेरा विधान सभा क्षेत्र लोहारू एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें पिछले दस

साल में कांग्रेस पार्टी ने कभी विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। यह क्षेत्र राजस्थान के साथ सटा हुआ रेतीला इलाका है। मेरे क्षेत्र में पिछले दस साल में विकास के नाम पर एक भी ईंट नहीं लगी है। मुख्य मंत्री जी ने मेरे क्षेत्र में एक जनसभा की थी। इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूं। मेरे हल्के लोहारू की ज्यादातर रोड्स टूटी पड़ी हैं। इन रोड्स की तरफ आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। इनमें से सबसे पहले मैं जिस रोड का जिक्र करूंगा वह मेरे गांव शिवानी की है। नैशनल हाइवे नं. 65 जो नलवा हल्के के विधायक रणबीर सिंह गंगवा जी के गांव से भी गुजरता है। इस समस्या को रखते हुए मुझे एक साल से ज्यादा समय हो चुका है। वहां इतनी दर्दनाक घटना हुई जिसका मैं यहां जिक्र नहीं कर सकता। एक भाई अपनी पत्नी को मोटरसाईकिल पर ले जा रहा था तो उसकी मोटरसाईकिल एक खड्डे में उछली और वह लेडी डम्पर के टायर के नीचे आ गई और उसकी तुरंत मौत हो गई। इस हादसे में केवल उस अकेली लेडी की मौत नहीं हुई बल्कि दो की मौत हुई क्योंकि उस लेडी के पेट में बच्चा था। मुख्यमंत्री जी, इस सड़क की जांच करवाएं कि क्यों नहीं एक साल से इस तरफ ध्यान दिया गया।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): ओम प्रकाश जी, नैशनल हाइवे नं. 65 के निर्माण का जो काम है वह नैशनल हाइवे अथोरिटी आफ इंडिया ने शुरू कर रखा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह काम प्रदेश सरकार का नहीं है। नैशनल हाइवे की सारी सड़कों के काम चल रहे हैं और मेरी केन्द्र सरकार के मंत्री से हर समय एक एक सड़क की बात होती रहती है और हमें जो जो कठिनाई होती है हम उसको दूर करने की बात उनसे करते रहते हैं ।

श्री परमिन्दर सिंह ढुल: उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को कहना चाहूंगा कि नैशनल हाइवे अथोरिटी आफ इंडिया पर दबाव जरूर बनाया जाए ताकि नैशनल हाइवे की सड़कें जल्दी बनाई जाएं। हमारे यहां जींद में भी नैशनल हाइवे की सड़क का काम डेढ़ साल से बन्द पड़ा हुआ है।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु): उपाध्यक्ष महोदया, मुख्यमंत्री महोदय जी ने बताया है कि नैशनल हाइवे अथोरिटी आफ इंडिया इन सड़कों को बना रही है और उनके काम चल रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री महोदय ने हरियाणा के नैशनल हाइवे के रोड्स की समीक्षा करते हुए जहां रिपेयर की आवश्यकता थी, और जहां नैशनल हाइवे अथोरिटी आफ इंडिया की प्रक्रिया में देरी हो रही थी, वहां हरियाणा सरकार की तरफ से पैसा दिया गया है। जैसे पेहवा, अम्बाला और कैथल हाइवे पर 19-20 करोड़ रूपये हरियाणा सरकार की तरफ से दिए गए हैं। फिर भी ऐसी कोई आवश्यकता होगी तो हम इस बारे में जरूर विचार करेंगे क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने इस मामले में हमेशा दरियादिली दिखाई है। नैशनल हाइवे नं. 65 पर बाई पास बन रहा है लेकिन यदि आपका रोड अंदर का है तो उसको बनाने का काम पी.डब्ल्यू.डी. का है।

श्री ओम प्रकाश बड़वा: उपाध्यक्ष महोदया, नैशनल हाइवे नं. 65 पर जो बरवा और शिवानी में बाई पास बन रहा है, उसके अंदर का रोड पी.डब्ल्यू डी के अंडर में है या नैशनल हाइवे के अंडर में है यह देखना सरकार का काम है।

श्री मनोहर लाल: ओम प्रकाश जी, बाई पास नैशनल हाइवे का है और अंदर का रोड पी.डब्ल्यू. डी. का है ।

श्री ओम प्रकाश बड़वा: उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमारा

अंदर का रोड खराब है। लोहारू की कुछ समस्याओं का मैं यहां जरूर जिक्र करना चाहूंगा। हमारी जितनी भी नहरें, डिस्ट्रीब्यूट्रीज या सबमाइनर्ज हैं वे सब टूटी पड़ी हैं तथा गाद से भरी हुई हैं और वहां झाड़ उगा हुआ है। उसमें शिवानी कैनाल, इसरवाल डिस्ट्रीब्यूट्री, मिट्ठी माइनर, शोरा माइनर, झुमका, दमकोरा और लोहारू डिस्ट्रीब्यूट्रीज ऐसी हैं जिनको मरम्मत की और सफाई की जरूरत है। दूसरी समस्या यह है कि बिजली की जो तारें हैं वे बहुत ढीली हैं जिसकी वजह से आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। यहां ऊंची नीची जमीन होने के कारण किसान जब रात को फव्वारा सैट से सिंचाई करता है तो गलती से भी पाइप ऊपर हो जाती है तो बहुत सी दुर्घटनाएं हुई भी हैं और दुर्घटनाएं होने का अंदेशा भी बना रहता है। खेतों की ढाणियों में लाइट की समस्या का भी हल किया जाए। आवारा पशुओं की समस्या पूरे हरियाणा की है इसको भी दूर किया जाना चाहिए। पीने के पानी की भी हमारे यहां समस्या है। लोहारू में ज्यादातर हल्कों में टयूबवैल का पानी आता है जोकि पीने के लायक नहीं होता है इसलिए नहरी पानी की व्यवस्था पीने के लिए की जाए तो बहुत अच्छा होगा। आज पानी की वजह से कैंसर और हार्ट अटैक की बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं इसलिए उसमें सुधार होना जरूरी है। मंत्री महोदय राम विलास शर्मा जी हमारे साथ लगते हल्के के हैं। लोहारू से महेन्द्रगढ़ की सीमा तक की रोड की जो हालत है उसका इनको पता है कि वहां से किसी व्हीकल का निकलना आसान बात नहीं है। इसके अलावा जिगनाऊ से बारवास, जिगनाऊ से गोढड़ा पोटिया, पहाड़ी से बरालू, लोहारू से फर्टियाभीमा, शेर से ढाणी लालपुर और बुढेडा से ढिगावा तक सड़कों की भी हालत बहुत खराब हैं जिनकी रिपेयर करवाना बहुत जरूरी है। इसके अतिरिक्त मेरे हल्के में कुछ कच्चे रास्ते हैं जहां पर सड़क बनाना बहुत जरूरी है। ये रास्ते हैं नलौई से गुरेरा, बहल से ढ़ाणी केहरा और बिधवान से गुडा। उपाध्यक्ष महोदया, इस तरह मेरे हल्के में नहर से संबंधित, सड़क से संबंधित, पानी से संबंधित जो समस्याएं हैं उनका समाधान सरकार जल्द से जल्द करवाये। अंत में मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश में पिछले दिनों जो हालात और परिस्थितियां बनी जिनके बारे में मेरे से पहले बहुत से वक्ताओं ने विचार रखे हैं। इस बारे में मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि धरती पूत्र जननायक चौधरी देवी लाल के हरियाणा को खुशहाल बनाने तथा फलता फूलता देखने के लिए आज सबके सहयोग की जरूरत है ताकि इस तरह की घटनाएं भविष्य में न हों। इसमें सभी साथी सहयोग करें। धन्यवाद।

मुख्य संसदीय सचिव (डॉ. कमल गुप्ता) : उपाध्यक्ष महोदया, मैं सभी का वन्दन करता हूं और आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा करने का जो अवसर दिया उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मित्रो अभी थोड़ी देर पहले एक शब्द अजूबा आया था। कई मित्रो ने उस पर आब्जैक्शन किया था। मैं कहना चाहूंगा कि अजूबा तो वास्तव में हो गया है कि हरियाणा बनने के 50 साल बाद पहली बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और बनने के डेढ़ साल के अंदर सरकार ने वे कार्य कर दिखाये जो पिछले 50 साल में नहीं हुए। इसका पहला परिणाम यह है कि अभी जिला परिषदों, पंचायतों और ब्लोक समिति के चुनाव हुए। पहले कभी हमारी पार्टी को या हमारी पार्टी के लोगों को इन चुनाओं में बहुमत नहीं मिला। अब 100 प्रतिशत नहीं तो 90 प्रतिशत बहुमत इन चुनावों में हमारे लोगों को मिला है यानि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चेयरमैंन बने हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है । यह इस बात का परिणाम है कि डेढ़ साल के अंदर हमारी सरकार ने विकास कार्य किए हैं जिसके कारण गांव-गांव से लोग हमारी पार्टी से जुड़े हैं, क्या

यह अजूबा नहीं है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971 में किया था।1971 से लेकर 2014 तक केवल 2.75 करोड़ खाते पूरे हिंदुस्तान में खुले थे और केवल 2014 से लेकर अब तक 18 करोड़ खाते प्रधान मंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए हैं। यह भी एक अजूबा हुआ है। यह कोई कम बड़ी बात नहीं है। उसके बाद प्रधान मंत्री जी ने देश के किसान को, गरीब को 12 रूपये में जीवन सुरक्षा बीमा दिया है ताकि गरीब आदमी भी स्वाभिमान से जी सके। यदि कभी किसी गरीब की मृत्यु हो जाती है तो इस बीमे के माध्यम से उसके परिवार के सदस्यों को एक उचित राशि पालन पोषण के लिए मिल जायेगी। इससे पहले यदि किसी गरीब की मृत्यु हो जाती थी तो हमें मुख्यमंत्री या डी.सी. की तरफ राहत के लिए देखना पड़ता था कि मृतक के परिवार को कुछ राहत मिल जाये। उपाध्यक्ष महोदया, राहत कोई बढ़िया चीज नहीं होती। यह केवल मजबूरी में दी जाती है। राहत लेने के लिए हर आदमी खुश भी नहीं होता। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रधान मंत्री जी ने किसान और गरीबों जिनकी आयु 18 साल से 70 साल की है उनके लिए 12 रूपये में जीवन सुरक्षा बीमा दिया है। मैं अपने जीवन की एक घटना बताता हूं। हमारे किसी मित्र की मृत्यु हो गई थी। हम कुछ साथियों ने मिलकर उसकी पत्नी को राहत के तौर पर कुछ पैसे देने के लिए इकट्ठे किए लेकिन हमारी हिम्मत नहीं हुई कि उसकी पत्नी को पैसे कौन दे, कभी लेने से इनकार न कर दे। क्योंकि राहत बहुत से लोग लेने के लिए तैयार नहीं होते। हमारे प्रधान मंत्री जी ने जो जन धन बीमा योजना शुरू की है यह अपने आप में एक अजूबा से कम नहीं है। हमारे अलावा किसी भी देश के प्रधान मंत्री जी ने ऐसी जीवन बीमा योजना शुरू नहीं की है। सब लोगों को जॉब देना बहुत मुश्किल कार्य है। सरकार सब लोगों को जोब नहीं दे सकती। हमारी सरकार ने एक अनोखी योजना मुद्रण बैंकिंग योजना शुरू की है जिसमें तीन प्रकार के यानी शिशु, तरूण, किशोर लोन शुरू किए हैं। शिशु लोन की लिमिट 50 हज़ार रूपये तक है, तरूण लोन की लिमिट 50 हज़ार रूपये से 5 लाख रूपये तक और किशोर लोन के लिए 5 लाख रूपये से 10 लाख रूपये तक की लिमिट फिक्स है। इस प्रकार की ऐसी बहुत सी योजनायें हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने हिन्दूस्तान में पहली बार चलाया। ये सभी अपने आप में एक अजूबा हैं। आरक्षण के विषय पर यहां बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं हांसी में बैठा था और वहां पर दंगे फसाद हो रहे थे। वहां पर मेरे साथ डी.सी. साहब और एस.पी. साहब थे। उस समय हमने तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी को फोन किया और वास्तविक स्थिति से अवगत करवाया । हमारे फोन के डेढ़ घंटे बाद तीन हैलीकॉप्टर से सेना के 70 जवान एयर ड्राप हुए। ऐसा करके हमने हांसी और हिसार को बचाया। यह कितनी एफीशिएंशी की बात है इसका अंदाज़ा कोई भी लगा सकता है। यह कोई छोटी बात नहीं है। इतना बड़ा काम और इतने कम समय में हो जाये यह इससे पहले कभी किसी ने देखा नहीं होगा। ये सभी अपने आप में अजूबे हैं। मैं इसलिए यह कह रहा था कि पहली बार यहां पर सन् 1984 में झगड़े हुए। इसी प्रकार से यहां पर वर्ष 1990 में मण्डल कमीशन का जो कर्फ्यू लगा उसमें भी कई लोगों का झगड़ा हुआ। हमारी सरकार ने व्यापारी वर्ग और जिनका भी इस दंगे में नुक्सान हुआ उनको बिना किसी जाति या क्षेत्र के भेद से ऊपर उठते हुए एक महीने के अंदर-अंदर उचित मुआवज़ा देने की घोषणा हमारी सरकार द्वारा की गई है। हमारी सरकार ने मुआवज़ा की पहली किस्त जो कि 25 प्रतिशत थी उसको पहले सात दिन के अंदर-अंदर जारी भी कर दिया।

श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया : उपाध्यक्ष महोदया, मैं कमल जी को यह बताना चाहता हूं

कि जैसे कि ये कह रहे हैं हमने हांसी को बचा लिया मैं इनको यह कहना चाहता हूं कि इसके बावजूद भी ये हांसी को नहीं बचा पाये और वहां पर लोगों का काफी नुक्सान हुआ है।

डॉ. कमल गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदया, मैं श्री बलवान सिंह के ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा कि हमारे समय पर उठाये कदमों का ही यह नतीज़ा रहा कि हांसी में रोहतक और झज्जर के मुकाबले काफी कम नुक्सान हुआ। जो चीज़ बच जाती है उसका हमें अहसास ही नहीं होता। रात को दस बजे हमारे गुज्जर भाई की मृत्यु हुई । मैंने उसका संस्कार वहां जाकर करवाया। मैं यह बात इनको ऐसे समझाना चाहता हूं कि Good is not good when better is expected. (विघ्न)

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : उपाध्यक्ष महोदया, डॉ. साहब ने अपनी स्पीच में यह बात कही कि हमारे यहां पर 1984 में झगड़े हुए और इसी प्रकार से इन्होंने 1990 में भी झगड़े होने की बात कही है। मैं इनको यह बात बताना चाहता हूं वर्ष 1984 में कोई झगड़े नहीं हुए थे बल्कि वर्ष 1984 में तो दिल्ली और कानपुर सहित देश के विभिन्न हिस्सों में सिक्खों का एकतरफा कत्लेआम हुआ था लेकिन इसके बावजूद भी सिक्खों ने किसी को उंगली तक नहीं लगाई थी। इसलिए मैं इनको एक बार फिर कहना चाहता हूं कि उस घटना को ये झगड़े में काऊंट न करें बल्कि यह कहें कि उस समय सिक्खों का कत्लेआम हुआ था। उस समय पूरे हिन्दूस्तान में 5 से लेकर 6 हज़ार तक सिक्खों का कत्लेआम किया गया था।

डॉ. कमल गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदया, उस समय कुछ पर्टिकुलर लोगों का ही ज्यादा नुक्सान हुआ था यह बात मैं भी मानता हूं। इसलिए सरदार जसविन्द्र जी की यह बात पूरी तरह से सही है कि उस समय सिक्खों का ही नुक्सान हुआ था। इनकी यह बात मैं भी स्वीकार करता हूं। आपातकाल में 26.06.1975 से लेकर 21.03.1977 तक का समय काला अध्याय था अर्थात उस समय हिन्दूस्तान में एमरजैंसी लगी थी। उस एमरजैंसी में जिन लोगों ने बलिदान दिये वह किसी से छिपा नहीं है। उस समय राम बिलास जी को जेल में पता नहीं किस-किस प्रकार की यातनायें दी गई थी। यह सभी जानते हैं। उनके उस बलिदान को कौन भूल सकता है। इस प्रकार लोगों ने पता नहीं कितना बलिदान दिया। लोग जेलों में चले गये। लोगों को यह उम्मीद नहीं थी कि वे जेलों से कभी छूटेंगे भी या नहीं। मैं विपक्ष के माननीय साथियों से पूछना चाहता हूं कि ऐसे लोगों का मान-सम्मान किसने किया। पूरे 38 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों को मान और सम्मान दिया। यह कार्य भी किसी प्रकार के अजूबे से कम नहीं है। इस प्रकार से अनेक काम हरियाणा प्रदेश में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा किये गये हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी 29 दिसम्बर, 2015 को हिसार में गये थे। पहली बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख से हिसार के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात आई। आज हमारे हरियाणा प्रदेश को बने हुए पचास साल हो गये हैं और इसी प्रकारसे देश की आजादी को 68 साल हो गये हैं लेकिन इतने समय के बाद भी किसी ने भी हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की बात नहीं सोची। हमारी सरकार ने उसका सर्वे करवाया है। मेरी इस बात से सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी साथी सहमत होंगे कि हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए 4 हज़ार एकड़ ज़मीन उपलब्ध है। जो कहीं भी उपलब्ध नहीं है केवल हिसार में उपलब्ध है और उसको देखते हुये माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यहाँ पर इंटरनेशनल ऐयरपोर्ट बनेगा। उसकी चर्चा मुख्यमंत्री जी ने अमेरिका में भी की तथा प्रधानमंत्री जी की चण्डीगढ़ और सोनीपत में हुई रैलियों में भी इसकी घोषणा की थी।

केवल इंटरनेशनल ऐयरपोर्ट ही नहीं बनेगा बल्कि उसका रख-रखाव, डेंटिंग-पेंटिंग और रिपेयर का काम वहाँ पर शुरू हो जायेगा तथा जिस दिन वहाँ पर अमेरिका और जापान से हवाई जहाज उतरेंगे उस दिन की आप कल्पना करके देखिये। (विघ्न) आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने लेकर तो देखिये। आज तक किसने सपने लिये ? (विघ्न) जब सपने ही नहीं देखेंगे तो सपने साकार कैसे होंगे। पिछले 50 साल में जब कुछ नहीं हुआ तो डेढ़ साल में सबकुछ एक दम कैसे हो सकता है ? (शोर एवं व्यवधान)

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : उपाध्यक्ष महोदया, क्या यह सरकार मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही दिखायेगी या कुछ काम भी करके दिखायेगी?

डॉ. कमल गुप्ता : जसविन्द्र जी, आप भावना को समझिये, शब्दों पर ज्यादा ध्यान न दीजिए।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूँ कि :-

मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है,

पंखों से कुछ नहीं होता, हौंसलों से उड़ान होती है ।

डॉ. कमल गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदया, इसी प्रकार से यहाँ सदन में ओलावृष्टि की बात हुई थी। हमने कहा कि हमारी सरकार ने 1092 करोड़ रूपये का मुआवजा किसानों को दिया है। उसके बाद सफेद मक्खी के प्रकोप से किसानों की कपास की फसल बर्बाद हो गई थी उसके लिए भी हमारी सरकार ने 967 करोड़ रूपये का मुआवजा दिया है। किसी भाई ने यह कहा कि इससे पहले इतना नुकसान भी नहीं हुआ था। यह मजाक की बात नहीं है लेकिन इससे पहले 12000 रूपये प्रति एकड़ का मुआवजा कभी नहीं दिया गया। उससे पहले 6-7 हजार रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिलता था। इसी प्रकार से अगर वृद्धावस्था पैंशन की बात की जाये तो पहले 1000 रूपये पैंशन मिलती थी। हमारी सरकार ने 2000 रूपये मासिक पैंशन देने का वादा किया था और आज 1400 रूपये प्रति मास मिल रही है तथा 1-1-2019 को यह 2000 रूपये प्रति मास हो जायेगी जिसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी कर चुके हैं। मैं हिसार में इंटरनेशनल ऐयरपोर्ट की बात कर रहा था। जिस दिन हिसार में इंटरनेशनल ऐयरपोर्ट बन जायेगा उस दिन हिसार में 100 किलोमीटर के दायरे में कितने एक्सप्रैस-वे बन जायेंगे, कितनी इंडस्ट्रीज आ जायेगी, कितनी रेलें चल जायेंगी और कितना विकास हो जायेगा उसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते । इस डिवैल्पमैंट को आगे बढ़ाने के लिए एक तो परियोजना सैंक्शन भी हो चुकी है। रेलवे मंत्री ने रोहतक से महम होते हुये हांसी की रेलवे लाईन की जो बात की है उसके बारे में मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि उसके अवार्ड की घोषणा शीघ्र की जाये ताकि जल्दी से जल्दी उस पर काम शुरू हो सके।

कैप्टन अभिमन्यु : उपाध्यक्ष महोदया, मैं आरणीय कमल गुप्ता जी को बताना चाहूँगा कि रोहतक से महम होते हुये हांसी की रेलवे लाईन पर हरियाणा सरकार अपने हिस्से का साढ़े तीन सौ करोड़ रूपये जारी कर चुकी है।

[18.00 बजे] **डॉ. कमल गुप्ता** : उपाध्यक्ष महोदया, इसी तरह से गरीबों के रहने के लिए अफोरडेबल हाऊस बनाने के लिए भी बातें हुई हैं। इसी तरह से दिल्ली से बल्भगढ़ तक मैट्रो बनाने के लिए भी बात हुई है। हमारी सरकार पूरा ध्यान दे रही है। इसी तरह से सभी जिलों में जो डॉक्टर्ज की कमी है उसको पूरा करने के लिए सभी जिलों में मैडिकल कॉलेज खोलने की बात भी हमारी सरकार ने की है। जो आज तक किसी ने नहीं की और यह काम हमारी सरकार ने अपने कार्यकाल के डेढ़ वर्ष के अन्दर ही किया है। आज हमारा जो हैल्थ डिपार्टमैंट में चाईल्ड डैथरेट है वह अब काफी कम हो गया है क्योंकि वर्ष 2013 में यह प्रति हजार पर 41 था और वर्ष 2015 में यह 33 पर आ गया है। इस बारे में एक कालिंग अटैंशन मोशन भी आया था। उसमें भी यह बात कही गई थी कि जो एम.आर.आई., सिटी स्कैन और इस तरह की लेटेस्ट इन्वेस्टीगेशंज हैं वे सभी जिलों के अस्पतालों में लगने वाली हैं। हमारे आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने उनके वैक्सीनेशन की बात भी की थी कि पैंटावलैंट वैक्सीनेशन 6 सप्ताह 10 सप्ताह और 14 सप्ताह में लगाये जाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदया : डॉक्टर साहब, वाईंड अप कीजिए।

डॉ. कमल गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदया, हिसार में आवारा पशुओं की भी बड़ी समस्या है। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि 50 एकड़ की जमीन जो हमें मिल चुकी है वहां पर एक बड़ा गौअभ्यारण बनेगा उसके बनने के बाद हिसार शहर सबसे पहले पशु मुक्त होगा तो हिसार होगा जिसमें सारे आवारा पशु भेज दिये जाएंगे।

श्री ओम प्रकाश बरवा : डॉक्टर साहब, यह तो बता दो कि वह गौ अभ्यारण कब तक बन जाएगा? (विघ्न)

डॉ. कमल गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदया, डेढ़ साल में 50 एकड़ में बन सकता है क्या ? आज हम यह तो कहने वाले हो गये कि बनेगा। आज से पहले आपने क्या यह बात सुनी थी ? (विघ्न) यह आने वाले दो-तीन साल में बन जाएगा।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : उपाध्यक्ष महोदया, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सच्ची बात कही है उन्होंने झूठा वादा नहीं किया जो सच्ची बात है वही कही है ।

(इस समय श्री अध्यक्ष चेयर पर आसीन हुए)

डॉ. कमल गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं इनका धन्यवाद करता हूं कि इनको कोई बात तो पसंद आई। देखिए हिसार में देश की आजादी से आज तक कोई एस.टी.पी. प्लांट नहीं था और हिसार जैसे बड़े जिले में एस.टी.पी. न हो तो it is a criminal on the part of the Government पहली बार 9 एकड़ जमीन में 40 एम.एल.डी. का जो एस.टी.पी. है वह हिसार में बनने जा रहा है। जिसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। सकाडा का वाटर वर्क्स पिछले 6-7 महीने में लगभग 80 प्रतिशत बन गया है और 20 प्रतिशत रह गया है। यह तीसरा वाटर वर्क्स हिसार में बनने वाला है। इसके साथ मैं एक बधाई देना चाहता हूं कि हमारे देश को आजाद हुए 68 साल हो गये हैं लेकिन जो गुलामी की निशानियां थी वह आज भी हमारे अन्दर विद्यमान थी। अभी पिछले साल युनिवर्सिटी में दो कन्वॉकेशन हुई। हरियाणा एग्रीकल्वर युनिवर्सिटी और लाला लाजपत राय युनिवर्सिटी दोनों के वाईस चांसलरों ने जो यह गुलामी की निशानी थी कि

कालेगाउन पहनकर जो डिग्रियां लेते थे उस काले गाऊन का उन्होंने बहिष्कार किया और हिन्दुस्तानी ड्रैस में सभी बच्चों ने डिग्रियां ली जिसके लिए वह बधाई के पात्र है। हमारी तो आजादी हो गई और आजादी के बाद हमारी जो मानसिकता है उस पर से अपने को गुलामी हटानी पड़ेगी। मैं आप सब की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि वर्ष 1982 में मैंने अपनी एम.एस. की डिग्री धोती-कुर्ते में ली थी। अध्यक्ष महोदय, मैं दो बातें और सदन में बताना चाहता हूं कि पूरे देश के लिए बधाई के पात्र हैं। इसी तरह से इण्टरनेशनल सोलर एलायंस का हमारे देश में कहीं भी इण्टर नेशनल लेवल का हैड क्वार्टर नहीं था। आज पहली बार फिर मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा के गुड़गांव में उसको बनवाया है और जिसमें 122 देशों की भागीदारी हुई। जिसमें फ्रांस के राष्ट्रपति भी आए थे इस तरह से तो इण्टरनेशनल सोलर एलाइंस का हैड क्वार्टर है वह हिन्दुस्तान मे बना है और हिन्दुस्तान में भी हरियाणा के गुड़गांव में बना है जो बहुत बड़ी बात है। अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस में पहले हम अन्तर्राष्ट्रीय लेवल पर कहां खड़े थे लेकिन आज 21 जून को यू.एन.ओ. में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे संसार में अन्तर्राट्रीय योग दिवस मनवा कर पूरे देश में जो लोहा मनवाया इसकी कोई मिसाल नहीं है। इसके अतिरिक्त मैं मंडियों के बारे में भी कहना चहता हूं कि आज तक पूरे हरियाणा प्रदेश में बनाई गई नई सब्जी मंडियों तथा नई अनाज मंडियों का एक मुश्त में ट्रांसफर या शिफ्टिंग कभी नहीं हो पाई थी। पहली बार हिसार में सब्जी मंडी को नई सब्जी मंडी में एक दफा में ही शिफ्ट कर दिया गया है। अनेक बातें ओर हैं जिन्हें मैं सदन के समक्ष रखना चाहता हूँ लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय ने समय का बंधन लगा रखा है इसलिए मैं संक्षेप में माननीय मुख्यमंत्री जी को तथा सदन में उपस्थित सभी सदस्यों को बधाई देना चाहता हूँ कि आज एस.वाई.एल. नहर पर सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय स्टे के रूप में आया है और सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई है और जिस नहर की जमीन को पंजाब ने मिट्टी डालकर भरने की कोशिश की थी उस जमीन पर यथास्थित बनाए रखने के आदेश दिये गये हैं तथा सुप्रीम कोर्ट की इस संविधान पीठ ने केन्द्रीय गृह सचिव, पंजाब के मुख्य सचिव और डी.जी.पी. को नहर का रिसीवर नियुक्त किया है। हरियाणा प्रदेश अपने हितों के लिए लड़ाई लड़ रहा है। इस लड़ाई को सही मानते हुए ही सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई है। धन्यवाद।

श्री नगेन्द्र भड़ाना (फरीदाबाद एन.आई.टी.) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मैं सदन के समक्ष जो मेरे एन.आई.टी विधान सभा क्षेत्र के समक्ष समस्यायें अनुभव हो रही हैं उनको रखना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी की है। इंडस्ट्रियल टाउन होने की वजह से मेरी विधान सभा क्षेत्र का 80 प्रतिशत हिस्सा कॉलोनिज का है। इस क्षेत्र में अधिकतर मजदूर तबका रहता है। इन लोगों को तो न्यूनतम वेतन तक भी नहीं मिलता है। पानी की समस्या के कारण इन मजदूरों को पीने का पानी भी खरीदकर पीना पड़ रहा है। फरीदाबाद जिले में पानी रेनीवैल से प्राप्त होता है। यह रेनीवैल का प्लॉट यमुना नदी के किनारे लगाया गया है। मेरा विधान सभा क्षेत्र बिल्कुल आखिरी छौर पर पड़ता है। रेनीवैल प्लॉट से यह पानी पहले तिंगाव विधान सभा क्षेत्र, ओल्ड फरीदाबाद, बल्लबगढ़ तथा बड़खल होते हुए अंत में मेरे विधान सभा क्षेत्र में पहुंचता है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि अंतिम छौर में पड़ने वाले मेरे विधान सभा क्षेत्र में रेनीवैल प्लॉट से डॉयरेक्ट

[श्री नगेन्द्र भड़ाना]

लाईन दी जाये ताकि हमारे मजदूर तबके को पीने का मीठा पानी सुलभ हो सके। इसी के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यह भी अनुरोध करूंगा कि फरीदाबाद जिले में पानी का स्तर दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। बारिश के समय जब यमुना नदी में बाढ़ आती है तो वह पानी जल संरक्षण के अभाव में व्यर्थ ही बहकर समुंद्र में चला जाता है। आपसे अनुरोध है इस पानी के संरक्षण के लिए यमुना नदी के किनारे पर बड़े-बड़े डैम बनाये जाये ताकि यमुना नदी के पानी का संरक्षण हो सके और हमारे पूरे फरीदाबाद जिले को कम से कम पीने के लिए तो मीठा पानी मिल सके। इसके अतिरिक्त सीवरेज व पानी की निकासी न होने जैसी समस्यायें मेरे विधान सभा क्षेत्र में मौजूद हैं। आज भी कई ऐसी जगह हैं जहां बारिश का समय न होने के बावजूद भी हर समय पानी भरा रहता है। जवाहर कालोनी-साठ फीट रोड़ पर, सारन- तलाब रोड़ पर, डबवा-गाजीपुर रोड़ पर तथा शिव बाउंड्री के पास यह ऐसी जगह हैं जहां पर एक-एक फुट पानी भरा रहता है। इसके अतिरिक्त फरीदाबाद जिले में जो खनन कार्य काफी दिनों से बंद पड़े हुए हैं उनको चालू करवाया जाये। मांगर और कोट गांव के पास 600 हेक्टेयर ऐसी जमीन है जोकि अरावली वन क्षेत्र से बाहर आती है, मेरा निवेदन है कि मांगर और कोट गांव में खनन कार्य खोले जाये ताकि हमारे प्रदेश को राजस्व प्राप्त हो सके क्योंकि जो गाड़ियां दूसरे प्रदेशों से पत्थर लेकर आती हैं उसकी वजह से समय भी ज्यादा लगता है, डीजल भी ज्यादा लगता है, रोज दुर्घटनायें होती हैं। अगर यहीं पर खनन कार्य खुल जाता है तो नि:संदेह फरीदाबाद जिले के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और अच्छी गुणवत्ता का माल भी मिलेगा। इसके परिणाम स्वरूप ग्राहकों को भी सस्ती दरों पर अच्छा मैटीरियल प्राप्त होगा। इसी के साथ-साथ मेरे फरीदाबाद एन.आई.टी. विधानसभा क्षेत्र के डबवा पाली रोड़ पर हजारों लोगों के गुजरने के बावजूद भी इसकी हालत बहुत दयनीय है । माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय मुख्य संसदीय सचिव श्रीमती सीमा त्रीखा की जनसभा में इस रोड़ को बनवाने के लिए 5 करोड़ रूपेय की घोषणा की थी। यह रोड़ काफी बड़ा होने के कारण नगर निगम, फरीदाबाद ने उस रोड़ के बीच में डिवाईडर डालकर सीवरेज और दोनों तरफ लाईटिंग की व्यवस्था करके डबवा गांव से पाली गांव तक, पाली गांव से गाजीपुर गांव तक और गाजीपुर गांव से नंगला गांव तक एस्टीमेट 27-28 करोड़ रुपये का बनाया था। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूँगा कि इस रोड़ के बनने से फरीदाबाद एन.आई.टी. और बड़खल विधानसभा क्षेत्र के हजारों लोगों की समस्या हल हो सकती है। मेरे फरीदाबाद एन.आई.टी. विधानसभा क्षेत्र के गोच्छी ड्रेन के दोनों तरफ लाईटिंग की व्यवस्था करके आर.एम.सी. की सड़क बनवाई जाये, इससे भी फरीदाबाद एन.आई.टी., बल्लभगढ़ और बड़खल विधानसभा क्षेत्र के लोगों को फायदा मिलेगा क्योंकि यह सड़क हार्डवेयर चौंक से लेकर के सैक्टर-25, फरीदाबाद को जाने वाली मुख्य रोड़ से बाईपास होकर बल्लभगढ़ और सोहना जाने का काम करेगी। इस रोड़ के बनने से मेरे फरीदाबाद एन.आई.टी. विधानसभा क्षेत्र के डबवा और जवाहर कॉलोनी के हजारों लोगों को फायदा मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, बल्लभगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक जनसभा के दौरान बल्लभगढ़ रेलवे पुल को डबल करने की घोषणा की थी। अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि बल्लभगढ़ का जो रेलवे पुल है वहां से लेकर के खोली जमालपुर गांव तक वाया गोच्छी-पाली होते हुए क्योंकि यह मेरे विधानसभा क्षेत्र का आखिरी गांव है उसके बाद गुड़गांव शुरू हो जाता है, उस पर डिवाइडर लगाकर चार लेन बनाया जाये। इस रोड़ के बनने से मेरे फरीदाबाद

एन.आई.टी. विधानसभा क्षेत्र के लोगों को आने-जाने के लिए जो जाम की स्थिति से गुजरना पड़ता है, उससे निजात मिल सकेगी। अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में पाली गांव है। जब बारिश होती है तो पानी बहकर एक नाले में चला जाता है। यदि वहां पर जल संरक्षण करने के लिए एक पाली लेक का निर्माण किया जाये तो मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। बड़खल झील के लिए हमारी बहन श्रीमती सीमा त्रीखा हर सत्र में इसके रख-रखाव करने के लिए मांग करती आई है। बड़खल झील हमारे जिले की आन बान और शान है। इसलिए ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि यह झील हमेशा हरी-भरी रहे। फरीदाबाद में पिछले 20 सालों से चल रही मैटल बॉक्स, आयशर, इलैक्ट्रोनिक्स ईस्ट इण्डिया, कॉटन मिल्ज, साईकिल, विको इंजीरियरिंग आदि बड़ी कम्पनियां अपनी बेशकीमती जमीन आवासीय खंडों में बेचकर दूसरे प्रदेशों में सस्ती जमीनें लेकर वहां लगाने का काम कर रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यह निवेदन करता हूँ कि इन कम्पनियों को अपनी जमीन आवासीय खंडों में बेचने की परमिशन ना दी जाये बल्कि ऐसा प्रावधान करना चाहिए कि इण्डस्ट्री जमीन पर केवल इण्डस्ट्री ही लगे ताकि हजारों युवकों को बेरोजगार ना होना पड़े, उन्हें रोजगार मिलता रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी फरीदाबाद जिले को एक मदर यूनिट देने का काम करें। ताकि हमारे क्षेत्र के जो हजारों बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार मिल सके। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : भड़ाना जी, आप प्लीज वाइंड अप कर लीजिए।

श्री नगेन्द्र भड़ाना : अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री का हाल में हमारे प्रदेश में आरक्षण के नाम पर उपद्रव, अराजकता तथा लूटपाट पर नियंत्रण करने के लिए धन्यवाद करना चाहूंगा। आरक्षण की मांग करना प्रत्येक नागरिक का हक है लेकिन जिस तरीके से असामाजिक तत्वों ने प्रदेश को लाखों-करोड़ों रूपये का नुक्सान पहुंचाया और लोगों के आपसी भाईचारे को नुक्सान पहुंचाया उसकी मैं निंदा करता हूं। प्रदेश में जो सभी जातियों के लोग प्यार-मुहब्बत के साथ रहते थे उनके भाईचारे को तार-तार कर दिया गया है। इस उपद्रव से उनमें जो दूरियां बढ़ी हैं उनको दूर करने के लिए सरकार को प्रयास करने होंगे। हाल ही में हैपनिंग हरियाणा गलोबल समिट के जरिये हरियाणा सरकार ने लाखों-करोड़ों रूपये के निवेश के लिए हमारे प्रदेश में एम.ओ.यू. साइन करवाये हैं इसके लिए मैं प्रदेश सरकार को बधाई देता हूं।

श्री सुभाष बराला : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि अच्छी बात का तो सभी को स्वागत करना चाहिए । (विघ्न)

श्री नगेन्द्र भड़ाना : अध्यक्ष महोदय, हमारे हरियाणा प्रदेश के लिए सरकार ने एम.ओ.यू. साइन करवाए हैं। मेरी मांग है कि हमारे फरीदाबाद का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए और वहां पर नई इंडस्ट्रीज लगाई जाएं। इसी के साथ हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एस.वाई.एल. के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से स्टे लिया है। यह फैसला हरियाणा प्रदेश के किसानों के हितों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके लिए मैं प्रदेश सरकार को बधाई देता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से हरियाणा सरकार "सबका साथ सबका विकास" नारे के तहत काम कर रही है उसी तरह मेरे क्षेत्र का भी विशेष रूप से विकास कराया जाए। मैं इन शब्दों के साथ माननीय अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद करता हूं।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री नगेन्द्र भड़ाना ने अपने विधानसभा क्षेत्र की प्रत्येक समस्या को सदन में प्रस्तुत किया और सच को सच कहा है परंतु मैं देख रहा हूं कि माननीय सदस्य सरदार जसविन्द्र सिंह संधू, श्री जाकिर हुसैन, नसीम अहमद और श्री परमिन्द्र सिंह ढुल ... (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : राम बिलास शर्मा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि श्री जाकिर हुसैन मुझसे मिलकर सरकार के विकास कार्यों की तारीफ करते हैं। इन्होंने मुझे बताया कि इस सरकार के आने पर ही हमने अपने खेतों में नहर का पहली बार पानी दिया है इससे पहले इनके खेतों में कभी पानी नहीं आया था। (विघ्न)

श्री जाकिर हुसैन (नूंह): अध्यक्ष जी, मैंने ये बातें सिर्फ आपको अलग से नहीं कही हैं अपितु मैंने ये सब ऑन द फलोर ऑफ द हाउस स्वीकार की हैं। हमारे क्षेत्र की कोटला झील का एक्वीजिशन लैप्स होने वाला था उसको इस सरकार ने इकॉनोमिक स्टूमीलस पैकेज से पैसा दिया। यह रिकॉर्ड की बात है। कांग्रेस गवर्न्मैंट ने इसका सत्यानाश कर दिया था। मैंने हाउस में कल भी कहा था कि मैडिकल कॉलेज के इशू में कांग्रेस को क्यों बचाया जा रहा है। यह भी एक गड़बड़ है।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी कह रहे हैं कि हम सरकार की तारीफ नहीं करते। सरकार पूरे प्रदेश में समान विकास की बात करती है। जब मेरे क्षेत्र में विकास होगा तो मैं भी अवश्य सरकार की तारीफ करूंगा। (विघ्न)

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि ये सरकार के विकास कार्यों की ओर आंखे बंद किये हुए हैं । मैं माननीय सदस्य श्री नगेन्द्र भड़ाना और उनकी पार्टी के अन्य माननीय सदस्यों को उपद्रव के दौरान फरीदाबाद, मेवात और सिरसा आदि क्षेत्रों को शांत रखने और प्रशासन का सहयोग करने के लिए धन्यवाद करता हूं। (विघ्न)

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश में चाहे कहीं भी हिंसा और उपद्रव हुआ हो लेकिन मेवात शतप्रतिशत शांत रहा था। इस बात को सरकार ने अभी तक हाउस में नहीं बताया है। वहां पर 36 बिरादरी एक-साथ रहती हैं और उनमें इतना प्यार है कि वहां पर किसी की साईकिल भी नहीं रोकी गई।

श्री केहर सिंह (हथीन): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। होडल, पृथला, पलवल और पुन्हाना इन चारों हल्कों के किसानों की जीवन रेखा गुड़गांव और आगरा कैनाल हैं। आगरा कैनाल का बहुत लम्बे समय से विवाद चल रहा है और हमें उसमें से हमारे हिस्से का पानी नहीं मिल रहा है। मैंने पिछले सदन में भी यह बात उठाई थी कि पिछली सरकारों में सभी जगह के 14 करोड़ रूपये अबियाने के माफ हुए थे लेकिन उत्तर प्रदेश का मामला होने के कारण हमारे क्षेत्र की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सदन से अनुरोध है कि सरकार उस 14 करोड़ रूपये के अबियाना को वहन करे और माफ करे। सरकार ने वायदा किया था कि हर खेत और हर टेल तक पानी पहुंचाएंगे। आगरा कैनाल से निकलने वाली हथीन डिस्ट्रीब्यूट्री और उसकी सहयोगी नहरें जैसे बिछोर माइनर, कोट माइनर, गोरसर माइनर, नीमका माइनर, बंचारी माइनर, बोराका और सोनंद माइनर ऐसी

माइनर्स हैं जिनमें पिछले 12 सालों में टेल तक पानी नहीं पहुंचा है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध भी है और सुझाव भी है कि नहरों के अंतिम छोर तक पानी तब जाएगा जब पीछे की छोटी छोटी लिंक नहरों को बंद किया जाएगा। यदि ऐसा किया जाता है तो सरकार की वाहवाही होगी और पिछले 12 वर्षों से जो किसान प्यासे बैठे हैं उनको पानी मिल जाएगा। गुड़गांव कैनाल की भी यही स्थिति है। गुड़गांव से उटावड़ के लिए डिस्ट्रीब्यूट्री जाती है और उटावड़ मेवात का सबसे बड़ा गांव है। गुड़गांव कैनाल में वह डायरैक्ट नहीं पड़ती है। उसमें तीन पम्प हैं और उन पम्पों के माध्यम से पानी दिया जाता है लेकिन पिछले 12 सालों से एक ही पम्प चलाया जाता है जिसकी वजह से पिछले 12 सालों से उटावड़ गांव के आखिरी छोर तक नहर में पानी नहीं पहुंचा है। 1978 के बाद अब की बार इसकी थोड़ी रिपेयर हुई है लेकिन नए पम्प फिर भी नहीं लगाए गए और वे आज भी बंद पड़े हैं। अध्यक्ष महोदय, यही स्थिति धतीर डिस्ट्रीब्यूट्री की है। गुड़गांव कैनाल से दुवारू माइनर निकलती है जो जाकिर जी के हल्के के लिए भी जाती है। उसके हैड से 500 मीटर आगे चलकर उसे ड्रेन का रूप दे दिया गया है और टेल से 700 मीटर पहले उसे फिर दोबारा माइनर का रूप दे दिया गया है यानि बीच में जो किसान पड़ते हैं उनकी डेढ़ हजार एकड़ जमीन में पिछले 20-25 सालों से सेम की समस्या है। अगर इसको ड्रेन का रूप प्रदान कर दिया जाए तो उन किसानों की सेम की समस्या हल हो जाएगा और अगले किसानों को खेती के लिए पानी मुहैया हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार का यह 5वां सैशन चल रहा है और मैंने हर सैशन में आवाज उठाई है कि हमारे जीताखेली, कनोली, सारोली, मंडकोला, असवरपुर, नाटोल, रीवड़, नौरंगाबाद, मंडनाका, मट्ठेपुर, छांयसा, दुरेती, बीघावली और जलालपुर गांवों के साथ साथ 3 नए गांवों रीडंका, टहरमा और बड़ा में सेम की समस्या है। इतनी बड़ी सेम की समस्या पूरे हरियाणा में कहीं नहीं है। केवल मात्र उलेहटा हसनपुर ड्रेन खुदवा दी जाए, ड्रेन नं. 8 जो उजीना में डलती है उसको खुदवा दिया जाए, मंडनाका से एक नहर ड्रेन के माध्यम से खुदवा कर हथीन तक पहुंच जाए तो हमारे 6 गांवों की प्यासी धरती को पानी मिल जाएगा। सरकार द्वारा कहा गया था कि जिन गांवों में सेम की समस्या है उन गांवों की सूची हमें प्रदान की जाए, उसका सर्वे करवाया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, इसका सर्वे करवाया गया था और सर्वे की रिपोर्ट पिछले सैशन में पेश की गई थी लेकिन उसमें हमारे किसी गांव का नाम नहीं है। हमने लिखित में इरीगेशन मिनिस्टर को शिकायत की थी कि पिछली बार वायदा किया गया था कि हरियाणा में जितने गांवों में सेम की समस्या है वह या तो खत्म की जाएगी या जब तक सेम की समस्या खत्म नहीं होती है तब तक उन किसानों को मुआवजा दिया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, आज तक न तो वहां सेम की समस्या खत्म हुई है और न ही उन किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है। मेरी मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि इस सेम की समस्या को जल्द हल करने का कष्ट करें। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से हथीन क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या भी बहुत गंभीर है। हथीन क्षेत्र में एक महीने में किसानों को, गरीब को और मजदूर को करोड़ों रूपये का पानी खरीदना पड़ता है। मैंने वहां के जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से कई दफा इस बारे में बात की लेकिन उनके कान पर जूं नहीं रेंगती। जिन गांवों में पीने के पानी की समस्या है उनके नाम हैं कलवाका, जैदापुर, कानोली, नौरंगाबाद मंडोरी, गखौता, धामका, अहंरवा, दर्गापुर, गेलपुर, रतीपुर, कैराका, जोधपुर, टीकरी ब्राहमण, विनोदा गढ़ी, हुडीथल, स्वामीका, लखनाका, गुराकसर, खिलूका, मौहदमका, उटावड़, रनियाला खुर्द, मंगूरी, रूपनगर, नाटौली, आलीमेव, नांगल, अंधोप, आली ब्राहम्ण, नांगल जाट आदि। अध्यक्ष

[श्री केहर सिंह]

महोदय, ये 30 गांव हैं जहां प्रतिमाह एक करोड़ रूपये का पानी लोग खरीदते हैं और अपनी व अपने पशुओं की जान बचाते हैं। सदन के माध्यम से मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इन गांवों में पीने के पानी की सुविधा जल्द मुहैया करवाई जाए। ये सभी गांव माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी ने जो मेवात के लिए रैनीवैल स्कीम बनाई थी उसमें आते हैं लेकिन कांग्रेस के राज में रैनीवैल पर जो पैसा लगना चाहिए था वह पूरा वहां न लगाकर 186 करोड़ रूपये रोहतक में लगा दिए। नरवाना के विधायक रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने यह भेदभाव हमारे क्षेत्र की जनता के साथ किया क्योंकि वे उस समय जन स्वास्थ्य मंत्री थे। सदन के माध्यम से मेरी मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि इस घोटाले की पूरी जांच की जानी चाहिए क्योंकि वहां पर जो पाइप वगैरा खरीदी गई हैं उनमें बहुत गड़बड़ी हुई है। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि बेराजगार युवाओं को 9-9 हजार रूपये बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा लेकिन राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इसकी कहीं चर्चा नहीं की गई है। यह युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा है जबकि युवाओं ने ही भारतीय जनता पार्टी को देश और प्रदेश में सत्ता सौंपी है। मेरा अनुरोध है कि उनके सपनों पर सरकार पानी न फेरे। सरकार या तो उनको रोजगार दे या अपना किया हुआ वायदा पूरा करके उनको 9 हजार रूपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दे। अध्यक्ष महोदय, अब मैं बिजली की बात करना चाहूंगा कि बिजली के क्षेत्र में भी हथीन पिछड़ा हुआ है। पिछली सरकार के समय बहीन में 33 के.वी.ए. का सब स्टेशन लगाया गया था लेकिन जिस समय उसका उद्घाटन किया जा रहा था उसी समय बिजली नहीं थी। मेरी मुख्यमंत्री जी से मांग है कि बहीन के सब स्टेशन को 66 के.वी.ए. का किया जाये। वहां अब केवल 6 घंटे लोगों को बिजली मिलती है। इसी तरह से मेरे हल्के में उटावड़ा बहुत बड़ा गांव है जिसमें 10 हजार वोट हैं इसलिए वहां पर भी 33 के.वी.ए. का सब स्टेशन लगाया जाये। वहां पर 3-4 दिन में बिजली आती है उसको मलाई फीडर बोलते हैं। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मेरे गांव नांगल जाट में पी.एच.सी. है लेकिन वहां पर फार्मासिस्ट नहीं है इस वजह से वहां कोई दवाई नहीं मिलती। इसलिए मेरा निवेदन है कि वहां पर फार्मासिस्ट की पोस्ट दी जाए। इसी तरह से मण्डकौला गांव की पी.एच.सी. पिछले कई वर्षों से जर्जर हालत में है। वहां कोई भी हादसा हो सकता है उसको भी ठीक करवाया जाये। अध्यक्ष महोदय, हथीन विधान सभा क्षेत्र हरियाणा का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। हथीन कस्बे को छोड़कर कोई शहर इस हल्के में नहीं पड़ता। वहां पर पी.डब्ल्यू.डी. का मात्र एक रैस्ट हाऊस है जो जर्जर हालत में है और बंद पड़ा है। उसको भी ठीक करवाया जाये। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से हथीन कस्बे में तीन साल पहले सीवर लाईन डाली गई थी और आज तक सीवर लाइन खोदने से जो सड़कें खराब हुई थी उनका निर्माण नहीं किया गया है। मेरी मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि उन सड़कों का निर्माण तुरंत करवाया जाये ताकि वहां के निवासियों को परेशानी से निजात मिल सके। अध्यक्ष महोदय, जहां तक शिक्षा की बात है इस बारे में मैं मांग करूंगा कि मेरे हल्के का मण्डकौला गांव बहुत बड़ा गांव है वहां पर लड़कियों का सीनियर सैकेण्डरी स्कूल खोला जाए। इसी तरह से मानपुर गांव भी 14-15 हजार की आबादी का है वहां भी लड़कियों का सीनियर सैकेण्डरी स्कूल बनाया जाये। इसी तरह से फुलवाड़ी में भी सीनियर सैकेण्डरी स्कूल बनाया जाये। अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे क्षेत्र के भावनीखेड़ा गांव में विद्यालय की मांग करता हूं। यह बहुत बड़ा गांव हैं। यहां पर विद्यालय खोलने से आसपास के 10-12 गांवों को बहुत फायदा होगा। इसी तरह से हथीन में जो लड़कियों का कॉलेज बनाया है वह कस्बे से बाहर है जहां कोई भी

अपनी बच्चियों को पढ़ने के लिए नहीं भेजता। इसलिए मेरी मांग है कि हथीन में जहां सीनियर सैकेण्डरी स्कूल है वहां यह लड़कियों का कॉलेज बना दिया जाए और सीनियर सैकेण्डरी स्कूल को कॉलेज की जगह दे दी जाए । वहां पर 16 कमरे खाली पड़े हैं। वहां पर इसके अलावा भी बहुत सी ज़मीन अवेलेबल है। यह मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है। मेरी एक छोटी सी डिमाण्ड और है जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा था कि अगर आपके पास 6 करम के रास्ते हैं तो उनके बारे में उनको बताया जाये वे उसको पक्का बनवा देंगे। मेरा हल्का ऐसा हल्का है जिसकी सभी सरकारों में पूरी तरह से उपेक्षा हुई है। वहां पर मानपुर से कौंडल, नांगल जाट से पारसर, गहलव से कलसाड़ा, मटराका से जनासौली इत्यादि सड़कों को बना दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : केहर सिंह जी, इस बारे में तो माननीय मंत्री जी ने कहा था कि इन सड़कों का ब्यौरा आप माननीय मंत्री जी को दे दें और ये सारी की सारी सड़कें निर्धारित नार्म्ज पूरे करती होंगी तो इनका निर्माण करवा दिया जायेगा।

श्री केहर सिंह: स्पीकर सर, ये सारे रास्ते सभी नॉर्म्ज़ पूरे करते हैं। इसके साथ-साथ मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से एक मांग और है कि जो दो बार उनके मुखारबिंद से एक आवाज़ निकली कि उनकी सरकार द्वारा हर विधायक को उसके क्षेत्र के विकास के लिए 5-5 करोड़ रूपये की धनराशि दी जायेगी। हमने इस बारे में पूरी प्रपोज़ल भी बनाकर दी है । मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि पूरे हरियाणा प्रदेश को उनसे बहुत ज्यादा आशायें हैं इसलिए वे हरियाणा प्रदेश के सभी विधायकों को बिना किसी भेदभाव के 5-5 करोड़ रूपये की राशि उनके हल्कों के विकास के लिए जल्दी से जल्दी उपलब्ध करवायें। वे पूरे हरियाणा प्रदेश के रक्षक हैं। उनसे मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि प्रत्येक विधायक को 5-5 करोड़ रूपये की राशि जारी करने के लिए अपनी सरकार को आदेश जारी करें। स्पीकर सर, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सदन की बैठक कल दिनांक 18 मार्च, 2016 को प्रात: 10.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तत्पश्चात् सभा की कार्यवाही दिनांक 18 मार्च, 2016 को प्रात: 10.00 बजे तक के लिए *स्थगित हुई।)

54378—H.V.S.—H.G.P., Chd.